हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

13 मार्च, 2001 (द्वितीय बैठक)

खण्ड 1, अंक 8

अधिकृत विवरण

विषय सूची

मंगलवार, 13 मार्च, 2001

	पृष्ठ संख्या
वर्ष 2001-2002 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(8)1
वैयक्तिक स्पष्टीकरण —	(8)36
श्री मांगे राम गुप्ता एम०एल०ए० द्वारा	
वर्ष 2001-2002 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(8)37
बैठक का समय बढ़ाना	(8)53
वर्ष 2001-2002 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(8)54
वैयक्तिक स्पष्टीकरण —	(8)54
चौधरी जय प्रकाश एम०एल०ए० द्वारा	
वर्ष 2001-2002 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(8)57
बैठक का समय बढ़ाना	(8)59
वर्ष 2001-2002 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(8)60

मूल्य :

71 00

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 13 मार्च, 2001 (द्वितीय बैठक)

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में 14.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री सतबीर सिंह कादयान) ने अध्यक्षता की।

वर्ष 2001-2002 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्ष : अब श्री जीतेन्द्र मलिक जी बोलेंगे।

श्री जीतेन्द्र सिंह मलिक : स्पीकर साहब, मैं कल बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : इनके अलावा कांग्रेस का कोई और सदस्य सदन में नजर नहीं आ रहा है। कैप्टन अजय सिंह भी नहीं हैं, जय प्रकाश जी भी नहीं हैं, राव धर्म पाल भी नहीं हैं, श्री शादी लाल बत्तरा भी नहीं हैं, श्री बलबीर पाल शाह भी नहीं हैं, श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा भी नहीं हैं, श्री चन्द्र मोहन जी भी नहीं हैं और जाकिर हुसैन भी नहीं हैं।

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : स्पीकर साहब, इससे पता लगता है कि कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य बजट पर बोलने के बारे में कितने सीरियस हैं। वे बजट पर बोलने के बारे में सीरियस नहीं हैं। फिर कहते हैं कि उन्हें बोलने का मौका नहीं मिलता।

श्री अध्यक्ष : चौधरी बंसी लाल जी क्या आप बोलना चाहते हैं।

चौधरी बंसी लाल (भिवानी) : अध्यक्ष महोदय, मैं बोलना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी हाउस में जो बजट लाए हैं उसके बारे में मैं अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, अगर ये देखा जाए कि पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है तो यह मेरे पास बजट एट ए ग्लांस की बुक है। इसमें बताया गया है कि पब्लिक डैट से 35.28 परसैंट पैसा आता है जो लोन की रीपेमैंट पर जाता है वह 21.59 परसैंट और कर्जे के इंट्रस्ट की पेमैंट पर 13.82 परसैंट जाता है यह मिला कर 35.41 परसैंट हुआ। एक तरफ जितना कर्जा आता है दूसरी तरफ उतना ही पैसा चला जाता है। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1999-2000 में नान प्लान साइड में जो खर्चा हुआ वह 6179 करोड़ रुपए हुआ और वर्ष 2000-2001 में 6838 करोड़ रुपए हुआ और रिवाइज्ड बजट एस्टिमेटस 7400 करोड़ रुपये थे यानि इस साल में लगभग 20 परसैंट का इजाफा है पिछले साल के मुकाबले में। इस साल इन्होंने दिया है 8016 करोड़ रुपये यह तो मेरे ख्याल में इसमें कमी चली जाएगी। क्या इससे पहले साल के बजट में 20 परसैंट का इजाफा है? वित्त मंत्री जी इस बारे में अपने जवाब में बता दें। अध्यक्ष महोदय, 1999-2000 में प्लान एक्सपैंडीचर 1943.34 करोड़ रुपए हुआ और 2000-2001 में रिवाइज्ड एस्टिमेटस के हिसाब से 2095 करोड़ रुपये हुआ और ये अगले साल के लिए एस्टिमेट कर

[चौधरी बंसी लाल]
रहे हैं 2520.68 करोड़ रुपए यह तकरीबन 8 परसैंट का इजाफा हुआ ये कैसे कंटेन करेंगे इस बारे में वित्त मंत्री जी अपने जवाब में बता देंगे।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, चौधरी साहब दोबारा चैक कर लें कि इस साल के बजट में बजट एस्टिमेट 2520.68 करोड़ रुपए नहीं है।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2001-2002 के लिए आप बजट एस्टिमेट 2520.68 करोड़ रुपए कर रहे हैं।

प्रो० सम्पत सिंह : चौधरी साहब, आपको जो रिवाइज्ड प्लान दिया गया है उसको देखें?

चौधरी बंसी लाल : रिवाईज्ड बजट ऐस्टिमेट 2095 करोड़ का है।

प्रो० सम्पत सिंह : चौधरी साहब, आपको इस साल का भी प्लान दिया गया है और पिछले साल का भी बजट ऐस्टिमेटस दिया गया है और जो रिवाईज्ड इस्टिमेट है वह भी दिया है।

चौधरी बंसी लाल : सम्पत सिंह जी, आप अपनी बात में ये सारी बातें समझा देना। अध्यक्ष महोदय, जो बजट की मेजर एलोकेशन इन्होंने मेजर हैड्ज में की है उनके बारे में मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। सरकार ने इरीगेशन विभाग के लिए वर्ष 1998-99 में 601.96 करोड़ रुपये का खर्चा किया। 1999-2000 में 597.46 करोड़ रुपये खर्च हुआ और रिवाईज्ड ऐस्टिमेटस 621.33 करोड़ रुपये के रखे। सरकार का इस काम के लिये 2000-2001 का ऐस्टीमेट 731.97 करोड़ रुपये है। मैं जानना चाहूंगा कि यह साल खत्म होने में अब केवल 15 दिन ही रह गए हैं। क्या इन 15 अकाया दिनों में ये 621.33 करोड़ रुपये खर्च होंगे या इससे कम ज्यादा होंगे, वित्त मंत्री जी जवाब देते समय इस बात का जवाब दे दें।

अध्यक्ष महोदय, सरकार ने वर्ष 1998-99 में पावर पर 1265.60 करोड़ रुपया खर्च किया। वर्ष 1990-2000 में 859.61 करोड़ रुपया खर्च हुआ और वर्ष 2000-2001 के लिए 1019.71 करोड़ रुपये का संशोधित अनुमान रखा है। सरकार ने इस काम के लिए 2001-2002 के अनुमान में जो इसका बजट ऐस्टिमेटस है वह 1287.11 करोड़ रुपये है। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि इतने कम पैसे से ये कैसे पूरी बिजली दे पायेंगे। वित्तमंत्री जी इस बात को भी अपने जवाब में मुझे समझा दें।

अध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चर साईड में वर्ष 1998-99 में 472.09 करोड़ रुपये रखे व वर्ष 1999-2000 में 317.05 करोड़ रुपये रखे। इनका 2000-2001 का संशोधित अनुमान 772.92 करोड़ रुपये का है। सरकार का इस काम के लिए 2001-2002 का बजट ऐस्टिमेट 539.90 करोड़ रुपये का है। मैं जानना चाहूंगा कि इतने कम पैसे से ये कैसे हरियाणा के लोगों को पानी दे पायेंगे। ये चालू वर्ष में 772.90 करोड़ रुपये कैसे खर्च कर पायेंगे, इस बारे में भी वित्त मंत्री जी अपना जवाब दे दें क्योंकि चालू साल खत्म होने में केवल 15 दिन ही रह गये हैं।

अध्यक्ष महोदय, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमैंट के लिए सरकार ने वर्ष 1998-99 में 247.25 करोड़ रुपये खर्च किये। वर्ष 1999-2000 में 179.07 करोड़ रुपये खर्च किए। 2000-2001 में इन्होंने इस काम के लिए रिवाईज्ड ऐस्टिमेटस 172.03 करोड़ रुपये के रखे हैं। नैक्सट ईयर के लिए इन्होंने बजट में 194.28 करोड़ रुपये रखे हैं। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर

बोलते हुए मुख्य मंत्री जी ने जवाब में बताया कि जुलाई तक प्रदेश की सभी सड़कों की तारकोल से मुरम्मत कर दी जावेगी। मुझे तो नहीं लगता कि इतने कम पैसे से ये इस काम को पूरा कर पायेंगे। इस बारे में वित्त मंत्री जी बता दें।

अध्यक्ष महोदय, एक्साईज विभाग की जो रसीट्स हैं वर्ष 1999-2000 में 765.36 करोड़ रुपये था। रिवाईज्ड ऐस्टिमेट 840 करोड़ रुपये है। बजट ऐस्टिमेट में आपका 1033.50 करोड़ रुपये है। एक तरह से 10 परसैंट का इजाफा है। नैक्सट ईयर में इन्होंने एस्टिमेट लगाया है 924 करोड़ रुपये का। अब तो औक्शन भी शुरू हो चुकी है। मैं जानना चाहूंगा कि इन्होंने जो 10 परसैंट का इजाफा दिखाया है क्या उसको ये मेनटेन कर पायेंगे या नहीं, इस पर भी मंत्री जी रोशनी डाल दें। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुख्य मंत्री जी कई बातों का जवाब नहीं दे पाये थे। मैं सरकार के नोटिस में लाना चाहूंगा कि रिवाड़ी की जो लिफ्ट इरीगेशन स्कीम है उसका मैं पहले जिक्र नहीं कर पाया था, उसके लिए नैक्सट ईयर में कितने रुपये रखे गए हैं। इसी प्रकार से अम्बाला, कैथल, भिवानी की जो वाटर सप्लाई स्कीम शुरू हुई उस पर अगले साल में कितना पैसा खर्च करने का प्रोविजन रखा गया है, इस बारे में वित्त मंत्री जी बता दें।

अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर भाखड़ा मेन लाईन और नरवाना ब्रांच में पानी फुल रेस्टोर हुआ है या नहीं यह मैं जानना चाहता हूं। क्योंकि इस ब्रांच से हमें 1600 से 1800 क्यूसिक्स पानी कम मिल रहा है। अगर यह फुल रेस्टोर नहीं हुई है तो यह कब तक फुल रेस्टोर हो जावेगी। मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस काम के लिए सरकार ने कितना पैसा रखा है ताकि हमें पूरा पानी मिल सके। एक और ग्रामीण विकास समितियां बनाई गईं। अध्यक्ष महोदय, यह अन-कांस्टीच्यूशनल है। जिस कांस्टीच्यूशन के तहत हिन्दुस्तान की पार्लियामैंट और हरियाणा प्रदेश की असैम्बली बनी है उसी कांस्टीच्यूशन के तहत गांव में पंचायतें भी बनी हैं, क्या वजह है उन पंचायतों के ऊपर एक नई कमेटी बिठा दी। अगर सरकार उसका स्कोप बड़ा करना चाहती है उसको वाईड करना चाहती है तो बजाए इसके कि नई ग्रामीण समितियां बनाई जाएं उनका नाम ग्राम सभा रख दें। ग्राम सभा की साल में दो बार मीटिंग होनी चाहिए आप उसकी मीटिंग्ज साल में चार बार कर दें। मगर यह चीज जो की गई है यह ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, पावर के लिए मुख्य मंत्री जी ने कहा कि 500-500 मैगावाट के तीन और प्लांट लग जाएंगे यह बहुत अच्छी बात है मगर इनको चालू जल्दी से जल्दी करवा लें क्योंकि प्रदेश बिजली के बगैर तबाह हो रहा है। इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहूंगा कि बिजली की चोरी रोकने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है, यह बात भी सरकार को सदन में बतानी चाहिए। बिजली की चोरी एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। अगर यह बिजली की चोरी न हो तो बिजली के रेटस घटाए भी जा सकते हैं बशर्ते कि चोरी न हो। इत्तेफाक से चोरी बहुत ज्यादा है और यह जो लोग मीटर चैक करने जाते हैं तो कहीं किसी की सील तोड़ दी जाती है या जैसा हुआ कर दिया। गांव में किसी पंच या सरपंच अथवा गांव के नम्बरदार को साथ ले जा कर मीटर चैक कर लें कि किस का मीटर ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वे वहां जाएं चाय पीवें और चलते वक्त कहते हैं कि जरा मीटर भी चैक कर लो। अगर वह टूटा हुआ मिले तो लोग कहते हैं कि आ करके वे खुद तोड़ देते हैं। अध्यक्ष महोदय, एक जो पीने के पानी की तकलीफ है उसके बारे में मैं यह कहूंगा कि सैंट्रल हरियाणा और दक्षिणी हरियाणा में बहुत बड़ी तकलीफ है। आगे गर्मी आ रही है। इस गर्मी में तो शहरों में पानी के लिए रायट्स हो जाएंगे और लोगों को नलकों पर पानी नहीं मिलेगा। लोगों को पीने का पानी देने के लिए भाखड़ा का पानी डब्ल्यू०जे०सी० में डालना चाहिए ताकि लोगों को पीने का पानी मिल सके। अध्यक्ष महोदय, यह कई चीजें ऐसी हैं कि सरकार अगर थोड़े वक्त पर कदम उठा ले तो उससे भी

[चौधरी बंसी लाल]

काम चल जाएगा लेकिन वक्त पर कदम न उठाने से फर्क पड़ता है। हुडको से जो 321 करोड़ का लोन आ रहा है वह भी वित्त मंत्री जी बता दें कि कितने दिनों में आ जाएगा। अढ़ाई हजार करोड़ रुपये जो भारत सरकार ने डीजल पर टैक्स लगाकर इकट्ठे किए हैं उसमें हमारा कितना हिस्सा बना है, 30, 40 या 50 करोड़, वह कब तक आ जाएंगे और कब तक वह लगेगा। अध्यक्ष महोदय, जो नैशनल हाईवे भारत सरकार ने बनाए हैं उनकी वाईडनिंग, स्ट्रैंथनिंग कब तक करेंगे, उनका क्या प्रोग्राम है, क्या इस बारे में भारत सरकार से पूछा है। सरकार ऐसी कोई बात भारत सरकार से करने वाली है या कि नहीं ? अध्यक्ष महोदय, एक चीज मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कही थी कि कान्फैड के जो लोग हैं उनमें जिन लोगों की 20-20 साल की नौकरियां हो गयी हैं वे कहां जाएंगे। उन लोगों के पास अब कहीं और जाने की जगह नहीं रही है क्योंकि वे ओवर-ऐज हो चुके हैं। तो मैं कहता हूँ कि जहां गवर्नमैंट की कोई जगह निकले तो उस छोटी बड़ी जगहों पर उनको एडजस्ट कर दें ताकि उनके रिट्रैंचमैंट की नौबत न आए। स्कूलों के लिए कहा जाता है कि ग्रामीण पंचायतों को दिया जाएगा। उसके लिए मैंने पहले भी पूछा था और अब भी जानना चाहूंगा कि स्कूलों को अगर पंचायतों को देंगे तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा और वे कैसे चलेंगे ? अध्यक्ष महोदय, कांस्टेबल की भर्ती के लिए फार्म के लिए जो 500 रुपये की फीस रखी गई है वह बहुत ज्यादा है। आई०ए०एस० और आई०पी०एस० के लिए तो फीस 40-50 रुपये है और कांस्टेबल के लिए 500 रुपये की फीस रख दी है। एक गरीब आदमी 500 रुपये कहां से देगा ? रैस्ट हाउस को बेचने के लिए जो पॉलिसी है मैं चाहूंगा कि सरकार उस को रिकंसीडर करे। रैस्ट हाउसिज को बेचने की कोई आवश्यकता नहीं है। पंजाब के गवर्नर महोदय ने अपने एड्रैस में यह कहा है कि चण्डीगढ़ पंजाब को मिलना चाहिए। मैं समझता हूँ हम सब पार्टियों ने इकट्ठे मिल कर एक फैसला किया था कि हमें शाह कमीशन की रिपोर्ट लागू कराने का प्रयास करना चाहिए और उसी की डिमांड हम को करनी चाहिए। आज हम इस बारे में कहां पर खड़े हैं इस बारे भी रोशनी डाल दें। (विघ्न)

अध्यक्ष महोदय, मैं अब किसानों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। किसानों की अब जो फसल पकेगी, पहले सरसों की फसल पकेगी, सरसों की फसल के बाद गेहूं की फसल पकेगी तो उन फसलों को पकाने के लिए किसानों को पूरी बिजली देनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, गुजरात में जो त्रासदी हुई उसके लिए हमारी सरकार ने, हमारे प्रदेश के लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है और उसके लिए एक सिस्टम अडोप्ट किया है। यह बहुत ही सराहनीय काम है, अच्छा काम है लेकिन 10 मार्च 2001 के "दि ट्रिब्यून" के आर्टिकल 'Team back with imported goodies - Deputy Commissioner orders probe' में जो बात छपी है, उसमें लिखा है कि —

> "Government employees from Haryana are back from Rapar in Gujrat after their much-pulicised relief opreration with truckloads of foreign goodies meant for quack victims, forcing the district administration to order a probe into who pinched what."

(विघ्न) अगर यह बात आ गई है तो ठीक है आप इस पर रोशनी डाल दें। मैं इसमें सरकार का कोई कसूर नहीं मानता हूं, कसूर उनका है जो डिफाल्टर हैं। उनको सजा दी जाए। (विघ्न) मैं बहुत सजा दे सकता था। (विघ्न) आप गलत कह रहे हैं। दैनिक भास्कर में भी ऐडिटोरियल आया है। जिन्होंने

भी यह कसूर किया है उनको सजा देनी चाहिए। उनको माफ नहीं किया जाना चाहिए और इसकी पब्लिसिटी भी होनी चहिए ताकि जनता को पता रहे कि उन कसूरवारों को क्या सजा मिली है।

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने राज्यपाल महोदय की स्पीच के जवाब में कहा है कि इन्होंने पिछली सरकारों के मुकाबले में 49 लाख यूनिट बिजली ज्यादा दी है। आपने फरीदाबाद के यूनिट की भी बिजली इसमें जोड़ी होगी अगर हां तो आपने पिछली सरकारों के मुकाबले में बिजली कम दी है। अगर इस यूनिट की बिजली निकाल दी जाए तो आपने 30 लाख यूनिट ही बिजली दी है। असल में आपने जो फरीदाबाद के यूनिट से बिजली दी है उसको भी 49 लाख में काउंट किया है। अगर इसको काउंट नहीं करेंगे तो आपकी बिजली कम हो जाएगी। मैंने पेपर में पढ़ा था कि गवर्नमैंट ऑफ इंडिया ने मुख्य मंत्रियों की कान्फ्रैंस में स्टेट गवर्नमैंटस के बिजली बोर्डों को कर्जे से राहत दिलाने के लिये कुछ देने का वायदा किया है। अगर वे देते हैं तो अच्छी बात है क्योंकि आपने जो एन०टी०पी०सी० को 130 करोड़ के बाण्ड दिए हुए हैं वे मिल जाएंगे। आपको इस बारे में गवर्नमैंट ऑफ इंडिया से बात कर लेनी चाहिए। ओटु डैम और पथराना डैम की बात आपने की है यह कोई नई बात नहीं है। ये दोनों डैम मेरे ही चालू किए हुए हैं। इसमें आपने क्या नई बात की है। (विघ्न) यह जो आपने नाबार्ड की स्कीमों के बारे में कहा है ये कौन-कौन सी हैं इनके बारे में भी आप खोल कर बता दें। वित्तमंत्री जी आप बताएं या मुख्यमंत्री जी बता दें। अध्यक्ष महोदय, यह जो नैशनल हाई-वे पर ट्रैफिक का प्रबन्ध करने जा रहे हैं मैं इसकी सराहना करता हूँ। यह अच्छी बात है, यमुना ऐक्शन प्लान में जो इन्होंने लिखा है कि 12 कस्बे होंगे यह तो पुरानी बात है यह कोई आपके वक्त की बात नहीं है। एक आपने लिखा है कि किसानों को सैमेनेरेटिव प्राईस मिलेगा, क्या मिलेगा। पहले जो किसानों की पैडी सस्ती गई थी उन किसानों को आपको कम्पनसिएट करना चाहिए। (विघ्न) हमारी सरकार ने भी उसकी मांग की थी लेकिन आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा यह मैं कह नहीं सकता हूँ। आपको उन किसानों को सहायता देनी चाहिए जिनकी पैडी सस्ती बिकी है। इसी तरह से इन्होंने यह भी कहा कि पानीपत रिफाइनरी की क्षमता 6 मिलियन टन से 12 मिलियन टन की हो जाएगी। यह बहुत अच्छी बात है। अध्यक्ष महोदय, हमने इसके साथ एक ऐग्रीमैंट किया था जिसके तहत 301 मैगावाट रिफाइनरी से पावर मिलनी थी। अगर इसकी क्षमता 12 मिलियन टन हो जाएगी तो 600 मैगावाट पावर हरियाणा को मिलेगी जो कि एक अच्छी बात है। अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका शुक्रियादा करता हूँ। धन्यवाद।

कैप्टन अजय सिंह यादव (रिवाड़ी) : अध्यक्ष महोदय, कल सम्पत सिंह जी ने सदन में 2001-2002 का जो ऐनुअल बजट पेश किया है उस पर चर्चा के विषय में मैं आज अपने विचार प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं तो समझता था कि सम्पत सिंह जी बड़े पढ़े-लिखे और काबिल हैं लेकिन इन्होंने जो बजट पेश किया है उसमें तो मुझे कोई नवापन नजर नहीं आया है और न ही यह बजट विकासशील है। इस बजट में उन्होंने 2150 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। वर्ष 2000-2001 में इन्होंने 2530 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा था जिसे बाद में रिवाइज करके 1815 करोड़ रुपये कर दिया था। इसमें शोर्टफाल बहुत ज्यादा है। इकोनोमिक्स सर्वे ऑफ इंडिया में बाकायदा लिखा हुआ है कि ऐग्रीकल्चरल कमोडीटीज की सेल प्राइस पिछले दो सालों में रिवर्स हो चुकी है। हरियाणा का इंडैक्स का जो बेस 1980-81 माना गया है तो उसके हिसाब से यह 8.2 परसैंट नीचे आ गयी है। इसी प्रकार से अगर आल इंडिया प्राइस इंडैक्स का बेस 1982 माना जाए तो उसमें यह 2.7 परसैंट हो गयी है। अध्यक्ष महोदय, जो हरियाणा स्टेट वर्किंग क्लास कंज्यूमर इंडैक्स है उसमें यह 2.8 परसैंट है। इसी तरह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में पलसिज की प्रोडक्शन 1995-96 में 451 टन थी जो घटकर

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

1999-2000 में 0.79 टन रह गया है। कॉटन में 1996-97 में उत्पादन 1507 गांठों का था जो 1999-2000 में घटकर 1309 गांठ हो गया है। इसी तरह से ऑयल सीड में भी बड़ी भारी गिरावट आयी है। 1995-96 में यह 783 टन था जो 1999-2000 में घटकर 642 टन हो गया है। शुगर केन में पहले प्रोडक्शन 1995-96 में 809 क्विंटल था वहीं 1999-2000 में यह 739 क्विंटल हो गया है। इसी प्रकार से जो नेट एरिया इरीगेशन का था वह सेचुरेशन प्वायंट पर आ चुका है। टोटल इकोनोमी कर्ज में डूब चुकी है। हरियाणा सरकार पर 14 हजार 39 करोड़ रुपये का कर्ज है और पब्लिक सैक्टर का घाटा 2841 है। इनका बजट 2841 करोड़ रुपये का है इस तरह से इनके ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा है। जब मुख्य मंत्री जी इधर बैठते थे तो कहा करते थे कि शराबबंदी के दौरान जो टैक्सिज बंसी लाल जी ने लगाये हैं, उनको वे हटा लेंगे। इसलिए हमें तो उम्मीद थी कि वित्तमंत्री जी अपने बजट के माध्यम से लोगों को राहत देंगे। इन्होंने पहले भी कहा था कि हमने टैक्स फ्री बजट पेश किया है लेकिन उसके बाद दुनिया भर के टैक्स लाद दिए गए। हाउस टैक्स के नाम पर टैक्स लगाया गया और आम पब्लिक को जो राहत देने की बात कही थी बजाय उसके आपने मोपेड, स्कूटर आदि पर म्यूनिसिपल टैक्स लगा दिया। मुख्य मंत्री जी जगह-जगह गेहूं के बारे में मिनिमम सपोर्ट प्राइज के बारे में कहा करते थे, बोनस देने की बात कही गई थी उसके बारे में बजट में कहीं जिक्र नहीं किया गया आप बोनस कहां से देंगे?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, शायद सम्मानित सदस्य को इस बात का ध्यान नहीं है, ये सदन में नहीं थे। मैंने सदन से बाहर भी कहा था और सदन में भी कहा था और पुनः इस बात को दोहरा रहा हूं कि अगर केन्द्र सरकार पिछले साल के मुकाबले में गेहूं के दाम नहीं बढ़ाएगी तो हम हरियाणा सरकार की तरफ से किसानों को बोनस देंगे।

कैप्टन अजय सिंह यादव : मैंने यह कहा है कि बजट में इसका उल्लेख नहीं है। आज प्रदेश के अंदर सूखे की स्थिति पड़ी हुई है खासकर जो मेरा इलाका है वहां पर मुख्य मंत्री हर तीसरे दिन पहुंच जाते हैं लेकिन देने के नाम पर कुछ भी नहीं है। आज हमारी पार्टी के बारे में चर्चा करते हैं। इन्होंने वहां पर ट्रेनिंग कैंप लगाया और वहां पर अपने वर्कर्स से 1100 रुपये टैक्स ले लिया अपने वर्करों को भी नहीं छोड़ा।

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, उनको जो लिट्रेचर दिया गया था वह फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया था।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने इंडस्ट्री पर चार परसैंट टैक्स लगा दिया। टोटल इंडस्ट्री यहां से पलायन कर रही हैं। ड्राइविंग लाइसैंस पर 100 रुपये और स्कूटर पर 100 रुपये म्यूनिसिपल टैक्स लगा दिया। पांच परसैंट कॉमर्शियल टैक्स एक हजार रुपये से लेकर ढाई हजार रुपये तक लगा दिया और टैक्स फ्री बजट कहते हैं। प्रोफेशनल फायर टैक्स लगा दिया। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने इरीगेशन डिपार्टमैंट के ऊपर बजट के अंदर कहीं भी एस०वाई०एल० का जिक्र नहीं किया। असल में बात यह है कि जो हमारे हिस्से का पानी है वह सिरसा और हिसार के लोग पी रहे हैं। अगर यह एस०वाई०एल० बन जाती है तो एस०वाई०एल० का पानी साउथ हरियाणा के खेतों में जाएगा लेकिन आपकी नीयत में खोट है। आप चाहते नहीं हैं कि एस०वाई०एल० का पानी साउथ हरियाणा के खेतों में जाए। (विघ्न) अगर ये एस०वाई०एल० कैनाल बना देते हैं तो दक्षिणी हरियाणा के हिस्से का पानी हमें मिल जाएगा अगर अंतरिम रिपोर्ट कावेरी की लागू हो सकती है तो इराडी ट्रिब्यूनल की क्यों नहीं लागू हो सकती।

श्री भागी राम : अध्यक्ष महोदय, मैं अजय सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि ये फौज खुद छोड़कर आए, भागकर आए या इनको निकाल दिया था।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, इसका नाम खुद भागी राम है। (हंसी) भागने का काम तो इनका है, मैं तो अपनी मर्जी से आया हूँ। अध्यक्ष महोदय, एक बात जो मैं कह रहा था जैसा कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने कुरुक्षेत्र में अपने भाषण में कहा कि रीवर अथोरिटी बनाकर एस०वाई०एल० की समस्या को रिजोलव कर सकते हैं। जिस प्रकार रीवर अथोरिटी से कावेरी की समस्या हल हो सकती है तो यहां की क्यों नहीं हो सकती। बस यह कह देते हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है इसलिए यह मामला रिजोलव नहीं हो रहा। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, सदन के सम्मानित मेरे दोस्त को मैं यह बताना चाहूंगा कि जो फैसला कोर्ट के विचाराधीन हो उस पर चर्चा करते हुए खासा मौहतैदा रहना चाहिये। इस बारे और भी कई माननीय सदस्य जिक्र कर रहे थे चौधरी बंसी लाल जी ने भी जिक्र किया कि सिपाहियों की भर्ती के लिये फार्म के 500 रुपये यह सरकार ले रही है। जो 1600 सिपाही निकाल दिये गये वे कैसे लगाये गये थे यह देखने की बात है। जिन 1600 सिपाहियों को सुप्रीम कोर्ट ने निकाला था उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिवीजन फाइल की थी आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी वह रिवीजन भी खारिज कर दी है। अगर उस समय वे सिपाही कायदे कानून से मुकम्मल भर्ती किये थे तो फिर वे सड़क पर क्यों आ गये। हमने तो फिर उनको कहा है कि भर्ती में समय की छूट देंगे, अधिक आयु सीमा में छूट देंगे, बल्कि पांच नम्बर फालतू देंगे। हम कोर्ट के फैसले के बाद भी लोगों को इज्जत देना चाहते हैं। इसलिए कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : कप्तान साहब आप दो मिनट में कंक्ल्यूड कीजिये।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि गुड़गांव में 18 एकड़ भूमि फाइव स्टार होटल बनाने के लिए तो ये सरदार प्रकाश सिंह बादल को दे सकते हैं लेकिन उनसे एस०वाई०एल० नहर के बारे में बात नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष : आप बजट पर बोलें। आप को यह मालूम है कि एस०वाई०एल० नहर का बजट राज्य सरकार का होता है या भारत सरकार का होता है?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, इस सरकार की नीयत ठीक नहीं है। इस सरकार की नीयत में खोट है इसलिये दक्षिणी हरियाणा का पानी सिरसा और हिसार में ले जा रहे हैं। हमारी दोहन पच्चीसी ने पिछले चुनावों में इस सरकार को वोट नहीं दिये फिर भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने वहां पर साइबर कैफे खोल दिया और वहां के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। दुजाना और हमीरपुर भाइनर का पानी राजस्थान में ले जा रहे हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, जहां तक बिजली की बात है। बिजली बोर्ड के महकमे में तीन चार कारपोरेशन बना दिये हैं और उससे ज्यादा बोझ बढ़ा है। आज भी जो ट्रांसफार्मर्ज हैं वे पूरी बिजली नहीं दे रहे हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप अपनी कंसट्रक्टिव बात कहें।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, आज हर काम करवाने के लिए बिजली के बिलों का एन०ओ०सी० लेना पड़ता है। डी०आर०डी०ए० के लोन के लिए चाहे व्हीकल के रजिस्ट्रेशन के लिए, बैंक लोन के लिए, टयूबवैल्ज के कनैक्शन के लिए, इस के लिए 50 रुपये का खर्चा आ जाता है। आज हरियाणा में बिजली के लाइन लोसिस 41 प्रतिशत हैं जबकि नेशनल लेवल पर ये लाइन लोसिस 20 प्रतिशत है। In reply to started question No. 285 asked by me, "It is given

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

that no other new agreement with the World Bank or any agency has been signed by the Government of Haryana for restructuring and reforming the power sector since 1998-99 except making amendments in the Haryana Project agreement". तो क्या मुख्य मंत्री महोदय जी बताएंगे कि क्या-क्या अमैंडमैंट की हैं। आपने जो वर्ल्ड बैंक के बारे में निरस्त करने की बात कही थी और कहा करते थे कि चौ० बंसी लाल ने सारे पावर सैक्टर्स बेच दिए? क्या मुख्य मंत्री महोदय बताएंगे कि वर्ल्ड बैंक के साथ किए गए एग्रीमैंट में क्या-क्या अमैंडमैंट्स की गई हैं। अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि 12 पैसे मीटर रेट में बढ़ा दिए गए और किसानों के फ्लैटस रेट में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी गई। इस सरकार ने बिजली के कमर्शियल रेट 4 रुपये 19 पैसे और डोमैस्टिक जो आम व्यक्ति का है उसको 4 रुपये 25 पैसे कर दिया। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से हाउस टैक्स के बारे में जो कलैक्टिव रेट के नाम पर उसकी कोस्ट निकाली जा रही है, आज कोस्ट आफ कंस्ट्रेक्शन निकाली जा रही है। 300 स्केवयर फुट आर०सी०सी० के नाम के ऊपर जो सर्वेक्षण के बारे में सैल्फ असैसमैंट फार्म दे रखा है और 10 परसैंट आफ दि रैन्टल वैल्यू लगा दी है इसके अलावा इस सरकार ने न जाने कितने प्रोफैशनल टैक्स डाक्टरों के ऊपर लगा दिए हैं। अध्यक्ष महोदय सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मुख्य मंत्री महोदय रिवाड़ी में बावल के अन्दर आए। मेरे क्षेत्र के लोग वहां गए और उन्होंने कहा कि हमारा काम कीजिए लेकिन उनको वहां के लोगों ने वहां से भगा दिया और कहा कि यह तो बावल हल्के के लोगों का काम है।

श्री अध्यक्ष : आप जल्दी समाप्त करें।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, इनकी जितनी भी ताकतें हैं, चाहे जिला परिषद की हैं, चाहे एम०एल०ए० की और चाहे ब्लाक समिति के मैम्बर की ताकत हैं *******

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब जो कह रहे हैं, वह रिकार्ड न किया जाए। (शोर)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, हमें एक बात का बड़ा दुःख और खेद है कि आपने 2 बजे हाउस को उठाया, हम समझते थे कि आधे घण्टे का ब्रेक खाने के लिए होगा। हम तो खाने के लिए बाहर निकले ही नहीं थे उससे पहले ही दोबारा 2 बजे हाउस की कार्यवाही शुरू हो गई। अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा और ज्यादती हमारे साथ क्या हो सकती है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। यहां पर हाउस को गुमराह किया गया है जो कि मुनासिब बात नहीं है। 2 बजे हाउस को उठाया जाता है और फिर उसी वक्त हाउस की कार्यवाही शुरू कर दी गई जो कि मुनासिब बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, अगर कोई मैंबर बोल रहा हो और उसे आप बैठाना चाहते हैं तो आपको कहना चाहिए कि आप अपनी बात दो मिनट में समाप्त करें लेकिन आपने कैप्टन अजय सिंह को सीधे ही बैठा दिया। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी, आपके सभी मैंबरों को बोलने का पूरा मौका दिया जा रहा है। मांगे राम गुप्ता जी भी संतुष्ट हैं, इन्हें बोलने का पूरा मौका मिला है।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं संतुष्ट नहीं हूं। मुझे बजट पर बोलने के लिए पूरा समय नहीं मिला।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, हमारा कोई भी मैंबर संतुष्ट नहीं है।*******

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी, चेयर के बारे में जो कुछ भी कहें वह रिकार्ड न किया जाये। चौधरी भजन लाल जी, हाउस तरीके से चल रहा है, प्लीज आप बैठें।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी के सदस्य कैप्टन अजय सिंह जी बोल रहे हैं वे बहुत ही सीनियर विधायक हैं और हमारी पार्टी के उप लीडर हैं आपने इन्हें एकदम बैठा दिया। अगर आप चाहते हैं कि हम हाउस में न बैठें तो हम बाहर चले जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेहरबानी करके कैप्टन साहब को पांच मिनट का समय और दिया जाये ताकि वे अपने हल्के की बातें कह सकें।

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी, अभी दूसरे मैंबर्ज को भी बोलना है बाद में समय दे दिया जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता और विपक्षी साथियों को इस बात के लिए आपकी प्रशंसा करनी चाहिए कि आपने बड़ी फ्राखदिली से इन्हें राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए पूरा समय दिया। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर साढ़े सात घंटे बहस चली है और आपने विपक्ष के साथियों को उस पर बोलने के लिए पूरा समय दिया। लेकिन जिस समय आप विपक्ष के भाइयों को बोलने के लिए समय देते थे उस समय ये बाथरूम में चले जाते थे। आपने तो इन्हें राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर दोबारा भी बोलने के लिए समय दे दिया था फिर भी ये कह रहे हैं कि इन्हें समय नहीं दिया जा रहा। चौधरी भजन लाल जी कह रहे हैं कि हाउस दो बजे एडजोर्न कर दिया गया। ये एक सीनियर विधायक हैं, मुख्य मंत्री भी रहे हैं इनको मालूम होना चाहिए कि पूर्व निर्धारित समय सुबह 9.30 बजे से लेकर दोपहर 1.30 बजे तक था और दूसरी सिटिंग दोपहर 2.00 बजे से लेकर 6.30 बजे तक की है और हाउस का समय 1.30 बजे बढ़ाया गया तथा हाउस दो बजने में पांच मिनट पहले एडजोर्न हुआ और दूसरी सीटिंग अपने टाईम के हिसाब से 2.00 बजे आरम्भ हो गई। लेकिन उस समय कांग्रेस का कोई भी सदस्य हाउस में नहीं था। चौधरी बंसी लाल जी और जितेन्द्र मलिक को तो इस बात की जानकारी थी इसलिए ये दोनों तो यहीं पर थे। बहन अनिता यादव उस समय हाउस से बाहर जा रही थी मैंने इनको कहा कि अभी हाउस शुरू होने वाला है और आप बाहर जा रही हैं। जब कोई सदस्य नहीं मिला तो चौधरी बंसी लाल जी को बजट पर बोलने का समय दिया गया। अध्यक्ष महोदय, क्या कैप्टन अजय सिंह जी को पुराने वक्त याद नहीं हैं कि ये कूक कर रह जाते थे और इन्हें एक मिनट भी बोलने के लिए समय नहीं दिया जाता था। अध्यक्ष महोदय, यह तो आपकी फ्राखदिली है कि कैप्टन साहब बोलने के काबिल न होते हुए भी आपने इन्हें बोलने का समय दिया। इस बात के लिए इन्हें आपकी प्रशंसा करनी चाहिए। चौधरी बंसी लाल जी की सरकार के समय हमारे 22 सदस्य होते थे और विपक्ष के नेता को बोलने के लिए पांच मिनट का समय नहीं दिया जाता था।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, हमारी संख्या भी 21 की है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर साढ़े सात घंटे बहस चली है। आप रिकार्ड मंगवा कर देख लें कि कितना समय विपक्ष को बोलने के लिए दिया गया है। विपक्ष को अभिभाषण पर बोलने के लिए खुला समय दिया गया और विपक्षी भाई पानी पी-पी कर बोले। इनको दोबारा बोलने का भी अवसर दिया गया। अब भी इनको छूट है। अध्यक्ष महोदय, आप सैशन को लम्बा चलाइए और कौंटीन्यू रखें। दोबारा से इनको बुलाओ और क्लिक के बुलाओ।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक नहीं है। हम आगे जाकर आपकी बहुत सराहना भी करेंगे।

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, आप बैठिए। आपका भाषण हो चुका है।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कह कर अपनी बात खत्म करता हूं। "किसी ने कहा कि बेटे का नाम के है, इसका क्या नाम निकला, लखी तो मां ने देखा, भाजत देखा सुरा, आगे से पीछा भला, नाम धरचा लटूरा।" आपने पहले वाले स्पीकर को भला कहलवा दिया उसके लिये हमें खुशी है और कोई बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अब श्री अनिल विज जी बोलेंगे।

श्री अनिल विज (अम्बाला कैंट) : अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने जो वर्ष 2001-2002 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत किये हैं उसके ऊपर अपने विचार प्रकट करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। There is a saying, "There are two ways to become rich, first is to increase his resources and the second is to cut short of his expenses." वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें उन्होंने नये कर न लगा कर दूसरा मार्ग अपनाया है। उन्होंने अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति और अर्थ व्यवस्था में ही बजट अनुमान पेश करने का संकल्प व्यक्त किया है उसके लिए मैं वित्त मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। (इस समय मेजें थपथपाई गई) जो वित्तीय सर्वे प्रस्तुत किया गया है उसके मुताबिक पिछले वर्ष में हमारी स्टेट ने 6-9 परसैंट ग्रोथ रजिस्टर्ड किया है। हालांकि जिस दिन से सत्र आरम्भ हुआ है उसी दिन से हम सब लोग सदन में हिस्सा ले रहे हैं और अपने-अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। हम जिस सहस्र शताब्दी को पीछे छोड़ आये हैं उसकी वैसे तो अनेक उपलब्धियां रही हैं, वे उपलब्धियां गिनाई नहीं जा सकती हैं लेकिन उस शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि है—डैमोक्रेसी शासन पद्धति को अंगीकार करना। सारे प्रदेशों और तमाम देशों ने इस पद्धति को अंगीकार किया है। इसका मूल उद्देश्य केवल वोट डालना या सरकार बनाना ही नहीं है बल्कि इस पद्धति का उद्देश्य हमारे अधिकारों की रक्षा करना है। इसमें दो प्रमुख बातें हैं। एक तो प्रैस को फ्री बनाकर रखना और दूसरी बात फ्री-डिस्कशन के लिए व्यवस्था बनाना। डैमोक्रेसी ही इन दोनों चीजों के राइट को सेफगार्ड करती है और उसे सेफ गार्ड करने के लिए आप बार-बार सभी सम्मानित सदस्यों को बोलने का पूरा अवसर प्रदान कर रहे हैं। चाहे सत्ता पक्ष के सदस्य हों, चाहे विपक्ष के सदस्य हों, आप सभी को अपने हलके की बात कहने का पूरा अवसर और अधिकार दे रहे हैं। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। **(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)**

उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम पिछले साल के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो इस वित्तीय वर्ष में प्राइमरी सैक्टर में जो इन्क्रीज हुआ है वह 5.6 प्रतिशत का इन्क्रीज है। सैकण्डरी सेक्टर में छः परसैंट तथा थर्ड सैक्टर जिसमें कि ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आते हैं उसमें 9 परसैंट का इन्क्रीज रजिस्टर्ड हुआ है। ऐसा इसलिये नहीं हो पाया है कि हमारी प्रदेश सरकार द्वारा आज आर्थिक तबदीलियां की जा रही हैं बल्कि इसके लिये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रदेश में और देश में शांति व्यवस्था को बनाये रखना। इस विषय में अगर पिछले वर्ष का अवलोकन कर लिया जाए तो हमारी सरकार इस बार शांति व्यवस्था कायम करने में पूरी तरह सफल रही है। प्रदेश में चारों तरफ शांति का वातावरण है, कहीं पर कोई कम्यूनल हारमोनी नहीं है, कहीं पर लेबर अण्डरैस्ट नहीं है। कई सदस्य बार-बार एक बात कहते हैं, कहीं पर किसी के मर्डर की बात उठाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा तो होता रहता है और सब जगह होता है लेकिन यह समस्या इतनी बड़ी नहीं है। अगर

नैशनल क्राइम रेट को देखें तो वह बढ़ रहा है और 3.6 परसैंट के हिसाब से नैशनल क्राइम रेट बढ़ा है। इस हिसाब से भी हम देखें तो सरकार ने इस बारे में बहुत सफलता प्राप्त की है कि हमारे प्रदेश में पूरी शांति व्यवस्था है जिसके कारण हम प्रदेश में तरक्की कर पा रहे हैं। मैं सरकार को इस बात की बधाई देना चाहूंगा कि आज की सरकार हर क्षेत्र में चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वह एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, चाहे वह इंडस्ट्रीज लगाने की बात हो और चाहे किसी विकास के कार्य को करने की बात हो सरकार हर क्षेत्र में तरक्की पा रही है। हम प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम रखने में कामयाब रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार कैसी होनी चाहिए, सरकार वह होनी चाहिए जो उपयोगी हो, जो सहयोगी हो और जो उद्योगी हो। यह बात ठीक है कि कुछ लोग सरकार को गलत कहते हैं और कुछ लोग ठीक कहते हैं लेकिन महापुरुषों का एक पैमाना बना दिया कि सरकार वह होनी चाहिए जो उपयोगी हो, उद्योगी हो और सहयोगी हो। उपयोगी सरकार वह हो जो हरियाणा प्रदेश के लोगों का भला करने वाली सरकार हो। आज की सरकार ने जो नीतियां बनाई हैं उनसे हरियाणा प्रदेश के लोगों का भला हुआ है। यदि हम विकास की दृष्टि से देखें तो सरकार ने लोगों की भलाई करने के लिए अनेकों नीतियां बनाई हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जो बुढ़ापा पैंशन थी उसको सरकार ने 100 से बढ़ा कर 200 रुपये कर दिया यानि डबल कर दी। इसी तरह से विकलांगों की पैंशन भी डबल कर दी। सरकार ने जो भी योजनाएं बनाई हैं उनसे ऐसा लगता है कि सरकार अपने प्रदेश के लोगों का भला करना चाहती है। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार उद्योगी होनी चाहिए, इनोवेटिव होनी चाहिए सरकार में कुछ कर गुजरने की क्षमता होनी चाहिए, सरकार में कुछ नया कर दिखाने की हिम्मत होनी चाहिए। अगर इस दृष्टि से देखें तो सरकार ने इसके प्रयत्न किए हैं। सरकार ने अपने प्रदेश में नई शिक्षा नीति बनाई है और सरकार ने नई आई०टी० नीति बनाई है। सरकार ने राइट ऑफ वे बिल की नीति बनाई है। अनेकों क्षेत्रों में सरकार कोशिश कर रही है, उद्यम कर रही है कि प्रदेश के लोगों की भलाई हो। सरकार कोशिश कर रही है कि सारी व्यवस्था को परिवर्तित किया जाए क्योंकि आज का युग हर क्षेत्र में परिवर्तन चाहता है। उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार ने बजट पेश किया वह कोई आंकड़ों का बजट नहीं है वह भी एक स्ट्रक्चरल रिफार्मज देने का बजट था जिसको परिवर्तित किया जा रहा है ताकि एक ऐसी व्यवस्था कायम हो सके, एक ऐसा वातावरण तैयार हो सके जिससे इस देश को, इस देश के हर प्रदेश को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो सके और हर व्यक्ति हर क्षेत्र में तरक्की कर सके। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने गवर्नर एड्रैस में और बजट स्पीच में भी गुजरात में जो त्रासदी हुई उसका वर्णन किया है। सरकार ने वहां पर लोगों की सहायता करने के लिए अपने प्रदेश से दल भेजे और दूसरे साधन भी वहां पर भेजे। सरकार ने हर तरह से लोगों से सहयोग ले करके वहां पर सहायता भेजी। इस बात के लिए मैं सरकार की सराहना करना चाहता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, खाली गुजरात में सहायता भेजने की ही बात नहीं है जब उड़ीसा में बाढ़ आई थी तब भी यह सरकार पीछे नहीं रही सरकार वहां पर सहायता भेजने के लिए आगे बढ़ी। सरकार ने उड़ीसा के लोगों की सहायता की। उड़ीसा के लोगों की ही नहीं बल्कि जब राजस्थान में सूखा पड़ा तब भी हमारे मुख्य मंत्री जी ने खुद जगह-जगह जा करके भूसे के ट्रक भरवा-भरवा कर राजस्थान में भिजवाए। जहां पर हमारे मुख्य मंत्री जी सहायता करते हैं वह अपने फर्ज से भी ज्यादा करते हैं। इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि अनेकता में एकता। चाहे हम भिन्न-2 प्रांतों के हैं चाहे हमारी भिन्न-2 भाषाएं हैं लेकिन हम सब राष्ट्रीय हैं हम सब भारतीय हैं हम किसी भी कुदरती त्रासदी के समय सब एक हैं। यह बात इस बात से स्पष्ट होती है कि हमारी हरियाणा सरकार ने गुजरात प्रदेश के 19 गांव गोद लिए हैं और उन 19 गांवों के लोगों को जिस किसी चीज की जरूरत थी, जो भी उनकी आवश्यकता थी उसको पूरा करने के प्रयास सरकार कर रही है।

[श्री अनिल विज]

उपाध्यक्ष महोदय, आज की सरकार ने नई शिक्षा नीति बनाई है। हमारे प्रदेश में जो लिट्रेसी रेट है वह 55.85 परसैंट था लेकिन जो नया लिट्रेसी रेट है वह 52.51 परसैंट है उससे अधिक है। फिर भी इसमें बहुत कुछ किया जाना बाकी है। हमारे जो प्राईमरी स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनमें काफी सुधार हुआ है। जब हरियाणा बना उस समय 1966 में प्राईमरी स्कूल गोइंग बच्चों का लिट्रेसी रेट 58 परसैंट था जो अब 83.54 परसैंट हो गया है। इसी तरह से जो मिडल स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनके लिट्रेसी रेट में 65 प्रतिशत का इजाफा हुआ है लेकिन फिर भी बहुत कुछ करना बाकी है इसीलिए सरकार ने नई शिक्षा नीति बनाई है जिसके तहत प्राईमरी स्कूल से ही सरकारी स्कूलों में बच्चों को अंग्रेजी की शिक्षा व कम्प्यूटर की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। एम्फेसिस दिया जा रहा है कि जो शिक्षा की क्वालिटी है वह इम्प्रूव हो। हमारी सरकार ने प्राईमरी स्कूल से ही अंग्रेजी के विषय को अनिवार्य विषय बना दिया है। इसी प्रकार से कम्प्यूटर की भी एजूकेशन दी जायेगी। सरकार ने ऐसा करके शिक्षा नीति को काफी इम्प्रूव करने की कोशिश की है। जब हम आजाद नहीं थे उस वक्त की आवश्यकताएं कुछ और थीं। उस वक्त के जो हाकिम थे उनको आगे चलने वाले आदमी नहीं चाहिए थे। बल्कि पिछलग्गु चाहिए थे यानी उन्हें क्लर्क चाहिएं थे। आज हमें एक ऐसी शिक्षा नीति की आवश्यकता है जो हमें हर क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान कर सके। आज ऐसी शिक्षा नीति की आवश्यकता है जिसके माध्यम से हमारे यहां के इंजीनियर हमें नेतृत्व प्रदान कर सकें इसी प्रकार से हमें ऐसी ब्यूरोक्रेसी को एजूकेशन देने की आवश्यकता है जो हमें हर दिशा में नेतृत्व दे सके और वह हर चुनौती को स्वीकार कर सके। हमें ये सारी चीजें प्राप्त हो सकती हैं यदि हम अपनी शिक्षा नीति में परिवर्तन करके आज की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा दे सकें। हमें समय के मुताबिक अपनी शिक्षा नीति को बनाना चाहिए जो कि आने वाले समय की आवश्यकतानुसार चुनौती का आगे बढ़ कर सामना कर सके ताकि जो हमारा गुरु का खोया हुआ मान-सम्मान है उसे पुनः प्राप्त किया जा सके। मैं सरकार की सराहना करता हूं कि सरकार ने हिम्मत की है, कोशिश की है, एक सोच बनायी है जिसके तहत अपनी शिक्षा नीति में समय की आवश्यकता को देखते हुए उसमें बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है।

हमारी सरकार ने आई०टी० (इन्फर्मेशन टैक्नालाजी) पॉलिसी पर भी काफी जोर दिया है। यहां पर बोलते हुए हमारे एक साथी ने इस आई०टी० पॉलिसी पर भी सरकार के गवर्नर एड्रैस पर क्रिटिसाईज किया। उन्होंने बोलते हुए आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री का हवाला दिया कि कहीं उनकी तरह ही आपका हाल न हो जाये। सरकार का विरोध किया जाना चाहिए, तथ्यों पर विरोध किया जाना चाहिए लेकिन विरोध के लिए विरोध करना सही नहीं है। आज यह समय की पुकार है, आज समय की आवश्यकता है यदि सरकार सही काम करती है तो उसकी सराहना भी की जानी चाहिए। आज समय की आवश्यकता के अनुसार हमें चलना चाहिए। यदि दूसरे देश हथियारों से लैस होते हैं तो हमें भी हथियारों से लैस होना पड़ेगा। आई०टी० में सारा विश्व काफी आगे कदम उठा चुका है, इसमें हमें भी आगे बढ़ना चाहिए उन्होंने अपनी अलग सोच बनाई है। हमारे विधायक साथियों को भी आई०टी० की स्कीम के तहत कम्प्यूटर की ट्रेनिंग दी गई।

सरकार ने 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम जो चलाया है उसका इनको विरोध नहीं करना चाहिए। हमारे साथियों ने इस महान सदन में अपने भिन्न-भिन्न विचार प्रकट किये। हर विधायक की अपनी एक सोच होती है। आज जनता और सरकार में जो गैप बढ़ रहा है उसको दूर किया जाना चाहिए। मैं कह रहा था कि 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के तहत हर क्षेत्र में विकास कार्य किए गए चाहे वह रूलिंग पार्टी का हल्का था या अपोजिशन पार्टी का हल्का था। मेरे कहने का मतलब यह है

कि जो अच्छे काम हैं उनकी सबको सराहना करनी चाहिए। सरकार द्वारा चलाया गया 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम हमारे यहां पर सफल रहा है इसलिए दूसरे प्रदेश सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि कैसे यह प्रोग्राम सफल हो रहा है और कैसे मुख्य मंत्री इस प्रोग्राम के लिए समय निकाल पाते हैं। ऐसा होने पर हमारा प्रदेश हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। सरकार अपने प्रदेश में अमन और शांति बहाल करने में कामयाब रही है। सरकार ने हर क्षेत्र में अपना नियंत्रण कायम किया है और सरकार हर क्षेत्र में तरक्की कर रही है। हालांकि जैसा कि मैंने पहले कहा है कि हमारे यहां नेशनल लैवल पर क्राईम बढ़े हैं। हमारे यहां पर डब्ल्यू टी०ओ० का भी बड़ा हौवा खड़ा हो गया था। जब इसका असर यहां पर पड़ने लगा तो इसका असर हमारे वस्तु उत्पादन पर पड़ना शुरू हो गया था। विदेशों से जो वस्तुएं आ रही थीं वे हमारे यहां से काफी सस्ती थी जिस कारण हमारे यहां के उद्योगों पर इसका असर पड़ना था और हमारे उद्योग उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे क्योंकि उनका माल हमारे माल से सस्ता होता है जिस कारण हमारे कारखानों पर असर पड़ा और बेरोजगारी बढ़नी शुरू हो गई थी। आज केन्द्र सरकार ने भी 2004 तक अपनी नियुक्तियों पर 10 प्रतिशत का कट लगाया है यानि अब नई नियुक्तियां बहुत कम होंगी। जब नियुक्तियां कम होंगी और लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो क्राईम रेट्स भी बढ़ेगें। क्राईम इसलिए बढ़ेंगे क्योंकि रोजगार न मिलने पर अनएम्पलाएमैंट बढ़ेगा और इसका असर क्राईम पर अधिक होगा। You cannot pluck a flower without shaking a star.

15-00 बजे उपाध्यक्ष महोदय, जिस देश में कौन बनेगा करोड़पति और छप्पर फाड़ के जैसे कार्यक्रम टैलिविजन पर चलाए जा रहे हों उससे क्राईम रेट बढ़ेगा ही। उपाध्यक्ष महोदय, यह कहा जा सकता है कि इन प्रोग्राम्ज का क्राईम रेट से क्या ताल्लुक है लेकिन इसका ताल्लुक है। ऐसे प्रोग्राम्ज लोगों में रातों-रात अमीर बनने के सपने जागृत करते हैं (विघ्न)। ये लोगों में इच्छाएं जागृत करते हैं रातों-रात करोड़पति बनने की। जब लोग इस प्रकार से करोड़ पति नहीं बन पाते हैं, जब वे हॉट सीट तक नहीं पहुंच पाते जहां पर अमिताभ बच्चन बैठ कर पूछता है कि अगर आप को एक करोड़ रुपया मिल गया तो आप क्या करेंगे? जो वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं वे लोग एक करोड़ रुपये को हासिल करने के लिए नये रास्ते अपनाते हैं जो युवकों के कदमों को क्राईम की तरफ ले जाते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि कई ऐसे कारण हैं जिनसे क्राईम रेट बढ़ता है। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : विज साहब, अब आप वाईड अप करें।

श्री अनिल विज : उपाध्यक्ष महोदय, आप जब भी कहेंगे मैं अपनी बात को समाप्त कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप पांच मिनट में समाप्त करें।

श्री अनिल विज : ठीक है जी, मैं पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं अन्य विषयों के साथ ही साथ सरकार का ध्यान अपने हल्के की समस्याओं की ओर भी दिलाना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम ही है कि स्पोर्टस के विषय पर भी काफी ध्यान दिया गया है। खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए खिलाड़ियों को उत्साहित करने के लिए सरकार ने काफी काम किया है। हमारे प्रदेश में पोटेंशियल है लेकिन उनकी केयर नहीं हो पा रही थी, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा था लेकिन इस सरकार ने इस ओर भी ध्यान दिया है इसके लिए मैं सरकार की सराहना करना चाहता हूं। बिजली को स्ट्रैंथन करने के लिए भी सरकार काफी प्रयत्न और प्रयास कर रही है उसके लिए भी मैं सरकार की सराहना करना चाहता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैं अपना अधिक समय अपने हल्के की समस्याओं पर लगाना चाहता हूं और अपने हल्के की समस्याओं तक सीमित रहना

[श्री अनिल विज]

चाहता हूं क्योंकि मेरी राजनीति तो अम्बाला छावनी से शुरू हो कर अम्बाला छावनी पर ही खत्म हो जाती है। बाकी जो प्रदेश की नेशनल पार्टियां हैं उन्होंने तो अपनी बात रखी है और रखनी भी है लेकिन मैं अपने हल्के की बात रखना चाहता हूँ। अपनी बात को रखने से पहले, उपाध्यक्ष महोदय, मैं फाईनैंस मिनिस्टर और लोकल गवर्नमैंट मिनिस्टर का ध्यान जो हाउस टैक्स लगाया गया है उसकी तरफ़ दिलाना चाहता हूँ। हालांकि मैं इस नीति की सराहना करता हूँ कि सरकार ने हिम्मत की है एक ऐसी नीति बनाने की जो सबको यूनीफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर के नीचे ले कर आएगी। टैक्स स्ट्रक्चर ऐसा नहीं हो कि किसी की पहुंच है तो उसका टैक्स 100 रुपये कर दो और जिसकी पहुंच नहीं है उसका टैक्स 1000 रुपये कर दें। मैं इस बात की तो सराहना करता हूँ कि सरकार ने एक फार्मूला बना दिया जिसके तहत सब को एक समान टैक्स स्ट्रक्चर में लाया जाएगा। ऐसा होना भी चाहिए। मैं पहले भी इसकी ताईद करता रहा हूं लेकिन मैं सरकार से यह कहने जा रहा हूं कि इस फार्मूले का फिर से अध्ययन करवा लिया जाए कितना टैक्स बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि कुछ तो जो आंकड़े प्रस्तुत किये जा रहे हैं वे ठीक प्रस्तुत नहीं किए जा रहे हैं। मैंने खुद 70-80 फीसदी केसों को कैल्कुलेट किया है और आपको बताना चाहता हूँ और लोकल बॉडीज मिनिस्टर तथा सरकार को भी बताना चाहता हूँ। मुझे पूरा भरोसा है और मेरा विश्वास है कि मुख्य मंत्री जी इसके बारे में जरूर ध्यान देंगे। फार्मूला यूनीफार्म होना चाहिए ऐसा मेरा ख्याल है और सब सदस्य भी इस बात में राजी होंगे कि इसमें कुछ न कुछ छूट दिये जाने की भी आवश्यकता है। तीन या चार गुणा टैक्स कोई भी नहीं देगा। उस फार्मूले में 10 में से 9 केसिज का टैक्स 3-4 गुणा बनता है। मैं चाहूंगा कि आदरणीय वित्त मंत्री चौधरी सम्मत सिंह जी इस विषय पर ध्यान दें और इसका दोबारा आकलन करवा लें। दोबारा इसकी जांच करवा लें तो अच्छा है। जो आदमी ठीक टैक्स दे रहे हैं उनका 20-25 प्रतिशत से ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही मैं यह सुझाव भी देना चाहूंगा कि जो सेल्फ आकुपाईड हाउसिज हैं जिनके अपने मकान हैं और वे उनमें खुद रहते हैं उनको कम से कम 50 प्रतिशत रिबेट अवश्य दी जानी चाहिए ताकि इस टैक्स का उन पर ज्यादा भार न पड़े। उपाध्यक्ष महोदय, अम्बाला छावनी का स्टेट्स बाकी शहरों से भिन्न है। हमारे यहां पर दो लोकल बाडीज हैं, एक नगरपालिका है और दूसरा कण्टोनमैंट बोर्ड है। कण्टोनमैंट बोर्ड के अपने रूल्ज हैं और वह डिफैन्स एक्ट से लागू होता है उसके तहत कण्टोनमैंट बोर्ड में पहले एक सीजन्ड एग्रीमैंट के तहत ऑक्ट्राय सारे शहर की नगरपालिका कलैक्ट करती थी और उसमें कुछ हिस्सा कन्टोनमैंट बोर्ड को देती थी। लेकिन आपकी सरकार ने चुंगी समाप्त करने का ठीक निर्णय लिया, उस निर्णय को कन्टोनमैंट बोर्ड मानने के लिए तैयार नहीं है। कन्टोनमैंट बोर्ड कहता है कि हरियाणा सरकार का निर्देश हमारे ऊपर लागू नहीं होता है। आपने अपने ऑक्ट्राय खत्म किए हैं आप करें। लेकिन वो कन्टोनमैंट बोर्ड के इलाके में अपने ऑक्ट्राय दोबारा से लगाना चाहते हैं अगर कंटोनमैंट बोर्ड के इलाके में दोबारा ऑक्ट्राय लगाते हैं तो आप मानिये जो हमारा बाकी का सदर है वह सभी तरफ से कन्टोनमैंट से घिरा हुआ है। हमें हर जगह से उनके बैरियरों से निकलकर आना पड़ेगा। हमें तो दोहरी मार पड़ेगी। हमें आक्ट्राय भी या राहत आय भी देनी पड़ेगी। जहां हम आक्ट्राय के दायरे में भी रहेंगे और आक्ट्राय के ऐवज में जो ट्रेड टैक्स लगाया गया है हमें वह भी झेलना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : अनिल विज जी, मैं तो यह रिक्वैस्ट करूंगा कि अम्बाला छावनी दिल्ली छावनी की तरह सिंगल टायर होना चाहिए। दिल्ली में जहां कैंट एरिया है वहां पर कन्टोनमैंट बोर्ड-मैम्बर है, वहां पर नगर निगम के मैम्बर नहीं हैं। इसके बारे में तो मैं आपसे यह कहूंगा कि आप इस के बारे में अलग से डिमाण्ड करें जिसमें फायदा हो। दिल्ली में एक संस्था है, दो संस्थाएं नहीं हैं इस

तरह की बात आप मंत्री जी से अलग से डिस्कस कर लें।

श्री अनिल विज : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें डिसपैरिटी भी है। सड़क की एक ओर जो दुकानदार हैं उनसे हम ट्रेड टैक्स नहीं ले सकते हैं और सड़क की दूसरी तरफ जो दुकानदार हैं उनको ट्रेड टैक्स देना पड़ता है। बल्कि कुछ लोग तो अपने कारोबारों को बंद करके म्यूनिसपैलिटी से उठाकर कंटोनमैंट बोर्ड में शिफ्ट करने की सोच रहे हैं ताकि वे ट्रेड टैक्स से बच सकें। इसके बारे में मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि किसी भी एक शहर में दो तरह के टैक्स स्ट्रक्चर नहीं होने चाहिएं। सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने शहर की समस्याओं के बारे में कहना चाहूंगा। वैसे तो मैंने काफी क्वेशचंज भी दिए थे पर समझ नहीं आ रहा है कि वे क्यों नहीं लग पा रहे हैं। हमारे शहर में जो हर साल बाढ़ आती है वह बहुत ही तबाही करती है। बाढ़ को रोकने के लिए सरकार की तरफ से जो काम हो रहा है बाकी रह गया है सरकार इसकी ओर ध्यान दे। जो महेश नगर ड्रेन है उसके ऊपर बब्याल के पास डायवर्शन ड्रेन बनाने का मामला काफी देर से विचाराधीन है। उसका काम बीच-बीच में अटक जाता है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि उसकी तरफ शीघ्र ध्यान दे।

उपाध्यक्ष महोदय, अनाज मण्डी, सब्जी मण्डी और चारा मण्डी हमारे शहर से बाहर स्थानांतरित होनी हैं। नई मण्डी बननी है। अम्बाला छावनी सारे हरियाणा में एक ऐसा शहर होगा जहां कोई भी अनाज मण्डी बनाने की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी है मैं चाहता हूँ कि उसको इतनी तीव्र गति से किया जाए कि हम वहां पर ऐसा आश्वासन दे सकें कि अगले वर्ष अनाज मण्डी में काम शुरू हो जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्री जी इशारा कर रहे हैं मुझे पूरा भरोसा है कि वे जरूर इसमें गति प्रदान करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, तेपला के 220 के०वी० के एक सब-स्टेशन का काम तेजी से करने की आवश्यकता है क्योंकि हम घूलकोट के 220 के०वी० के सब-स्टेशन पर निर्भर हैं। उस पर अपनी निर्भरता समाप्त करने के लिए आवश्यक है कि तेपला का सब-स्टेशन जल्दी बने। हमारी कैनाल बेस्ड वाटर सप्लाई स्कीम शुरू होकर धीमी हो गई है। उस पर आज भी काम हो रहा है लेकिन धीमी गति से हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, आज वहां पर धन उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है। मेरे ख्याल से सरकार इसके बारे में ध्यान देगी।

उपाध्यक्ष महोदय, सिविल अस्पताल के बारे में भी हम यूरोपियन कमिशन के तहत आते हैं इसके बारे में भी सरकार ध्यान देगी।

हमारे जो जी०टी० रोड फोर लेनिंग है उस पर इंडियन ऑयल से लेकर महाराजा ढाबा तक एक सर्विस रोड को बनाया जाना चाहिए। मैं इसके बारे में पहले ही से कहता आ रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूं। सर्विस रोड का मतलब ही यही होता है कि जो लोकल ट्रैफिक होता है उसका हाई-वे पर कंजैशन न हो। उपाध्यक्ष महोदय, अब हम जो हुड्डा की कालोनियां बनाने जा रहे हैं वहां पर एक सर्विस रोड होनी बहुत जरूरी है। इंडियन ऑयल का डिपो जो कि शहर के बीचों-बीच आ गया है उनको वहां से हटाने के लिए कदम उठाने जरूरी हैं क्योंकि अगर कल को कोई दुर्घटना हो जाती है तो बाद में हम उस पर कोई इन्क्वायरी बिठाते फिरें उसका कोई लाभ नहीं होगा। हमें समय रहते ही इस बारे में कदम उठाने चाहिएं। कल को कोई दुर्घटना हो सारा शहर उससे तबाह हो सकता है। सारे इंडियन ऑयल, भारत पैट्रोलियम जी०टी० रोड पर शहर के बीचों बीच आ चुके हैं। इसके बारे में कम से कम मैं यह कहना चाहूंगा कि जिला स्तर पर उनकी ग्रीस का ऐनालाईज करवा लें अगर कल को

[श्री अनिल विज]

कोई दुर्घटना होती है तो कितना खतरा हो सकता है। अगर उससे कोई खतरा है तो लोगों की जिन्दगी से बढ़कर कोई चीज नहीं होती है। उसके लिए हमें कोई भी नुकसान उठाना पड़े तो उसको उठाना चाहिए। हमें उनको शहर से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह से सरकारी कॉलेज में भी अतिरिक्त भवन की आवश्यकता है। मैं चाहूंगा कि शिक्षा मंत्री महोदय इस तीन वर्ष पहले खुले सरकारी कॉलेज में यह काम करवाएं। इसी प्रकार से सरकार ने अपनी नयी इंडस्ट्रीज पोलिसी बनाई है। जहां तक साहा के इंडस्ट्रियल ग्रोथ सैंटर्ज की बात है मैं चाहूंगा कि दिल्ली से जो उद्योग हरियाणा में स्थानांतरित किए जा रहे हैं उनको केवल एन०सी०आर० तक ही सीमित न रखा जाए बल्कि उनको पूरे हरियाणा में स्कैटर करना चाहिए। अगर सरकार उनको केवल एन०सी०आर० तक ही सीमित रखेगी तो कहीं ऐसा न हो कि जो स्थिति आज दिल्ली की हुई है वही उस एन०सी०आर० की न हो जाये। इस तरह कुछ उद्योगों को साहा के इंडस्ट्रियल ग्रोथ सैंटर तक भी लाया जाना चाहिए। इस सैंटर के लिए चालीस एकड़ जमीन ऐक्वायर की जा चुकी है इसलिए अब वहां पर उद्योग स्थानांतरित किए जा सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो इससे अम्बाला शहर के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और विकास भी होगा। इसी प्रकार से मैं चाहूंगा कि गारबेज ट्रीटमैंट के लिए भी कोई पुख्ता नीति बनाई जानी चाहिए क्योंकि अम्बाला शहर और साहा के बारे में तो मुझे पता नहीं लेकिन अम्बाला कैंट में गारबेज ट्रीटमैंट की कोई व्यवस्था नहीं है। सारा मलबा शहर में से इकट्ठा करके शहर में ही डाल दिया जाता है जिससे वहां पर अनेक बीमारियों को निमंत्रण मिल रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : विज साहब, अब आप वाईंड अप करें।

श्री अनिल विज : सर, मैं पांच मिनट और लेना चाहता हूं। इसी तरह से हमें शहरों की ब्यूटिफिकेशन के लिए कोई न कोई नीति अपनानी चाहिए। वैसे तो सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है। हमारे शहर में सरकार ने नेता जी सुभाष चन्द्र बोस पार्क का निर्माण किया है और मुख्य मंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया है। यह पार्क शहर के बीचों-बीच बनाया जा रहा है मैं चाहूंगा कि इस पर और ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे जो शहीद हैं उनके प्रति सरकार का जो आदर है उसको मैं सैल्यूट करता हूं। कारगिल के शहीदों की भी सरकार ने बहुत सहायता की है। इसी तरह से शाहबाद में उधम सिंह जी का भी कार्यक्रम हुआ। अम्बाला कैंट में नेता जी सुभाष चन्द्र बोस की प्रतिमा बनाई गई और उसका अनावरण मुख्य मंत्री जी ने किया है। मैं सरकार की इस भावना का आदर करता हूं। लेकिन एक चीज और मैं कहना चाहता हूं जो कि अभी तक अछूती है। 1857 की क्रांति के बारे में जितने कागज मैंने देखे हैं या जो कुछ मैंने पढ़ा है उससे मुझे पता चला है कि यह क्रांति सबसे पहले मेरठ में मंगल पांडे द्वारा की गई क्रांति से भी दस घंटे पहले अम्बाला छावनी के कंटोनमैंट बोर्ड से आरंभ हुई थी। 68वीं इंफैंट्री ने बैरक छोड़कर क्रांति का ऐलान किया था। उपाध्यक्ष महोदय, यह क्रांति दस मई, 1857 को ही क्यों हुई। दस मई की तारीख ही इस दिन के लिए क्यों घोषित की गई। यह इसलिए क्योंकि दस मई को संडे था और इस दिन अम्बाला छावनी में नये चर्च का उद्घाटन होना था। सारे अंग्रेज ऑफिसर्ज उस दिन वहां पर इकट्ठे होने थे। इसलिए क्रांतिकारियों ने यह सोचा कि जैसे ही सारे अंग्रेज इकट्ठे होंगे वैसे ही हम उनको घेर लेंगे। इसी योजना के तहत 10 मई, 1857 को मेरठ में मंगल पांडे द्वारा की गई क्रांति के ऐलान से दस घंटे पहले प्रात: 9 बजे 68वीं इंफैंट्री ने अम्बाला छावनी में विद्रोह का ऐलान कर दिया और उस चर्च को घेर लिया। बाद में 12 बजे 5वीं इंफैंट्री भी इसमें शामिल हो गयी। मैं मुख्य मंत्री जी

से कहना चाहूंगा कि यह एक बड़ी राष्ट्रीय घटना है। इसलिए इसका अध्ययन होना चाहिए। ऐसे पुख्ता सुबूत भी मिले हैं कि किसी श्याम सिंह नाम के व्यक्ति ने पहले ही इस क्रांति के बारे में लीकेज कर दिया था, सी०आई०डी० कर दी थी जिसके कारण अंग्रेज इसको नियंत्रित करने में कामयाब रहे। 1857 की क्रांति की शुरुआत हमारे हरियाणा से हुई, अम्बाला छावनी से हुई, हमें इसके सारे सबूत एकत्रित करने चाहिएं और इसके लिए कोई न कोई समिति बनानी चाहिए। इस बारे में अधिकारियों को आदेश देने चाहिएं और अगर ये सारे तथ्य सामने आएं तो सरकार जैसा कि इतनी कृतसंकल्प है, दृढ़संकल्प है जो हमारे शहीद हैं, जिन्होंने हमारी आजादी के लिए और देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए अपना बलिदान किया तो हमें उनके लिए कोई न कोई स्मारक अम्बाला छावनी में जरूर बनाना चाहिए। यह एक राष्ट्रीय महत्व की बात होगी जो कि इतिहास के पन्नों से ओझल रह गई और हम उस तक नहीं पहुंचे। अब मैं सीवरेज के बारे में कहना चाहूंगा जैसा कि शहरों में और यहां तक कि छोटे कस्बों में भी सीवरेज डली हुई है लेकिन अम्बाला छावनी में 30 परसेंट भी सीवरेज नहीं डली हुई है। अम्बाला छावनी सुव्यवस्थित शहर था। वहां सीवरेज पूरी तरह से होनी चाहिए थी, लेकिन बजाय इसके जो सीवरेज डली हुई है, वह ठीक नहीं डली हुई है। उल्टी डली हुई है। मेरा निवेदन है कि पूरे अम्बाला कैंट में सीवरेज की व्यवस्था करनी चाहिए। ज्यूडीशियल कॉम्पलैक्स अम्बाला कैंट में था लेकिन एंटी रिजर्वेशन मूवमैंट के समय यह अम्बाला सिटी में चला गया जिसकी वजह से लोगों को बड़ी कठिनाई महसूस होती है, इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

श्री रामबीर सिंह (अनुसूचित जाति, पटौदी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो वित्त मंत्री जी द्वारा वर्ष 2001-2002 का जो बजट इस सदन में पेश किया गया है, उस पर मुझे आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी, मुख्य मंत्री जी और हरियाणा सरकार का इस बात के लिए आभारी हूं कि उन्होंने हरियाणा के लोगों के लिए टैक्स फ्री बजट दिया है और जिसका हरियाणा के हर निवासी ने स्वागत किया है, मीडिया ने स्वागत किया है, उद्योगपतियों ने स्वागत किया है और यह एक बहुत बढ़िया और स्वागत योग्य बजट है, मैं इसके समर्थन में बोलने के लिए प्रस्तुत हुआ हूं। सबसे पहले माननीय वित्त मंत्री जी ने गुजरात में जो त्रासदी हुई उसका जिक्र किया। उसके लिए हरियाणा सरकार ने जो मदद दी, उसके लिए मैं सरकार की सराहना करता हूं। हरियाणा सरकार ने इस त्रासदी में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और हरियाणा के निवासियों ने पीड़ित लोगों के लिए खुले दिल से जो योगदान दिया उसके लिए भी मैं आभार प्रकट करता हूं। मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा क्योंकि मैं स्वयंसेवक के रूप में वहां गया था। हरियाणा सरकार ने पहले रापर तालुका जो भुज जिले की तहसील है उसके 17 गांवों को गोद लिया था लेकिन जैसे-जैसे हरियाणा सरकार ने नियमबद्ध तरीके से वहां राहत कार्य शिविर चलाए तो उन्हें देखकर आसपास के गांवों के लोग इसरार करने लगे कि हरियाणा सरकार हमें भी ऐडोप्ट करे, उसके बाद दो गांवों को और लिया गया। हमारे विपक्ष के साथी कल इस बात पर ऐतराज कर रहे थे कि सरकार ने विपक्षी दलों को आमंत्रित नहीं किया, हम यह कहना चाहते हैं कि मैं भी वहां गया लेकिन मैं इसरार करके अनुरोध करके मुख्य मंत्री जी से इजाजत लेकर गया इन्वाइट नहीं किया गया। कोई त्रासदी जब आती है तो उसमें किसी को इन्वाइट नहीं किया जाता बल्कि वहां स्वयं-सेवक बनकर जाना पड़ता है। मैं एक बात यहां पर अवश्य बताना चाहूंगा कि वहां पर हम इंडियन नेशनल लोकदल के बैनर के साथ नहीं गये थे बल्कि हरियाणा सरकार की तरफ से और हरियाणा के निवासियों की तरफ से गये थे। जब हम वहां पर रापर से 80 किलोमीटर पहले राधनपुर पहुंचे तो हमें बड़ा अजीब नजारा वहां देखने को

[श्री रामबीर सिंह]

मिला। वहां पर एक पार्टी विशेष के झण्डे लगे हुए थे जैसे वहां कोई चुनाव प्रचार हो रहा हो। हमने जब उन लोगों से पूछा कि रापर कितनी दूर है तो उन्होंने हमें बताया कि रापर वहां से 200 किलोमीटर है। जो सदस्य वहां पर विरोध कर रहे हैं वे वहां पर जाकर देखें कि वे लोग किस दलदल में फंसे हुए हैं। हमने जो वहां पर शिविर लगाये थे उन में से किसी भी शिविर पर इंडियन नेशनल लोकदल के झण्डे नहीं लगे हुए थे। वहां पर हरियाणा सरकार के बैनर लगे हुये थे। वहां पर हरियाणा के लोग गये थे हरियाणा सरकार के अधिकारी वहां गये थे। हमारे माननीय स्पीकर साहब की अध्यक्षता में एक शिष्ट मंडल वहां गया था हमारे उपाध्यक्ष महोदय वहां गये थे। जिन लोगों ने वहां जाकर शिविर चलाया जब राशन कार्ड के जरिये हम किसी चीज को मुहैय्या कराते थे तो एक यूनिट बनाकर हम वहां पर काम करते थे जिस तरह से स्वयं-सेवक वहां काम करते हैं। हमने किसी पार्टी विशेष के रूप में वहां पर काम नहीं किया। वहां पर एडवर्टाइजमैंट करने हम नहीं गये थे। दो मिनट के लिये मैं वहां की चर्चा करना चाहूंगा। वहां के लोगों की ईमानदारी हमें देखने को मिली। जैसे किसी परिवार को हम कम्बल वगैरह देते थे और उस परिवार के आठ सदस्य हैं अगर दस कम्बल उनके पास चले जाते थे तो वे रात को दो कम्बल वापिस हमारे शिविर में दे जाते थे कि हमारे परिवार के तो आठ ही सदस्य हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आप तो वहां गये थे आपने देखा होगा कि वहां पर तीन साल से बरसात नहीं हुई है। कोई फसल वहां पर नहीं हो रही थी इतनी भुखमरी के बावजूद इतनी ईमानदारी हमें देखने को मिली। अगर एक चीज भी उन लोगों के पास फालतू चली गई तो वे हमारे शिविर में वापस दे गये। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार के बारे में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। इस सदन में 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के बारे में काफी चर्चा हुई। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि ये नहीं करते ये करते हैं। हमने गुजरात में देखा कि जितनी बिल्डिंग भू-कम्प से गिरी उनमें ज्यादातर सरकारी बिल्डिंग थी क्योंकि उनमें अच्छा मैटीरियल नहीं लगा हुआ था। हमारे मुख्य मंत्री जी ने जो विकास समितियां बनाई हैं वे इसलिए बनाई हैं कि सरकारी बिल्डिंग जो बने उनको चैक किया जा सके ताकि उनकी गुणवत्ता का ध्यान रखा जा सके कि सामान अच्छा परचेज कर रहे हैं या नहीं। यह सरकार की अच्छी सोच है जिससे जो भी सरकारी इमारतें बनेंगी वे मजबूत बन सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि सदन की यह परम्परा है कि जो आदमी सदन में मौजूद न हो उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिये। लेकिन हमारे माननीय मुख्य मंत्री 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के तहत हरियाणा के हर विधानसभा क्षेत्र में गये और लोगों की समस्याओं को सुना। लेकिन गुजरात में हम रापर एरिया में 15 दिन तक रहे, वहां का लोकल विधायक यह पूछने तक भी नहीं आया कि आप लोगों को क्या दिक्कत है, आप लोगों के साथ क्या बीती है और माननीय साथी 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जो गुजरात के उन 19 गांवों में स्वयं जाकर आये जो हरियाणा सरकार ने एडोप्ट किये थे लेकिन गुजरात का कोई भी मुख्य मंत्री या विधायक चाहे वह अब का हो या पहले रहा हो वहां पर एक दिन भी लोगों की तकलीफें पूछने नहीं आया। जबकि हमारी हरियाणा की जनता और अधिकारी वहां जाकर शिविर लगा कर उन लोगों की सेवा कर रहे हैं। मैं यहां पर गांधी जी का नाम अवश्य लेना चाहूंगा। गांधी जी के प्रदेश में एक चीज अवश्य देखने को मिली कि वहां की वेशभूषा से आप यह बता सकते हैं कि यह आदमी किस जाति विशेष का है। रैबारियों की अलग ड्रैस है और पटेल वालों की अलग ड्रैस है। लेकिन इस गुजरात की भीषण त्रासदी में जिस तरह से 19 गांवों को एडोप्ट करके हरियाणा सरकार ने वहां सहायता का काम किया है उसके लिए हरियाणा के मुख्य मंत्री, मंत्री, अधिकारी और हरियाणा के

निवासी धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं और आभार प्रकट करने के पात्र हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के बारे में यहां पर बड़ी बातें हो रही थीं। हमारे भाई कृष्ण पाल गुर्जर जी को पता नहीं क्या पीड़ा है यह तो मैं नहीं जानता क्यों कि पिछले दिनों पिछली सरकार में ये मंत्री के रूप में सरकार में शामिल थे, इन्होंने उस समय क्या-क्या बेकायदगियां की या नहीं की तथा क्या-क्या उल्टे सीधे काम किए, जिसका कि इनको डर है।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी पर्सनल एक्सप्लानेशन है कि मैंने कहा था कि यह हरियाणा के लोगों की पीड़ा है अगर यह मेरी व्यक्तिगत पीड़ा पर आरोप लगाना चाहते हैं तो इस बात की सी०बी०आई० से जांच करा लें।

श्री उपाध्यक्ष : कृष्ण पाल जी, आप बैठिए इससे ज्यादा बुरी बात क्या होगी, कि आपने अखबार को कोट किया। गुजरात में जो लोग या कर्मचारी गए उनको मैं जानता हूँ वे लोग अपना बिस्तर तक दे आए। उन लोगों ने सोचा कि हम इस बिस्तर को वापिस लेकर कहां जाएंगे, इसे किसी गरीब आदमी को दे देने से उसका काम चल जाएगा।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कहा था कि अखबार में जो छपा है पता नहीं वह सच है या नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : कृष्ण पाल जी, आप बैठिए क्योंकि अखबारों में तो पता नहीं क्या-2 छपता रहता है।

श्री रामबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अखबारों में जो छपता है, वह सारी सच्चाई नहीं होती। अखबारों में, टी०वी० में मरने वालों की संख्या बहुत कम बताई जाती है लेकिन असलियत में बहुत ज्यादा होती है। गुजरात में अगर आप स्वयं जाते तो आप देखते कि वहाँ लाखों लोग मरे हैं। अखबारों में सच्चाई नहीं होती है हमने वहां 50 आइटम बांटी और ऐसी-2 आइटम बांटी हैं जो लोगों ने देखी भी नहीं होंगी (शोर) उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम की इन्होंने आलोचना की और कहा लोकतंत्र पंगु हो गया है। हम यह कहते हैं कि जब से हरियाणा प्रदेश बना है, मैं तो यहां तक कहूंगा कि जब से देश आजाद हुआ है कोई भी विधान सभा हो चाहे पंजाब विधान सभा हो, मेरे पिता जी भी पंजाब विधान सभा में एम०एल०ए० रहे हैं पटौदी विधान सभा का एम०एल०ए० इस प्रदेश का मुख्य मंत्री भी रहा है, एक साल के अन्दर किसी भी प्रदेश की सरकार ने मुख्य मंत्री ने चाहे वह किसी भी पार्टी की सरकार के टाइम का हो, 20 करोड़ रुपये की योजनाओं को मंजूरी नहीं दी। ये तो लोकतंत्र को पंगु कहते हैं। जब मुख्य मंत्री किसी गांव में जाकर गांव के मुखिया से कहता है कि बताइए आपको क्या-क्या दिक्कतें हैं इससे लोकतंत्र को पंगु नहीं कहा जाएगा बल्कि मैं तो समझता हूं कि इससे लोकतंत्र बढ़ता है एक आम आदमी की पूछ इस सरकार में हुई है। इस सरकार ने सरकार और जनता के बीच की दूरी को कम किया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि कुछ साथी कह रहे थे कि विकास के कार्य नहीं हुए, उनको बताना चाहूंगा कि जब पहली बार 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम शुरू हुआ उस समय हरियाणा के किसी भट्टे पर भी ईंट नहीं थी, सारी ईंटें खत्म हो गई थीं क्योंकि गांव-2 में विकास के कार्य शुरू हो गए थे, गलियां और नालियां बनाई जा रही थीं। देश की आजादी के बाद से आज तक एक साल में इतने विकास कार्य नहीं हुए जितने अब हुए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, कई माननीय साथियों ने बिजली के बारे में भी बात की। इस बारे में मैं

[श्री रामबीर सिंह]

मुख्य मंत्री महोदय और हरियाणा सरकार का आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने 4-4 एम०ओ०यू० भारत सरकार से मंजूर करवाये हैं। इस बात के लिए मुझे ही नहीं बल्कि पूरे सदन को मुख्य मंत्री महोदय का आभार प्रकट करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आज के अखबार में सभी ने मुख्य मंत्री महोदय की स्टेटमैंट पढ़ी होगी कि आने वाले 2 सालों के अंदर हरियाणा में बिजली की कमी नहीं रहेगी और यहां से दूसरे राज्यों को भी बिजली दी जायेगी। जहां तक जल संसाधनों या सिंचाई की बात है, यह सब सदस्य जानते हैं कि पिछले दो सालों में वर्षा कम होने के कारण पानी की बहुत दिक्कत रही है लेकिन फिर भी पिछले साल खाद्यान्न में रिकार्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई और आने वाले साल में खाद्यान्न का उत्पादन पिछले साल से भी ज्यादा होने की संभावना है। यह बात सब सदस्य जानते हैं क्योंकि तकरीबन सभी किसान हैं और गांवों से बिलोंग करते हैं। वर्षा तो हुई ही लेकिन फिर भी इतनी अच्छी फसल हुई और यह हमारी सरकार द्वारा किसानों को उचित मात्रा में बिजली व नहरों का पानी देने के कारण ही हुई है। आज के दिन किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल लहरा रही है। जल-संसाधन में मैं एक मांग सरकार से करना चाहूंगा कि सालहावास लिफ्ट स्कीम, पौदा माईनर, लुहारी माईनर और गुगाना माईनर बनकर पूरे होने वाले हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हरियाणा सरकार से इन्हें जल्दी पूरा करवाने की सिफारिश करूंगा ताकि पटौदी में जहां भूमि के नीचे खारा पानी है वहां के लोगों को पीने का पानी और सिंचाई का पानी मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक सड़कों की बात है, सभी सदस्य जानते हैं कि दो साल पहले हरियाणा के अंदर सड़कों की बहुत बुरी हालत थी और आज के दिन बहुत अच्छी हालत माननीय मुख्य मंत्री जी ने करवा दी है। मुख्य मंत्री महोदय ने पूरे हरियाणा की सड़कों पर बिना भेदभाव के काम करवाया है। कांग्रेस के भाई राव धर्मपाल जी ने भी माना है कि आज के दिन हरियाणा के अंदर सड़कों की हालत अच्छी है और मौजूदा सरकार सड़कों की मुरम्मत करवा रही है। मैं हरियाणा सरकार का आभार प्रकट करूंगा कि गुड़गांव—सोहना—पलवल, गुड़गांव—पटौदी—रेवाड़ी और गुड़गांव—फरुखनगर—झज्जर इन चार सड़कों का काम दिन-रात में हो रहा है और बहुत अच्छी सड़कें आम नागरिक को उपलब्ध होंगी। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की तरफ से भी ग्रामीण सड़कों को बेहतर बनाने के लिए और नई सड़कें बनाने के लिए अच्छे निर्णय लिये गये हैं। पटौदी के अंदर मार्किट कमेटी ने इस साल 60 कि०मी० तक की सड़कें बनाने का निर्णय लिया है यह भी एक रिकार्ड है। आजादी के बाद आज तक इतनी ज्यादा कि०मी० की सड़कें किसी भी सरकार के समय में मार्किट कमेटी द्वारा अप्रूव नहीं हुई। पहले वाली सरकारों के समय में मार्किट कमेटी सिर्फ साल में 8 कि०मी० तक की ही सड़क बनवा सकती थी लेकिन हमारे यहां दो मार्किट कमेटी हैं उन्होंने पांच साल में एक कि०मी० सड़क भी नहीं बनवाई। लेकिन अब हमारी सरकार ने 60 कि०मी० की मंजूरी दे दी है। मंजूरी ही नहीं बल्कि सड़क बनने का कार्य शुरु हो गया है और 25 कि०मी० सड़कें पूरी हो चुकी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं परिवहन के बारे में विशेष तौर से चर्चा करना चाहूंगा। मैं सरकार और माननीय परिवहन मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने हरियाणा राज्य की सड़कों पर आदमियों की सुविधा के लिये 450 नई बसें उपलब्ध कराई हैं। इसके अलावा इस बजट में भी 100 नई बसें खरीद करने का लक्ष्य रखा गया है। इसलिए सरकार बधाई की पात्र है। इसके साथ-साथ मैं आपके माध्यम से सरकार का और विशेष तौर से माननीय परिवहन मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर भी

जरूर दिलाना चाहूंगा कि जिस तरह से राजेन्द्र सिंह बिसला जी ने एक प्रश्न किया था कि आगरा से दिल्ली के लिये डीलक्स बसें चलाई जायें, ठीक उसी तरह से दिल्ली और जयपुर के बीच में भी डीलक्स बसें चलाई जाएं क्योंकि जयपुर के लिए भी बहुत टूरिस्ट जाते हैं। इससे हरियाणा प्रदेश का राजस्व भी बढ़ सकेगा। उपाध्यक्ष महोदय, गुड़गांव आपका भी हल्का है और मैं आपके माध्यम से सरकार के सामने एक मांग रखता हूं कि गुड़गांव में एक आटो मार्किट बना दी जाए क्योंकि गुड़गांव बड़ी भीड़-भाड़ का इलाका है और वहां गन्दगी भी काफी रहती है। इसलिए अलग से एक आटो मार्किट भी जरूर बना दी जाए ताकि लोगों को गंदगी से छुटकारा मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष : इसके साथ-साथ मैं परिवहन मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि गुड़गांव का जो बस अड्डा है वह सबसे पुराना बस अड्डा है इसलिए जो दस लाख रुपये इस बस अड्डे के लिये रखे हैं उससे काम नहीं चलेगा। इसी तरह से तावडू में भी बस अड्डा बनाने के लिये चौधरी भजन लाल जी के समय में पत्थर रखा गया था उसका काम भी शुरू करवा दो। (विघ्न) पत्थर चाहे उन्होंने रखा हो तो भी उसका काम शुरू करवा दो इसमें भी आपका बड़प्पन होगा।

डॉ० रघुबीर सिंह कादयान : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो वही बात हुई कि अंधा बांटे रेवड़ी फिर-2 अपने-अपने को दे।

श्री रामबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को एक बात बताना चाहूंगा कि जैसा इन्होंने बोला कि अंधा बांटे रेवड़ी, फिर-2 अपने-अपने को दे वह बात गलत है। इन्हीं की पार्टी के ही एक सदस्य राव धर्मपाल जी के हल्के के अन्दर 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम में आठ करोड़ रु० से नौ करोड़ रु० की योजनाएं मन्जूर हुई हैं। ये लोग इस बात का जवाब देकर दिखा दें। (विघ्न) राव साहब को तो इसके लिए सरकार का धन्यवाद करना चाहिए।

राव धर्मपाल : उपाध्यक्ष महोदय, रामबीर जी ने मेरा पर्सनल नाम लिया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहूंगा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो काम हो रहे हैं उनको तो मानना ही पड़ेगा लेकिन जैसा माननीय सदस्य ने बताया कि मेरे हल्के में आठ-करोड़ रुपये की योजनाएं मन्जूर हुई हैं। अगर ऐसा है तो मुझे बता दें उसको भी मैं मान लूंगा।

श्री रामबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो रिकार्ड की बात है और मेरे पास इसके आंकड़े मौजूद हैं। (शोर)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से श्री रघुबीर सिंह कादयान की पुनः तसल्ली कराना चाहूंगा कि केवल बेरी विधान सभा क्षेत्र के अन्दर 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के तहत जो-जो काम हुए हैं उनको जरा ये नोट कर लें ताकि बाद में फिर कोई दिक्कत न आये। बेरी विधानसभा क्षेत्र में टोटल अमाउन्ट 4.83 करोड़ सैंक्शन हुआ और अमाउन्ट रिलीज़ भी 4.83 करोड़ हुआ है। स्कूली कमरों पर 1,07,20,000/- रुपये खर्च हुए, रिटेनिंग वाल पर 1,86,05,000/- रुपये खर्च हुए। (विघ्न) इसी तरह से गलियों के निर्माण पर 2,55,00,000/- रुपये खर्च हुए। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने प्रदेश के हर क्षेत्र में तरक्की की है। हर स्तर पर चाहे वह स्कूलों के कमरे बनाने की बात हो चाहे वह गांवों के जोहड़ों की रिटेनिंग वाल बनाने की बात हो और चाहे गांवों की गलियां पक्की करने की बात हो और चाहे सड़कें बनाने का मामला हो इस बारे में मैंने कल भी अलग से आपको बताया था वह इसके अतिरिक्त है। इसके बावजूद भी अगर आपकी तसल्ली नहीं होती है तो आपकी तसल्ली कौन करवाएगा, कैसे होगी उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता।

डॉ० रघुबीर सिंह कादयान : डिप्टी स्पीकर साहब, सदन के नेता ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ सड़कों का जिक्र किया (शोर)

श्री उपाध्यक्ष : सी० एम० साहब ने अब सड़कों का कोई जिक्र नहीं किया है। (शोर)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य को बेरी क्षेत्र की बातें बताई हैं।

डॉ० रघुबीर सिंह कादयान : डिप्टी स्पीकर साहब, अभी मुख्य मंत्री जी के द्वारा 4.83 करोड़ रुपये सड़कों के लिए दिया गया बताया है।

श्री उपाध्यक्ष : आपको जब बाद में बोलने के लिए मौका मिलेगा उस समय आप सड़कों के बारे में बोल लेना।

डॉ० रघुबीर सिंह कादयान : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपकी रूलिंग चाहूंगा कि जब बजट पर बहस चल रही हो और कोई माननीय सदस्य बोल रहा हो तो क्या मुख्य मंत्री या कोई मंत्री या पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर बीच में खड़े हो कर किसी बात का जवाब दे सकता है?

श्री उपाध्यक्ष : लीडर ऑफ दि हाउस बीच में इन्टरवीन कर सकते हैं और मंत्री भी कर सकते हैं।

श्री रामबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा सरकार का आभार प्रकट करता हूं कि राज्य सरकार ने रेवाड़ी और महेन्द्रगढ़ जिलों के फ्लोराईड प्रभावित क्षेत्रों में स्वच्छ जल आपूर्ति के लिए भारत सरकार की सहायता से दो परियोजनाएं आरम्भ की हैं। रेवाड़ी जिले के 129 गांव तथा महेन्द्रगढ़ जिले के 62 गांव इस परियोजना में शामिल हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि पटौदी ब्लॉक और फरूखनगर ब्लॉक को भी स्वच्छ आपूर्ति के लिए जो दो परियोजनाएं हैं उनमें शामिल किया जाए क्योंकि उन ब्लॉक्स में फ्लोराईडयुक्त पानी आता है। सरकार वहां पर कैनाल बेस्ड वाटर सप्लाई स्कीम का प्रबंध करने का आश्वासन दे ताकि वहां के लोगों को पीने का स्वच्छ पानी मिल सके। अगर सरकार वहां पर कैनाल बेस्ड वाटर सप्लाई स्कीम का प्रबंध करने के बारे में आश्वासन देती है तो वे गांव हैं मुसैदपुर, सचाना और छीलर। अगर इन गांवों में कैनाल बेस्ड वाटर सप्लाई स्कीम का प्रबंध कर दिया गया तो मैं इसके लिए सरकार का बड़ा भारी आभारी हूंगा। कई माननीय सदस्यों की तरफ से यह बात कही गई कि पानी की कमी है लेकिन मैं कहता हूं कि आप सभी लोग गांवों में घूमते हैं हर गांव में आप देखते हैं कि पीने का पानी गांवों की गलियों में बहता रहता है। हमारी संस्कृति रही है कि हमारे बुजुर्ग पीने के पानी के लिए पहले प्याऊ लगाया करते थे अब वे प्याऊ समाप्त हो चुके हैं क्योंकि हमारे पीने के पानी के जो साधन हैं पहले से बेहतर हैं। आप देखते हैं कि गांव के अन्दर जिस घर के आगे से पानी की पाईप लाईन जा रही है उसको काट कर उसमें मोटर लगाने का प्रयत्न किया जाता है जिससे उसके पड़ोसी को पानी न मिले। इस सोच को बदलने के लिए प्रयास किये जाने चाहिए। गांव में जो अवैध कनैक्शन हैं उनको कटवाने के लिए प्रयास किये जाने चाहिए। कृषि से संबंधित गतिविधियों के बारे में मैं अवश्य चर्चा करना चाहूंगा। मैं अपने सम्मानित मुख्य मंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला जी का विशेष तौर पर आभारी हूँ कि जब मिल्क प्रोडक्टस को यहां के लिए आयात करने की कोशिश की गई थी तो उस वक्त हरियाणा और पंजाब के किसानों को विशेष नुकसान होने की संभावना थी। मिल्क प्रोडक्टस के भाव उस वक्त कई गुणा डाउन आ गए थे। उस वक्त हमारे मुख्य मंत्री जी ने प्रधान मंत्री जी से

अनुरोध करके मिल्क प्रोडक्टस पर इम्पोर्ट टैक्स लगवाये। इसके लिए मैं अपने मुख्य मंत्री जी का आभारी हूं क्योंकि डब्ल्यू०टी०ओ० के कारण हमारे किसानों को जो नुकसान होना था उससे वे बच गए।

अब मैं अपने हल्के पटौदी के बारे में कुछ बातों पर चर्चा करना चाहूंगा। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि मेरे हल्के में ज्यादा बारिश न होने की वजह से अधिक बाजरा हुआ है जो पिछले 20 सालों में भी नहीं हुआ था। उसका कारण यह है कि सरकार ने किसानों को सही समय पर पूरी बिजली देकर उनके हितों का ध्यान रखा। यह जो हुआ है यह हमारी सरकार की बढ़िया पोलिसी के कारण ही संभव हो पाया है। (विघ्न) मैं एक बात अवश्य कहूंगा कि हमारे प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब कुरुक्षेत्र में आये तो उन्होंने हरियाणा के किसानों को इस बात के लिए प्रेरित किया था कि हरियाणा में गेहूं की फसल के अतिरिक्त कृषि से सम्बन्धित दूसरी उपजों की भी खेती करनी चाहिए। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे फरूख नगर में अब पटौदी के आसपास फूलों की खेती बहुत अधिक होती है। मेरी सरकार से मांग है कि वहां के लिए बागवानी का विशेष प्रबंध किया जाना चाहिए। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि गुड़गांव के अन्दर या फरूख नगर के अन्दर एक मार्किट बनायी जानी चाहिए जिससे वहां के किसानों को इस फसल के लिए सुविधा मिल सके और उनको अपने फूलों की फसल का उचित मूल्य मिल सके और वे उसे एक्सपोर्ट कर सकें। बजट में बताया गया है कि यहां पर 105 मण्डियां हैं, 189 उप मण्डियां हैं और 150 से अधिक खरीद केन्द्र हैं। मैं कृषि मंत्री जी का विशेष तौर पर आभारी हूं कि इन्होंने एक योजना लागू की जिसका नाम 'कृषक उपहार योजना' है। इस योजना के लागू होने से प्रदेश में जो 2 नम्बर का काम होता था वह बन्द हुआ है और हरियाणा के अन्दर मार्किटिंग बोर्ड से और एच०आर०डी०एफ० से जो पैसा आता था पहले से ज्यादा वसूली हुई है। इसी के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से औद्योगिक क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से दिल्ली से इण्डस्ट्रीज को निकाला गया है हो सकता है कि आने वाले समय में इन मण्डियों को भी दिल्ली से निकाला जायेगा। मैं हरियाणा सरकार से और कृषि मंत्री से विशेष तौर से अनुरोध करूंगा कि दिल्ली के आसपास की जो मंडियां हैं उनको इस हिसाब से तैयार किया जाये कि वे ट्रांजिट मण्डी के हिसाब की हों। बाहर साऊथ से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, राजस्थान या उत्तर प्रदेश आदि से जो माल आता है वह दिल्ली के आसपास की मण्डियों में डम्प हो और दिल्ली की जितनी आवश्यकता हो उस की इन मंडियों से पूर्ति की जाये।

पशुपालन के संबंध में सरकार ने जो हरियाणा में पशुधन विकास बोर्ड का गठन किया है और भैंसों की मुर्रा नस्ल को बनाये रखने का जो कार्यक्रम शुरू किया है उसके लिए मैं पशुपालन मंत्री व हरियाणा सरकार की सराहना करता हूं, लेकिन मैं एक बात की तरफ पशुपालन मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मेरे हल्के पटौदी के गांव जनोला, खरकड़ी, मोकलवास आदि में पशुओं के अन्दर एक अजीब तरह की बीमारी लग गई थी जिस कारण एक-एक गांव में 15-15 से लेकर 20-20 पशु मरे हैं। इस बारे में मैंने पशुपालन मंत्री जी से भी कहा था और माननीय मुख्य मंत्री जी से भी कहा था जिस कारण वहां पर एक टीम भेजी गई थी। मैं चाहूंगा कि इसकी जांच कराई जाये कि यह किस तरह की बीमारी है ताकि इसके लिए स्पेशल इंतजाम किये जा सकें और भविष्य में यह बीमारी दुबारा न लगे। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र के ये तीन गांव जिनका मैंने जिक्र किया है। ये मिल्क प्रोडक्शन में पहले और दूसरे नम्बर के गांव हैं। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि उन गांवों में डाक्टरों की एक विशेष टीम भेजी जाये जिससे वहां के पशुधन की रक्षा हो सके।

[श्री रामबीर सिंह]

मैं हरियाणा सरकार द्वारा अपनाई गई औद्योगिक नीति की सराहना करता हूं क्योंकि हरियाणा के मुख्य मंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने दिल्ली से जो इंडस्ट्रीज उठाई गई हैं उनको हरियाणा में स्थापित करने का प्रयास किया गया है। इस बारे में मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि गुड़गांव में मानेसर के आसपास के क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन कारखानों में बिहार, वैस्ट बंगाल, उड़ीसा के इलाकों के लोगों को नौकरी मिल जाती है जबकि हमारे यहां के लोकल युवकों को उनमें नौकरी पर नहीं लगाया जाता। इस बारे में मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि कोई ऐसा नियम बनाया जाये जिससे लोकल युवकों को वहां पर रोजगार अधिक से अधिक उपलब्ध कराया जा सके। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि बाहर के युवकों के यहां पर आने से हमारे यहां की लॉ एण्ड आर्डर की भी स्थिति बहुत खराब हो जाती है क्योंकि जो युवक यहां पर नौकरी के लिए आते है उनकी क्रिमिनल पृष्ठभूमि के बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता। जैसे राजेन्द्र सिंह बिसला जी ने पिछले दिनों एक बात कही थी कि लोग बाहर से यहां पर आ जाते है और यहां पर आते ही उनको फैक्टरीज के अन्दर नौकरियां मिल जाती हैं। वे वहां पर क्राईम करके भाग जाते हैं और उनका कुछ पता नहीं चलता है जिसके कारण लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति भी खराब होती है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि नौकरियों में ज्यादातर लोकल लड़कों को लगाया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, मारुति का उदाहरण आपके सामने है। मारुति में पीछे जो स्ट्राईक हुई थी तो उस समय जो हमारे लोकल लोग वहां पर लगे हुए थे उन्होंने मारुति उद्योग को चलाने का काम किया था। उन्होंने स्ट्राईक नहीं की थी और उन्हीं के कारण मारुति उद्योग चलता रहा। तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि लोकल लोगों को अवसर मिलना चाहिए और जो नये उद्योग लगाए जा रहे है उनमें ऐसा प्रबन्ध करना चाहिए ताकि लोकल लोगों को वहां पर नौकरियां मिल सकें। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक शिक्षा की नीति की बात है, शिक्षा नीति पर काफी प्रश्न भी आए। मैंने भी एक प्रश्न किया था जिसमें शिक्षा नीति की बात थी। माननीय शिक्षा मन्त्री को इस बात पर विचार करना चाहिए कि जिस प्रकार से सरकारी स्कूलों के लिए हाईकोर्ट के नॉर्म्ज हैं, वही नॉर्म्ज और नियम सब स्कूलों के लिए होने चाहिएं। सरकारी स्कूलों के लिए हाईकोर्ट के नॉर्म्ज और प्राईवेट स्कूलों के लिए कोई और नॉर्म्ज नहीं होने चाहिएं। प्राईवेट स्कूलों के अन्दर बहुत शोषण होता है। न वहां पर प्रोपर लैबोरेट्रीज होती हैं न प्रोपर लाईब्रेरीज होती हैं और न ही बच्चों के बैठने के लिए पूरे कमरे होते हैं इसके साथ ही साथ वहां पर अभिभावकों का पैसे के मामले में भी शोषण किया जाता है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो नॉर्म्ज सरकारी स्कूलों के लिए लागू किये गये हैं वही प्राईवेट स्कूलों के लिए भी लागू किये जाएं। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि शिक्षा नीति में परिवर्तन की बहुत जरूरत है। हम गुजरात के अन्दर गए और वहां देखा कि वहां पर स्कूल पंचायतों को दिये हुए हैं। हमारे साथी कहते हैं कि स्कूल पंचायतों को दे देने से कुछ नहीं होगा। गुजरात में पंचायतें स्कूलों में इम्पलाईज लगाती हैं और पंचायतें उन्हें चैक भी करती हैं कि मास्टर स्कूल में आए या नहीं आए और अगर वे न आए तो उनकी एब्सैंट भी लगाती हैं और उनकी कार्य प्रणाली भी चैक करती हैं। यह सिस्टम बहुत बढ़िया है। मिडल स्कूलों तक का प्रबन्ध पंचायतों को दिया जा रहा है और मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आजकल हमारे पास शिक्षा के पांच छः स्तर हैं। प्राइमरी स्कूल, मिडल स्कूल, हाई स्कूल, सीनियर सैकण्डरी स्कूल और फिर कॉलेजिज, मैं यह चाहता हूं कि इसमें कुछ परिवर्तन किया जाए। मिडल स्कूल तक एक स्तर रखा जाए, मिडल से सीनियर सैकण्डरी स्कूल तक एक स्तर रखा जाए और कॉलेज का स्तर अलग किया जाए। इससे प्रशासनिक और शिक्षा के स्तर

को स्ट्रैंथन करने में सहायता मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं समाज कल्याण की बात विशेष रूप से करना चाहता हूँ। सरकार ने अनुसूचित जातियों के वजीफे को जो दुगना किया है उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ और इसके लिए हरियाणा सरकार का आभार प्रकट करता हूँ। अनुसूचित जातियों के लिए भवन निर्माण के लिए अनुदान राशि 5000 रुपये से बढ़ा कर 10 हजार रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है उसके लिए भी मैं हरियाणा सरकार का आभारी हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा, एक साथी ने कहा कि कन्यादान की योजना एक ढकोसला है। मैं हरियाणा की बात नहीं करता, मैं इस देश की बात नहीं करता। विश्व के किसी भी देश या प्रदेश में ऐसी कोई परियोजना नहीं है कि किसी गरीब हरिजन की बेटी की शादी हो और सरकार की तरफ से 5100/- रुपये का कन्यादान दिया जाए। मैं हरियाणा सरकार की प्रशंसा करता हूँ कि माननीय चौधरी देवी लाल जी के नेतृत्व में उनकी नीतियों पर चलते हुए हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह योजना लागू की जिससे गरीब आदमी को बहुत फायदा होता है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं वृद्धावस्था पैंशन की बात करता हूँ। जिनके पास जमीन है, जिनके पास दुकान है, जिनके पास प्रोपर्टी होगी, जो लोग सरकारी नौकरियों में लगे हुए हैं उनको शायद 200 रुपये से कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं, उस गरीब बुजुर्ग मां की सोचिए जिसके पास आय का कोई साधन नहीं है उस परिवार में दो-सौ जमा दो-सौ 400/- रुपये घर में आते हैं तो उससे उसको बहुत फर्क पड़ता है तथा इससे गरीब आदमी को फायदा होता है। मैं इसके लिए सरकार की सराहना करता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, वित्तमंत्री जी ने जो बजट पेश किया है मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। गुड़गांव में जो लॉ-कालेज मुख्य मंत्री जी के और उपाध्यक्ष महोदय के प्रयासों से खुला है, उसके लिए मैं इनकी प्रशंसा करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। यहां पर स्पोर्ट के बारे में बातें कहीं जा रही थी कि स्पोर्ट नाम की कोई चीज नहीं है। निशान सिंह जी कह रहे थे हमारे बच्चे क्रिकेट खेलने लग गए थे और जो हमारे प्रादेशिक खेल जैसे कि कब्बड्डी, वालीबाल वगैरह थे उनको भूल ही गए थे। इस सरकार के प्रयास से हमारे प्रदेश में नैशनल वालीबाल चैम्पियनशिप का आयोजन किया गया, यह बहुत ही प्रशंसनीय बात है। (विघ्न) मैं अभय चौटाला जी का धन्यवाद करता हूँ जिनकी अध्यक्षता में प्रदेश ओलम्पिक संघ में खेलों को ज्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जब ओलम्पिक हो रही थी तो हमारी तो 100 करोड़ की आबादी वाले देश के लोगों की नजर मैडल की तरफ थी लेकिन कोई मैडल ही नहीं नजर आ रहा था हमने तो मोटे-मोटे चश्में लगा लिए थे लेकिन कोई मैडल नजर नहीं आ रहा था। मैं धन्यवाद करता हूँ मुख्य मंत्री जी का जो इन्होंने मैडल जीतने वाले को 25 लाख रुपये और 50 लाख रु० देने की घोषणा की। सारे देश में से सिर्फ कर्णम मल्लेश्वरी ने एक मात्र कांस्य पदक जीता। मैं उसके लिए हरियाणा सरकार को और मल्लेश्वरी जी को बधाई देता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी सदस्यों को कहना चाहूंगा कि ऐसे अच्छे बजट को एक मत होकर पास करें। धन्यवाद।

डॉ रघुबीर सिंह कादयान : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। उपाध्यक्ष महोदय, जब यहां पर बहस चल रही थी तो उस वक्त भू-कम्प के लिए सहायता से सम्बन्धित छपी अखबार में खबर की बात की गई तो रामबीर सिंह जी ने कहा था कि अखबार वाले कुछ भी लिख देते हैं। मैं इन को बताना चाहूंगा कि अखबार और मीडिया वाले फोरथ स्तम्भ होते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो शब्द कहे थे वे कार्यवाही से निकाल दिए जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इनसे यह पूछना चाहूंगा कि अखबारों में और टी०वी० में यह लिखा और दिखाया गया था कि वहां पर 15 हजार लोग मरे हैं तो क्या ये सोचते हैं

[श्री रामबीर सिंह]

कि वहां पर 15 हजार ही लोग मरे होंगे। मैं भी मीडिया का सम्मान करता हूँ। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : अब डॉ० राम कुवार सैनी जी बोलेंगे।

डॉ० राम कुवार सैनी (गोहाना) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोले के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, 26 जनवरी को गुजरात में जो भू-कम्प आया था वह इस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी रही है। जिसके अन्दर हजारों लोग मर गए थे और लाखों लोग जख्मी हो गए थे। मैं मुख्य मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ कि गुजरात में जब भू-कम्प आया था तो वहां पर बहुत त्रासदी हुई थी तो हरियाणा सरकार की तरफ से, कई संस्थाओं की तरफ से वहां पर लोगों की मदद की गई। वहां पर मशीनें भेजी गई जिनसे वहां पर दबे हुए लोगों को निकाला गया, वहां पर दवाएं भेजी गई, खाने-पीने की वस्तुएं भेजी गई और लोगों को पहनने के लिए कपड़े दिए गये। हरियाणा सरकार ने वहां पर 19 गांवों को अपनाया और उन्हें जरूरत की चीजें मुहैया करवाईं। इस कार्यवाही से हरियाणा का नाम संसार के मानचित्र पर आया है। आज सारे देश में हरियाणा सरकार की इस काम के लिए भूरी-भूरी प्रशंसा की जा रही है। मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूँ कि उनके इस कदम ने सारे देश में हरियाणा का नाम ऊंचा किया है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि वर्तमान सरकार ने अपने 19 महीने के समय के शासनकाल में जो विकास कार्य किए हैं वे सराहनीय कार्य रहे हैं। ये सारे कार्य हरियाणा के उज्ज्वल भविष्य के प्रतीक हैं। हमारी सरकार ने एक नयी शिक्षा नीति, औद्योगिक नीति लागू की है जिससे हरियाणा में एक नये समाज का सूत्रपात हुआ है, आदरणीय श्री ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा के नव निर्माण में लगे हुए हैं। जब उन्होंने कुर्सी संभाली थी तो उस समय राज्य की हालत खस्ता थी और राज्य का खजाना खाली था। पूरे राज्य में शराब माफिया और अपराधी किस्म के लोग पनप चुके थे, इन सब पर काबू पाने का श्रेय हमारी सरकार को ही जाता है। आदरणीय चौटाला साहब ने चौधरी देवीलाल जी के आदर्शों तथा स्वप्नों को लोगों के समर्थन से साकार करने का संकल्प लिया है इससे हरियाणा राज्य को एक नयी दिशा मिलेगी। आज हमारी सरकार ने हरियाणा के गांव-गांव एवं शहरों तथा कस्बों में विकास के कार्य शुरू करवाए हैं। हमारी सरकार ने 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के तहत जनता के घर-घर जाकर विकास के कार्य करवाए हैं। इसी तरह से पंचायती राज संस्थाओं को प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार दिए गए हैं। इसी प्रकार से हमारी सरकार ने ग्राम विकास समितियों का गठन करके एक सराहनीय कार्य किया है इससे हरियाणा राज्य को एक नयी दिशा मिली है। इसी तरह से हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी बेरोजगारी को दूर करने के लिए भी प्रयत्नशील हैं। उन्होंने सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को दूर करने का प्रयास भी किया है। इसलिए ऐसे मुख्य मंत्री की जितनी भी सराहना की जाए वह कम ही है। इसी तरह से चाहे वह टेल पर पानी पहुंचाने की बात हो, चाहे किसान को बिजली देने की बात हो या चाहे ट्यूबवैल्ज़ को कनैक्शंज देने की बात हो, हमारी सरकार ने सराहनीय काम किया है। हमारी सरकार शिक्षा के प्रति भी जागरूक है इसलिए हमारी सरकार ने नयी शिक्षा नीति लागू की है। अब हरियाणा में कम्प्यूटर की शिक्षा तथा पहली कक्षा से अंग्रेजी पढ़ाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। इस तरह से हमारी सरकार ने शिक्षा के माध्यम से हरियाणा को एक नयी दिशा दी है। इसी तरह से परिवहन के बारे में भी मैं कहना चाहूंगा। पिछली सरकार के समय में सारी बसिज़ के शीशे वगैरह तोड़ दिए गए थे सारी बसिज़ जर्जर हो चुकी थीं लेकिन हमारी सरकार ने इन बसिज़ को बदलने का भी काम किया

16-00 बजे

है जिसके लिए हमारे परिवहन मंत्री एवं मुख्य मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। उपाध्यक्ष महोदय, पहले हरियाणा में बिजली की बहुत कमी थी। कभी बिजली आती थी तो कभी जाती थी और कभी-कभी तो बिल्कुल भी बिजली नहीं आती थी। इस प्रकार हरियाणा की बहुत बुरी हालत थी।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के समय में पूरी बिजली मिलती है। जिंदल साहब ने बोलते हुए कानून और व्यवस्था की बात कह दी वे कह रहे थे कि व्यापारियों को धमकियां दी जाती हैं, फिरौती की मांग की जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार के समय कितने अपहरण हुआ करते थे, ये अपना वक्त भूल गए हैं। आज कानून और व्यवस्था की बात करते हैं उस समय जिन लोगों का अपहरण हो जाया करता था, उनको फिरौती देकर ही छुड़ाया जाता था और ये लोग यहां बैठकर कानून और व्यवस्था की बात करते हैं, अपना वक्त याद करो। अपना वक्त किसी को याद नहीं आता है पिरथला कांड की याद करो, द्रोपदी कांड की याद करो, रेणुका कांड की याद करो। लड़कियों का अपहरण होता था उनके साथ बलात्कार किया जाता था फिर उनको मार दिया जाता था, भूतमाजरा कांड की याद करो, अम्बाला में सतिन्द्र सेखों कांड की याद करो। फरीदाबाद के नगर परिषद के अध्यक्ष को मार दिया गया था। वर्तमान सरकार के समय में कोई कांड नहीं हुआ है। आज कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत ही अच्छी है और इसके लिए यह सरकार बधाई की पात्र है, आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं और उनकी जितनी भी सराहना इसके लिए की जाए वह कम है। हमारे विपक्ष के साथी यहां बैठकर कहते है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब है। यह उनके लिए बड़े शर्म की बात है। छाज तो बोले छलनी भी क्या बोले जिसमें सौ सुराख हों। यहां पर एस०वाई०एल० नहर का जिक्र चला था, बंसी लाल जी इस समय बैठे नहीं है लेकिन सच्चाई कहे बगैर मैं नहीं रहूंगा। बंसी लाल जी मुख्य मंत्री होते थे और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी और केन्द्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और उस समय उग्रवाद भी नहीं था फिर उस समय एस०वाई०एल० का काम क्यों नहीं किया गया? उस समय जो एस०वाई०एल० नहर पर काम किया गया, वह उल्टी तरफ से किया गया जिससे सारे हरियाणा की उपजाऊ जमीन खराब हो गई। उस समय अगर एस०वाई० एल० नहर खोदकर हरियाणा में ला देते तो हरियाणा प्रदेश की सारी समस्याएं, सारी रुकावटें मिट जातीं। उपाध्यक्ष महोदय, बिजली के लिए यह सरकार वचनबद्ध है और जहां तक पानी की बात है पानी के बारे में सब लोग जानते हैं कि वह एस०वाई०एल० के जरिए आएगा। हमारे विपक्ष में बैठे नेताओं ने इस प्रकार सारे हरियाणा की जनता के हितों के साथ कुठाराघात किया है। एस०वाई०एल० नहर के समझौते पर आदरणीय चौधरी भजन लाल जी ने जाकर साईन करके हरियाणा की जनता के साथ कुठाराघात किया था (शोर एवं व्यवधान) और आज वे किसानों के हितैषी बनते हैं। चौधरी देवीलाल जी जब भारत के उप-प्रधानमंत्री थे और केन्द्र में श्री चन्द्रशेखर जी की सरकार थी उस समय माननीय चौधरी देवीलाल जी मेरे हल्के गोहाना में आये थे और उन्होंने गोहाना में एक शूगर मिल लगाने के लिये घोषणा की थी। लेकिन दुर्भाग्य से लोकसभा भंग हो गई और लोकसभा के चुनाव डिक्लेयर हो गये थे और आचार संहिता लागू हो गई थी उस बात का फायदा उठाकर चौधरी भजन लाल जी ने चुनाव आयोग को इस बारे में शिकायत कर दी कि चौधरी देवीलाल जी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है इसलिए वह शूगर मिल गोहाना में नहीं लग सकी और उस शूगर मिल को अपने एरिया में ले गये। उन्होंने किसानों के हितों के साथ कुठाराघात किया है और आज वे किसानों के हितैषी बनते हैं। वे तो किसानों के पेट पर लात मारने वाले हैं और आज वे हमारे बीच बोलने की बात करते हैं (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सैनी साहब, आप वाईंड-अप कीजिये।

चौधरी भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, सैनी साहब की लय टूट जायेगी।

डॉ० राम कुवार सैनी : इनको अपना समय याद नहीं आता इनके समय में टोहाना कांड, नीसिंग कांड और मण्डीयाली कांड आदि हुए थे। इन्होंने किस तरह किसानों को गोलियों से भुनवा दिया था, उन किसानों का क्या कसूर था? किसान अपना हक मांगने के लिए प्रदर्शन भी कर सकते हैं जुलूस भी निकाल सकते हैं। उनकी समस्या का समाधान ट्रांसफार्मरज बदलकर भी किया जा सकता था लेकिन पुलिस के हाथों निहत्थे किसानों को गोलियों से भुनवा दिया था, सैकड़ों किसान जख्मी हुये थे, कुछ अपना स्थान छोड़कर चले गये थे और 7-8 दिनों तक उनका पता नहीं चल सका था कि कहां पर गये हैं। इस प्रकार किसानों पर बड़ा कहर ढाया गया था और आज विपक्ष के साथी किसानों के हितैषी बनते हैं। आज ये एस०वाई०एल० नहर के निर्माण की बात करते हैं, कानून व्यवस्था की बात करते हैं, आज प्रदेश की जनता समझ गई है कि कौन जनता का हितैषी है और जनता अपने आप यह फैसला कर देगी। उपाध्यक्ष महोदय, जनता जनार्दन की भावनाओं की कद्र करते हुए मैं बजट का हार्दिक समर्थन करता हूँ, धन्यवाद।

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : डिप्टी स्पीकर सर, चौधरी भजन लाल जी ने कहा कि सैनी साहब की लय टूट जायेगी।

चौधरी भजन लाल : मैंने यह कहा था कि बीच में टोका टाकी न करो इनकी लय टूट जायेगी पता नहीं आप ये****** कहां से ले आये।

श्री उपाध्यक्ष : यह अनपार्लियामैंटरी शब्द कार्यवाही से निकाल दिया जाये। चौधरी भजन लाल जी आप जैसे नेता के लिए ऐसे शब्द कहना शोभा नहीं देता।

चौधरी भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो यह बढ़िया चीज के लिए कहा था अगर आपको ठीक नहीं लगा तो मैं यह शब्द वापस लेता हूँ।

प्रो० सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी भजनलाल जी को ऐसे नहीं कहना चाहिये था। माननीय सदस्य इनकी सरकार का इतिहास बताकर इनको याद करवा रहे थे और इनकी अचीवमैंट्स बता रहे थे। मैं माननीय सदस्य को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : आप सभी बैठें। अब श्री तेजवीर सिंह जी बोलेंगे।

श्री तेजवीर सिंह (पुण्डरी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया। मैं प्रो० सम्पत सिंह जी का बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने वर्ष 2001-2002 का जो कर रहित बजट प्रस्तुत किया है वह बहुत अच्छा है। सारे हरियाणा प्रदेश में और दूसरे प्रदेशों में भी इस कर रहित बजट की पूरी सराहना हुई है। मीडिया के लोगों ने भी इसे सराहा है। हमारी सरकार पिछले 18 महीनों से पूरी तरह से हरियाणा की उन्नति और तरक्की के लिए प्रयासरत है अभी पीछे 26 जनवरी को जो गुजरात में भू-कम्प आया है, मैं समझता हूँ कि देश के अन्दर यह सबसे बड़ी त्रासदी हुई है। इस त्रासदी में हरियाणा के लोगों ने वहां जाकर पीड़ित लोगों की जो सेवा की है उससे हरियाणा की पूरे देश में बड़ी प्रशंसा हुई है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय के नेतृत्त्व में हरियाणा सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है। हरियाणा सरकार ने, हरियाणा सरकार के मंत्रियों ने, हरियाणा सरकार के आफिसर्ज ने, हरियाणा प्रदेश की जनता ने जो

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

पैसा देकर वहां के 19 गांवों में जो राहत कार्य किए हैं। मैं समझता हूँ कि यह बहुत ही पुण्य का काम है जो हरियाणा सरकार ने किया है। जब 24 जुलाई को सरकार बनी थी उस समय मुख्य मंत्री महोदय ने 'सरकार आपके द्वार कार्यक्रम' को चलाया था। मुख्य मंत्री महोदय ने सभी हल्कों में जाकर हल्कों के सभी गांवों की पंचायतों की समस्याएं सुनीं, उनकी मांगों को स्वीकार किया, यह बहुत ही अच्छा कार्य किया है। इस बार भी 2 अक्तूबर को माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने दोबारा 'सरकार आपके द्वार कार्यक्रम' के दूसरे चरण को शुरू किया जिसके अन्दर उन्होंने तालाबों की रिटेनिंग वाल के निर्माण के लिए, स्कूलों के कमरों के निर्माण के लिए, गलियों के निर्माण के लिए, पशु चिकित्सालयों के निर्माण के लिए पैसा दिया। अस्पतालों के लिए सरकार ने पैसा दिया। इसी तरह से हरियाणा के गांवों के लोगों की समस्याएं थीं, मांगें थीं, मुख्य मंत्री महोदय ने सभी मांगों को पूरी संख्या में मंजूर करके बहुत अच्छा काम किया है। उपाध्यक्ष महोदय, दूसरे राज्यों के मुख्य मंत्री भी इस प्रकार 'सरकार आपके द्वार कार्यक्रम' के नक्शे कदम पर चलते हुए इसके बारे में सोच रहे हैं कि जिस तरह से हरियाणा में यह कार्यक्रम सफल हो रहा है उसी तरीके से हम भी अपने राज्यों में इस कार्यक्रम को चलाएं। जहां तक बिजली की बात है तो हमारी सरकार ने बिजली की व्यवस्था बड़े अच्छे ढंग से, पूरी कोशिश करके लगभग 50 लाख यूनिट बिजली औसतन प्रतिदिन बिजली की वृद्धि की है। इस साल वर्षा बहुत कम आई थी लेकिन फिर भी फसल का एक रिकार्ड उत्पादन हुआ है। यह इसी वजह से हुआ है कि सरकार की एक अच्छी नीति रही है और पूरी तरह से बिजली सरकार ने कोशिश करके सप्लाई की है जिस वजह से इतना उत्पादन हुआ है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कोशिश करके प्रधान मंत्री महोदय से 3 गैस बेस्ड 500 मैगावाट के पावर स्टेशन हरियाणा प्रदेश के लिए मंजूर करवाए हैं, यह भी बहुत बड़ी बात है। आने वाले दिनों में जब ये पावर स्टेशन बनकर तैयार हो जाएंगे तो हरियाणा में बिजली काफी मात्रा में उपलब्ध हो सकेगी। इसी तरह से जहां तक कानून और व्यवस्था की बात है तो राष्ट्र का क्राइम रेट, हमारे हरियाणा प्रदेश के अन्दर बहुत कम है। कानून और व्यवस्था की स्थिति हमारे प्रदेश में बहुत अच्छी है। उपाध्यक्ष महोदय, आज नये-नये उद्योग हरियाणा प्रदेश में आ रहे हैं। यदि वहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं होती तो कौन उद्योगपति वहां पर उद्योग लगाने के लिए तैयार होता। दिल्ली से जितने भी उद्योग विस्थापित हुए हैं उनको हरियाणा प्रदेश की सरकार ने हरियाणा में स्थापित करने के लिए जमीन आबंटित कर दी है यह बहुत ही अच्छा कार्य है। हरियाणा सरकार ने अपनी नई औद्योगिक नीति-2001 बनाई है जिससे उद्योगों को काफी फायदा होगा।

शिक्षा के क्षेत्र में भी हरियाणा सरकार ने नई शिक्षा नीति बनाई है जिसके तहत पहली कक्षा से ही स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ाई जायेगी। इससे गांव के बच्चों को भी अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने का मौका मिलेगा और उनकी अंग्रेजी सुधरेगी और आज के कंपीटीशन के युग में वे अपने को कंपीट कर पायेंगे। इसके अतिरिक्त हरियाणा सरकार ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी नीति बनाई है ताकि हरियाणा के लोग भी इस बदलते हुए परिदृश्य में किसी से पीछे न रह जायें और पूरी तरह से दुनिया के साथ चल सकें। उपाध्यक्ष महोदय, परिवहन के क्षेत्र में भी हमारी सरकार ने बड़े ही सराहनीय कार्य किए हैं और अच्छे कदम उठाये हैं। यह सब माननीय मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में ही हुआ है। परिवहन विभाग ने लगभग 1100 बसें न्यू खरीदने का निर्णय लिया है जिसमें से लगभग 450 बसें खरीदी जा चुकी हैं और आने वाले साल में शेष बसें खरीदी जायेंगी ताकि पुरानी बसों को बदला जाये और जनता को सुविधा हो। इसके अतिरिक्त बसों के नये रूट भी बनाए गए हैं ताकि लोगों को समय पर बस उपलब्ध हो और असुविधा न हो।

[श्री तेजवीर सिंह]

उपाध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण के क्षेत्र में भी हमारी सरकार ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। जो अनुसूचित जाति और जनजाति की लड़कियां जिनकी शादी 18 साल की होने के बाद की जाती है उनको कन्यादान के रूप में 5100 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाते हैं यह बहुत ही अच्छी बात है। इसके अतिरिक्त बुजुर्गों को, विडोज को और विकलांगों को सम्मान देने के लिए मुख्य मंत्री महोदय ने उनकी पैंशन 100 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये कर दी इसके लिए मैं मुख्य मंत्री महोदय को बधाई देता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य मंत्री महोदय और हरियाणा ओलम्पिक संघ के प्रधान श्री अभय चौटाला जी ने खेलों को भी बहुत बढ़ावा दिया है। अभय चौटाला जी के प्रयासों के कारण ही हरियाणा प्रदेश में कई जगह नये-नये खेल कम्पलैक्स खोलने के लिए सैंटर की सरकार से मंजूरी करवाई गई है और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। कर्णम मल्लेश्वरी को हमारी सरकार ने ओलम्पिक में पदक जीतने पर 25 लाख रुपये इनाम के तौर पर दिये और इससे दूसरे खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा और वे भी पदक जीतने के लिए पूरे प्रयास और मेहनत करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट का पूरी तरह से समर्थन करता हूं और अपनी पुण्डरी हल्के की कुछ समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आपके माध्यम से दिलाना चाहूंगा। हमारे पुण्डरी क्षेत्र में 1996 में गांव पबनावा के अन्दर पोलिटैक्निक मंजूर हुई थी लेकिन अभी तक उसका कोई काम शुरू नहीं हुआ है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जल्दी ही इस पोलिटैक्निक का काम शुरू करवाया जाए ताकि वहाँ के लोगों को भी टैक्निकल एजुकेशन की सुविधा प्राप्त हो सके। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पुण्डरी क्षेत्र के गांव रसीना में एक पी०एच०सी० बननी थी जो कि 1994 में मंजूर हुई थी। इसकी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू भी हुआ था लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है, यह काम अधूरा पड़ा हुआ है। मैं आप के माध्यम से मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस का काम भी जल्दी पूरा करवाया जाए क्योंकि लम्बे समय से इसका काम अधूरा पड़ा हुआ है। इसके बाद मैं पुण्डरी क्षेत्र की सड़कों की हालत के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। उपाध्यक्ष महोदय, पी०डब्ल्यू०डी० और मार्किटिंग बोर्ड के अंतर्गत आने वाली पुण्डरी क्षेत्र की सड़कों की भी खस्ता हालत है इसलिए मेरा आप के माध्यम से मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है कि जल्दी ही पुण्डरी क्षेत्र की मार्किटिंग बोर्ड और पी०डब्ल्यू०डी० के अंतर्गत आने वाली सड़कों की रिपेयर कराई जाए ताकि लोगों को होने वाली असुविधा से छुटकारा मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से ढांढ में एक बस स्टैण्ड बनाने की बात थी जिसके लिए मैंने क्वैश्चन भी उठाया था और यह क्वैश्चन आया भी था कि ढांढ में एक बस स्टैण्ड का निर्माण करवाया जाए। पुण्डरी हल्के में ढांढ और पुण्डरी कस्बे हैं। पुण्डरी में तो बस स्टैण्ड है लेकिन ढांढ भी एक बड़ा कस्बा है वहां पर कोई बस स्टैण्ड नहीं है जबकि वहां पर लड़कियों का एक कॉलेज भी है जहां 1000 लड़कियां पढ़ती हैं। इस बस स्टैण्ड के बनने से उन लड़कियों को भी काफी सुविधा हो जाएगी। इसके साथ-साथ लोगों को भी काफी सुविधा होगी। इसलिये यह बस स्टैण्ड बनाया जाना जरूरी है। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से यह भी गुजारिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी ढांढ कस्बे में बस स्टैण्ड बनवाया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, पुण्डरी में 1993 से एक बी०एड० कॉलेज चल रहा है जो लोगों ने चन्दा इकट्ठा करके चला रखा है। हम पिछले आठ वर्ष से इस कॉलेज को चला रहे हैं माननीय मुख्य मंत्री जी जब 31 अगस्त को हमारे हल्के में आये थे तो उन्होंने घोषणा की थी कि बी०एड० कॉलेज को सरकारी ग्रान्ट देंगे। इसके बारे में मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से दोबारा दरखास्त

करना चाहूंगा कि इस बी०एड० कालेज को सरकारी ग्रान्ट दी जाए। हमारे हल्के में भी अभी 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम होना है। शायद इसी महीने में या अगले महीने में हमारे हल्के का नम्बर आएगा इसलिए मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के तहत हमारे हल्के की भी ज्यादा से ज्यादा समस्याओं को दूर करें और इस हल्के की मांगों को भी स्वीकार करें। उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं आप सब का धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं।

चौधरी भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, हमने आज के लिए कांग्रेस पार्टी के जिन सदस्यों के नाम दिये हुए हैं उसी के मुताबिक ही नम्बर वाइज़ सदस्यों को बोलने का मौका दें। आज की लिस्ट में दूसरा नम्बर डॉ० रघुबीर सिंह कादयान का है।

श्री उपाध्यक्ष : भजन लाल जी, जो भी प्रीज़ाईड करता है उसका यह कर्त्तव्य होता है कि सबको अकमोडेट करें आप के कुछ सदस्य बोल चुके हैं जिनकों बोलने का समय नहीं मिला है अगर उन में से कोई बोलना चाहे तो वह बोल सकता है।

डॉ० रघुबीर सिंह कादयान (बेरी) : डिप्टी स्पीकर साहब, आपने मुझे बजट पर चल रही बहस में पार्टीसिपेट करने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। डिप्टी स्पीकर साहब, जिस ढंग से फाईनैंस डिपार्टमैंट के माननीय ऑफिसर्ज़ साहेबान ने बजट की अच्छाई और बुराई बोल्डली दर्शाई हैं उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे हिसाब से इस सदन में किसी को इतनी महारत हासिल नहीं है जितनी प्रोफैसर सम्पत सिंह को है और वे दूसरे नम्बर पर आते हैं। हमारे माननीय सदस्य श्री मांगे राम गुप्ता जी को बजट के बारे में महारत हासिल है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने मोटे तौर पर बजट के बारे में नजर डाली तो मुझे साफ दिखाई दिया कि स्टेट के जितने रिसोर्सिज़ हैं, स्टेट का जो बजट है वह सारे का सारा कर्मचारियों की तनख्वाहों में, लोन की रीपेमैंट में और नान प्लान एक्सपैंडिचर में जा रहा है। **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)** स्पीकर साहब, आप बजट एट ए ग्लांस में देखें। इसके अनुसार नॉन प्लान एक्सपैंडिचर में 8016 करोड़ रुपए और प्लान एक्सपैंडिचर में 2520 करोड़ रुपए रखे गए हैं यह लगभग 80 परसैंट बजट नॉन प्लान एक्सपैंडिचर में जा रहा है। इसलिए नए असैटस के लिए सरकार के पास कोई पैसा दिखाई नहीं देता। ऐसा लग रहा है कि सरकार की इसमें कर्ज़ा लेने की नीयत साफ तौर पर झलकती है। इस बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा कि इस बजट स्पीच के पेज चार पर सीरियल नम्बर 8 में लिखा है —"राज्यों को वित्त अन्तरण के लिए ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशें हरियाणा जैसे प्रगतिशील राज्यों के लिए उत्साहजनक नहीं रही। आयोग द्वारा अपनाए गए तरीके बेहतर वित्तीय प्रबन्धन वाले राज्यों के हक में नहीं थे। फलस्वरूप केन्द्रीय करों में हमारा हिस्सा पहले के 1.238 प्रतिशत से घट कर अब 0.944 प्रतिशत रह गया है।" आयोग ने हरियाणा राज्य के वित्तीय प्रबंधन को अपेक्षाकृत बेहतर मानते हुए हमारे लिए राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश भी नहीं की है।

स्पीकर साहब, श्री ए०एम० खुसरो हमारे ग्यारहवें फाईनैंस कमिशन के चेयरमैन हैं और इंडियन एक्सप्रैस के श्री नरिन्दा गोपीनाथ ने स्पैसिफिकली कहा है।

श्री अध्यक्ष : कादयान साहब, आप 15 मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

डॉ० रघुबीर सिंह कादयान : स्पीकर साहब, मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं है कि गवर्नमैंट को लैट डाउन किया जाये। मेरी कन्स्ट्रैक्टिव सुजेशन की नीयत है। मैं कोई इरैलवेंट नहीं बोल रहा हूँ।

(विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कादयान साहब, आप अपनी स्पीच कन्टीन्यू करें।

डॉ० रघुबीर सिंह कादयान : स्पीकर साहब, आन्ध्रप्रदेश में यह शार्टफाल 7.9 परसैंट से 7.7 आया जो कि 0.2 परसैंट बैठता है जबकि हमारे यहां 20 प्रतिशत तक डिक्रीज किया है। इस डिक्रीज के ऊपर 27 अगस्त, 2000 के इण्डियन एक्सप्रैस मैगजीन के पेज 2 centrestage के आर्टिकल "Naidu has really no reason to crib" में इन्टरव्यू के दौरान वीरेन्दा गोपीनाथ ने यह सवाल किया "How do you react to the acquisition made by Chandrababu Naidu that the EFC has favoured 'non-performing states', with those who 'performed better' being discriminated against?"

स्पीकर साहब, इस सवाल के जवाब में मि० खुसरो ने यह कहा कि "First of all, to qualify the so-called 'group of eight' states as 'better performing states' is an error. Let me tell you, the economy of at least half of them is in a shambles. I don't want to name them, as I am not quarrelling with them, but at least three out of the five are fiscally bad performers. They have not reformed power and transportation systems and abolished taxes on agriculture and property arbitrarily,so the argument that 'better performing' states are penalised, does not come in."

स्पीकर साहब, इसमें स्पेसिफिकली मैंशन किया कि 11वें फाईनांस कमीशन के जो चेयरमैन मि० ए०एम० खुसरो हैं उनकी यह स्टेटमैंट है कि इस बिनाह पर हमारे बजट में जो शार्टफाल आया है उसके बारे में हमारे मुख्य मंत्री जी को क्लीयरली केन्द्रीय सरकार को बोलना चाहिए था कि हमारे बजट में 20 प्रतिशत जो डिक्रीज आया है यह एक बहुत बड़ी चिन्ता का विषय है। (विघ्न) इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन, इरीगेशन और पावर सिस्टम पर 2530 करोड़ रुपये की जो फिगर्ज दिखाई है यह एग्जेरेटिड है, यह प्लान पूरी होने वाली नहीं है। चौधरी सम्पत सिंह जी, आप इस प्लान को रिवाईज करें। जब यहां पर प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन मि० के०सी० पन्त आये थे तो उस मीटिंग में सम्पत सिंह जी मौजूद थे। इनको यह कहना चाहिए था कि हमारे यहाँ पर कट न लगाओ। मैं इनकी काबलियत पर शक नहीं कर रहा क्योंकि इनकी भी कुछ लिमिटेशन थी। कुछ लोग जो इनको रवैन्यू रिसिट अच्छी कलैक्ट करके देते वाले थे उनको इधर उधर बदल दिया जाता है। फाईनांस डिपार्टमैंट की भी हम लिमिटेशन समझते हैं। ये जो रवैन्यू रिसीट है यदि यह इनकी मर्जी से हो तो ये कर सकते हैं लेकिन जिस ढंग से 2530 करोड़ रुपये की प्लान को काटा गया है उसके बारे में मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊं कि इसमें गाज कहां पर पड़ेगी? यह गाज पड़ी इरीगेशन में जिसमें 200 करोड़ रुपये का डाऊन फाल आया। पावर के अन्दर 250 करोड़ रुपये का डाऊन फाल आया और ट्रांसपोर्टेशन के हैड में 350 करोड़ रुपये का डाउन फाल आया। स्पीकर साहब, यह बहुत बड़ी चिन्ता का विषय है। इन तीनों विभागों के बारे में फाईनांस कमीशन के चेयरमैन मि० खुसरो ने यह प्वाईंट आऊट किया है कि किसी प्रदेश के बुनियादी ढांचों में डाउन फाल दिखाया है, उससे इन्होंने इस प्रदेश के लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। इन्होंने इरीगेशन के लिए 506 करोड़ रुपये जो दिए थे उसको घटा कर 307 करोड़ रुपये कर दिया। पावर सैक्टर में 626 करोड़ रुपये दिए थे उसका रिवाईज्ड एस्टिमेट 374 करोड़ रुपये कर दिया और ट्रांसपोर्ट में 502 करोड़ रुपये का जो बजट ऐस्टिमेट था उसका रिवाईज्ड एस्टिमेट 162 करोड़ रुपये कर दिया। शुरू में 1634 करोड़ रुपये जो इन्होंने ट्रांसपोर्ट के लिए, इरीगेशन के लिए और पावर के लिए रखे थे उसको घटाकर 836 करोड़ रुपये पर ले आये यानि इन्होंने इन तीन महकमों पर ही तकरीबन 800 करोड़ रुपये का डाऊन फाल किया। सर, यह कोई

पेंटिंग या जगलरी तो हैं नहीं कि जिस ढंग से चाहे बजट पेश कर दें। ऐसा करके ये हरियाणा की जनता के साथ बड़ा भारी अन्याय कर रहे हैं और हरियाणा की जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, आज जो 2001-2002 में इन्होंने बजट ऐस्टिमेट्स पेश किया है, 368 करोड़ रुपये इरीगेशन में और 485 करोड़ रुपये दिये हैं पावर में। इसके साथ परिवहन में 324.75 करोड़ रुपये हैं लेकिन बजट कॉपी में ट्रांसपोर्ट के लिए 322.35 करोड़ दिये हैं इनमें कौन सी फिगर ठीक है आप यह चैक करवा लें क्योंकि दोनों फिगर्ज में फर्क है। यह सारे का सारा 1176 करोड़ रुपये 2001-2002 के लिए इसमें हैं। स्पीकर सर, जो वर्ष 2000-2001 का बजट था उसमें 1634 करोड़ रुपये और 2001-2002 के बजट में 1176 करोड़ रुपये हैं जिसमें कि 500 करोड़ रुपये का डाउनफाल है। गुप्ता जी ने यह प्वाइंट आउट किया है कि आप 64 से 54% पर आ गए बुनियाद ढांचे की प्रोग्रैस में, इसलिए इसमें downfall of the budget किस ओर जा रहा है, माननीय वित्त मन्त्री जी, क्या इस पर विचार करेंगे? स्पीकर सर, रैवेन्यू एण्ड रिसिट की बात बजट एट ए ग्लांस पर अगर हम आएं तो रिसीट में बजट ऐस्टिमेट्स 6755 करोड़ रुपये की थी और रिवाईज्ड ऐस्टिमेट्स 7035 करोड़ रुपये है। स्पीकर सर, फाईनैंस डिपार्टमैंट ने और इनकी काबलियत ने कमाल कर दिया। रैवेन्यू इतने जबरदस्त ढंग से बढ़ा है कि मेरे विचार से जब से हरियाणा बना है तब से ले कर आज तक कभी नहीं बढ़ा है। अगर चौधरी सम्पत सिंह जी इसमें अलग-अलग रिसीट देते कि इसकी ओरिजनल रिसीट कितनी है और जो यूनिफोर्म टैक्स लगेगा पूरे सिस्टम में उसमें रिसीट कितनी है। चौधरी बंसी लाल जी ने जो टैक्स लगाए थे उसका रिसीट कितना है और इस दौरान में आपने जो टैक्स लगाए हैं। उसका रिसीट कितना है। इसमें चार हैड्ज बनने चाहिएं थे तब इसमें दिखाई देता कि कितनी बहादुरी से सम्पत सिंह जी ने और फाईनैंस डिपार्टमैंट ने बजट को पेश किया है। (विघ्न)।

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि रैवेन्यू रिसीट बढ़ना क्या बुरी बात है? अगर रैवेन्यू रिसीट में परसैंटेज ज्यादा है तो यह तो एक बहुत ही बढ़िया बात है। (विघ्न) किस के टाईम में क्या आया और क्या नहीं हुआ, आप इस बात को छोड़ें। (विघ्न) जो रैवेन्यू आंकड़े दिये गये हैं क्या वे ठीक हैं या नहीं हैं, आप यह बताएं? (विघ्न)

डॉ० रघुबीर सिंह कादयान : आपका प्लान 2530 करोड़ रुपये से घटकर 1815 करोड़ रुपये रह गया। डिप्टी चेयरमैन, प्लानिंग कमीशन ने 1815 कर दिया यानी 700 करोड़ रुपये का कट आज चिन्ता का विषय है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप कैसे प्रदेश का विकास करेंगे? (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, जो बजट प्रस्ताव पेश किये गये हैं हम अपने विचार उस पर रख रहे हैं। हम जनता के प्रतिनिधि हैं इसलिए जनता की बात को यहां पर रखना हमारा अधिकार है। हम अपने सजैशंज देंगे लेकिन उन सजैशंज को सरकार माने या न माने यह उसकी मर्जी है। अगर आप गलत काम करेंगे तो जनता आपको अपने आप उसका जवाब दे देगी अगर हम गलत काम करेंगे तो जनता हमें भी अपना जवाब दे देगी। डिप्टी चेयरमैन, प्लानिंग कमीशन द्वारा 700 करोड़ रुपये का कट लगाने के बाद 1815 करोड़ रुपये रह गए जो पिछली सरकार के 1811 करोड़ रुपये के मुकाबले 6.9 प्रतिशत की वृद्धि वित्त मंत्री जी ने बताई है तो ये बता दें कि ये वृद्धि कैसे हो गई है?

श्री अध्यक्ष : कादयान साहब, आप पांच मिनट में खत्म करें।

डॉ० रघुबीर सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, कुल योजना का 54.06 प्रतिशत बिजली, सिंचाई और सड़क के बुनियादी ढांचे के लिए दिया गया है। लेकिन बजट एट ए ग्लांस में जब हम

[डॉ० रघुबीर सिंह कादयान]

देखते हैं कि रूपी ग्रोज में बिजली के लिए 9.94 प्रतिशत, सिंचाई के लिए 5.97 प्रतिशत, रोड्ज के लिए 3.95 प्रतिशत, ट्रांसपोर्ट के लिए 3.94 प्रतिशत दिए है यह टोटल खर्चा बुनियादी ढांचे के ऊपर दिया है जो कि 23.80 फीसदी बनता है यह बजट-एट-ए ग्लांस में दिया है। जबकि बजट में पेज नं० 5 पर 54.06 प्रतिशत दिखाया गया है यह वित्त मंत्री जी बताएं कि कौन-सा डैटा ठीक है? इसमें क्या हैरा-फेरी है वह बताएं। जहां तक पांच हैड रूरल डिवैल्पमैंट, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हैल्थ और इरिगेशन हैं इसमें आपका ऐलोकेशन 24.04 प्रतिशत है। इसका 80-85 प्रतिशत तो नॉन-प्लान में चला जाता है बाकि के पैसे से क्या स्कीमे चलेंगी? यह बहुत ही चिन्ता का विषय है। अध्यक्ष महोदय, पेज 11 पर लिखा है कि एक्स्पैंडिचर फ्राम कंसोलीडेटिड फंड आफ हरियाणा—मेजर एलोकेशन, इसमें एग्रीकल्चर के ऊपर 2000-2001 का रिवाईजड एस्टीमेट 772.92 लाख है और 2001-2002 के रिवाईज्ड एस्टीमेट में 539.90 लाख दिखाया है। इसमें डाउनफाल 229 लाख रुपये का है। यह बहुत ही चिन्ता का विषय है। आज प्रदेश के किसान पर डब्ल्यू०टी०ओ० की तलवार लटक रही है। इसमें ऐसा लग रहा है कि प्रदेश के किसानों की बहुत जोर से पिटाई होने वाली है उसका बहुत एक्सप्लॉएटेशन होने वाला है। यह सब किसानों की खेती को खत्म करने के लिए किया जा रहा है। (विघ्न) यह सब अपनी मोनोपोली चलाने के लिए है। (विघ्न)

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा) : अध्यक्ष महोदय, कादयान जी, यह बता दें कि डंकल प्रस्ताव किस सरकार के वक्त लाया गया था, किस ने यह एग्रीमैंट किया था और किस ने इसको साईन किया था। आप इस बारे में बता दें?

डा० रघुबीर सिंह कादयान : यह जो समझौता किया गया है इसका मुझे पता नहीं है किसने किया है और किस वक्त में किया गया है, हम उस वक्त में नहीं थे। स्पीकर साहब, इस समझौते के तहत आज हरियाणा के किसानों का एक्सप्लॉएटेशन होगा इसको कोई रोक नहीं सकता है। आज अमेरिका अपने किसानों को अरबों और खरबों रुपये का अनुदान दे रहा है। वर्ल्ड बैंक और आई०एम०एफ० के माध्यम से किसानों को अनुदान राशि मिल रही है यह उसको खत्म किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, दो दिन पहले करनाल में डॉक्टर नोरमल बारलो नोबल लयूरेट आए थे। उन्होंने कैटेगरिकल सजैशन दिया है कि अगर डब्ल्यू०टी०ओ० की तलवार से बचना चाहते हैं तो करोड़ों का इन्वैस्टमैंट करना पड़ेगा और आपने क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा, इसके सिवाय कोई और रास्ता नहीं है। बजट में यह भी लिखा है कि राज्य सरकार ने पंजाब सरकार के साथ मिलकर प्रो० वाई०के० अलघ की अध्यक्षता में एक विशेष समिति गठित की है। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही सीरियस मैटर है। (विघ्न) Face the facts squarely otherwise the facts will stab in the back.

श्री अध्यक्ष : कादयान साहब, आप वाईंड अप करें।

डॉ० रघुबीर सिंह कादयान : स्पीकर सर, हमारे और पंजाब के इंट्रस्ट तो मिलते ही नहीं है। अगर पंजाब से हमारे इंट्रस्ट मिलते तो जिस तरह से वे पैडी के लिए आठ सौ करोड़ रुपये भारत सरकार से ले गये उसी तरह से हमें भी पैसे मिलने चाहिएं थे लेकिन हमें एक पैसा नहीं मिला। स्पीकर सर, एन०सी०आर० में हरियाणा का बहुत सा एरिया पड़ता है इसलिए वहां सब्जी, फिशरीज, होर्टीकल्चर तथा डेयरी को अपनाने के लिए साईंटिस्टस की एक कमेटी बनायी जानी चाहिए जो इस बारे में अपने सुझाव दें। अध्यक्ष महोदय, जब तक डायवर्सीफिकेशन ऑफ क्रॉप नहीं होगा तब तक

किसान पर जो आज मार पड़ रही है, उससे नहीं बचा जा सकता। इस तरह से इनसे फेस टू फेस लड़ाई लड़ने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, भाई राम पाल माजरा ने आपके सामने सारी बात रखी कि जो बी०पी०एल० से नीचे रहने वाले लोग हैं उनकी संख्या पांच लाख से बढ़कर आठ लाख हो गयी है। स्पीकर सर, चार दिन पहले शांता कुमार जी ने जो पुअर फैमिलीज़ के बारे में स्टेटमैंट दी है उसमें उन्होंने हरियाणा के बारे में कहा है। The Total population projected is 1.98 crores. Average size of households as per 1991 census is 6.30. The percentage of BPL population in the State is 25.05%. इसमें पर कैपिटा इंकम जो है उसकी लाइन पैरलल सी है। एक तरफ तो पर कैपिटा इंकम नहीं बढ़ रही है वहीं दूसरी तरफ बी०पी०एल० से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ रही है जो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।

श्री पूर्ण सिंह डाबरा : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। मैं आपके माध्यम से आनरेबल मैम्बर से जानना चाहूंगा कि वे यह बताने का कष्ट करें कि किन-किन पॉलिसिज की वजह से यह नौबत आयी? क्योंकि इन्हीं की पार्टी ने लम्बे समय तक रूल किया है। ये गरीब लोगों के बारे में नारे तो उठाते हैं लेकिन इन्होंने उनके लिए कुछ नहीं किया।

डा० रघुबीर सिंह कादयान : बजट के अंदर मौटे तौर पर जो कहा गया है वह बहुत घिसापिटा है। फाइनैंशियल मैनेजमैंट में कुछ भी नया नहीं है। स्पीकर सर, आज के 'टाइम्ज ऑफ इंडिया' में एक हैडिंग में इस बात को कहा गया है कि "Haryana sinks deeper into debt trap." यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है। मांगेराम जी ने भी यही बात उठायी है कि दो हजार करोड़ रुपये हर साल घाटे के रूप में बढ़ रहे हैं। चौधरी सम्पत सिंह जी हिस्टोग्राम को एक सी०डी० की तरह लेकर चल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : रघुबीर सिंह जी, आप बैठ जाइए।

डॉ० रघुबीर सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, 35.4 परसैंट डैब्ट सर्विसेज़ और लोन रीपेमैंट में जा रहा है। यह बहुत ही सीरियस मैटर है। जो घर कर्ज के नीचे दबा हुआ हो और उस घर के चलाने वाले को कोई चिंता नहीं होगी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश किस दिशा में जा रहा है। मेरे हिसाब से यह बात जमती नहीं है।

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ ऑर्डर है।

डॉ० रघुबीर सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी किस रूलिंग के तहत बोल रहे हैं?

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं फ्रैंडली रूलिंग के तहत बोल रहा हूँ। मैं भाईचारे की रूलिंग के तहत बोल रहा हूँ। मैं इन से यह जानना चाहता हूँ कि इनकी पार्टी का कैप्टन कौन है? आपकी टीम का कैप्टन कौन है?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : हमारी पार्टी की लीडर सोनिया गांधी हैं।

प्रो० सम्पत सिंह : मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : हरियाणा का आपको मालूम ही है। ये अपनी जगह हैं हम अपनी जगह हैं। आपको बताने की जरूरत नहीं है। लोग बता देंगे। आपको क्या कठिनाई है, आप लोग

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]
अपना स्टेटस तो बता दें आपकी पार्टी में मुख्य मंत्री कितने हैं। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अब श्री बलबीर सिंह बाली बोलेंगे।

डॉ० रघुबीर सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, मुझे तो आपने बिठाया नहीं है। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : क्यों रघुबीर कादयान जी का ध्यान डायवर्ट कर रहें हैं, उन्हें बोलने का मौका दें, वे बहुत ही सीरियस बात कर रहे हैं, आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं?

नगर एवं ग्राम आयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिंह) : अध्यक्ष महोदय, माननीय पूर्व वित्त मंत्री जी व रघुबीर सिंह कादयान जी ने आज एक बहुत बड़ी शंका जाहिर की है कि प्रदेश में बाहर से पैसा आ रहा है। कर्ज के ऊपर इन्होंने कहा कि इतना पैसा ब्याज का देना पड़ेगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि चौधरी भजन लाल जी हाउस के नेता थे, मांगे राम जी वित्त मंत्री थे। मैंने पहली बार आग्रह किया था कि जो पैसा बाहर से लेकर नहर की सफाई का, सड़कों के बनाने के लिए, मुरम्मत के लिए या सूचना प्राप्त करने की कमेटी बनाने के लिए आएगा या किसी और काम के लिए आएगा उसके बारे मैंने सवाल किया था कि जो परम्पराएं हरियाणा में आ रही हैं वह भविष्य के लिए घातक होगी तो इन्होंने इस बात का मजाक उड़ाया था। (शोर एवं व्यवधान) जब मैंने पिछली कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान यह कहा था कि जो बाहर से पैसा लेने की परम्परा डाली जा रही है क्या वह पैसा हम वापस भी दे पायेंगे या नहीं दे पायेंगे? तब उस सरकार के समय में यह कहा गया था कि जिसकी साख अच्छी होती है पैसा उसी को मिलता है। उस समय जब हम इनकी दखल देते थे तो इनकी साख आ जाती थी। अब श्री मांगे राम गुप्ता जी बजट भाषण को इधर-उधर घुमाकर आज ये आशंका की बात करते हैं, व्यक्तित्व की बात करते हैं मैं तो इनकी बात को समझ नहीं पाया।

17-00 बजे

वैयक्तिक स्पष्टीकरण :

श्री मांगे राम गुप्ता एम०एल०ए० द्वारा

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मेरा पर्सनल एक्सप्लेनेशन है।

श्री अध्यक्ष : गुप्ता जी, आप बैठ जाइये।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात तो कहने दीजिये इन्होंने मेरा नाम लिया है। Speaker Sir, I have a right to speak in the House. I want to speak. I want to reply.

श्री अध्यक्ष : गुप्ता जी, आप बैठ जाइये।

नगर एवं ग्राम आयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिंह) : गुप्ता जी, मैंने तो आपका नाम लेकर प्वाइंट आउट किया था और मैंने तो यह कहा था कि पूर्व वित्त मंत्री श्री मांगे राम गुप्ता जी ने यह कहा था। अब अध्यक्ष जी कह रहे हैं तो आपको बैठ जाना चाहिये।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पर्सनल एक्सप्लेनेशन में कहना चाहता हूँ कि

जैसाकि चौधरी धीरपाल जी कर्ज के बारे में फरमा रहे थे। मैं बाहर से कर्ज लेकर भण्डार भरने के हक में नहीं था और न आज हूँ। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश 1966 में बना था और 1966 से 1996 तक हरियाणा प्रदेश पर सात हजार करोड़ रुपये का ऋण था और 1996 से 2000 तक हरियाणा प्रदेश पर 17000 करोड़ रुपये का ऋण हो गया है इन चार सालों में दस हजार करोड़ रुपये का ऋण बढ़ गया है। यह सरकार प्रदेश का दिवालिया निकाल रही है।

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : स्पीकर सर, कर्ज वाली बात का जवाब मैं रिप्लाई में दूंगा। बाकी श्री मांगे राम गुप्ता जी और कादयान जी से एक अर्ज मैं जरूर करना चाहूंगा कि बजट के बारे में जो आलोचना ये कर सकते थे वह की है लेकिन अब ये कर्ज को कम करने के बारे में हमें कोई सुझाव दे दें कि कर्ज को कम करने के लिए सोर्सिज कैसे जुटाये जा सकते हैं, हम इनका सुझाव मान लेंगे।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, आप कादयान साहब को समय कहां दे रहे हैं। वे सुझाव कैसे दे पायेंगे?

श्री अध्यक्ष : अभी भी बता सकते हैं, कई मौके दिए हैं।

Prof. Sampat Singh : Speaker sir, we are all concerned about the loan or about the borrowings.इसलिये मैं कह रहा हूँ कि जो रिसोर्सिज जुटा सकते हैं हम जुटाएंगे, ये हमें बताएं, हम उनके बारे में विचार अवश्य करेंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, अगर वित्त मंत्री जी ने सुझाव मांगने थे तो बजट पेश करने से पहले सुझाव मांगने चाहिएं थे जो कि हरियाणा में पहले से मान्यता रही है।

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, ये अब सुझाव दे दें हम तो अभी भी मान लेंगे।

वर्ष 2001-2002 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

डॉ० रघुबीर सिंह कादयान : स्पीकर सर, जिस ढंग से प्रदेश कर्ज के नीचे दबा जा रहा है, पर कैपिटा कर्ज बढ़ता जा रहा है और प्रदेश में ग्रोथ रेट कम होता जा रहा है। उसके बारे में ये लोग खुद जानते हैं, यह पोलिटिकल सिस्टम का कसूर है। इसमें फाइनैंशियल मैनेजमैंट का कसूर नहीं है। मेरा इसमें यह सुझाव है कि हरियाणा प्रदेश के पास काफी ऐसे क्षेत्र उपलब्ध हैं जहाँ पूरी ईमानदारी के साथ किसी मौजूदा टैक्स की वसूली की जाए तो बिना और टैक्स लगाए काफी रैवेन्यू इकट्ठा हो सकता है। जिससे मौजूदा रैवेन्यू रिसीट में भी ज्यादा पैसा आ सकता है। इससे पोलिटिकल सिस्टम इफैक्टिव है, यह बात अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा प्रदेश के माननीय वित्त मंत्री जी को बताना चाहता हूँ।

श्री पूर्ण सिंह डाबड़ा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पोलिटिकल सिस्टम का जिक्र किया तो मैं कहना चाहूँगा कि काफी लम्बे अर्से तक इनकी पार्टी सत्ता में रही है। क्या इनकी पार्टी की सरकार ने उस सिस्टम पर अमल किया था?

डॉ० रघुबीर सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, इनकी बात का जवाब मैं बाद में दूंगा। हरियाणा प्रदेश दिल्ली के तीन तरफ लगता है। दिल्ली में बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बड़े-बड़े शोरूम हैं। इस बजट में कई ऐसे कंसाइनमैंट टैक्स लगाए गए हैं जिनके ऊपर अच्छी तरह से सोचा जाए तो

[डॉ० रघुबीर सिंह कादयान]

हरियाणा प्रदेश टैक्स फ्री हो सकता है, अगर पोलिटिकल विल हो तो। अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने हल्के बेरी में नहरी पानी के बारे में बात करूंगा। मेरे हल्के में ड्रेन नं० 8 लगती है।

श्री अध्यक्ष : कादयान जी, आप बैठें। आपका समय समाप्त हो गया है।

डॉ० रघुबीर सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने हल्के के बारे में कहना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : कादयान जी, कल मुख्य मंत्री महोदय ने बेरी की 10 सड़कों के बारे में बताया था कि ये बन रही हैं। अगर फिर भी आप जो कहना चाहते हैं वह लिखकर दे दें। इसके अलावा आपके हल्के में एक लाख रुपये भी दिए गए हैं। (शोर एवं व्यवधान)

वित्त मंत्री (प्रो०सम्पत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, अब ये कह रहे हैं हमें बोलने दो फिर कह देंगे कि सैशन बहुत लम्बा चला रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं तो कहता हूँ कि यदि आपकी सहमति हो तो इस हाउस को सारी रात तक चलने दो।

डॉ० रघुबीर सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, मुझे दो मिन्ट का समय और दे दें।

श्री अध्यक्ष : कादयान जी, आप कॉलिंग अटैंशन पर भी बोल चुके हैं, गवर्नर एड्रैस और बजट पर भी बोल चुके हैं। इसलिए अब आप बैठ जाएं।

डॉ० रघुबीर सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, गवर्नर एड्रैस पर तो मैंने बाई काट कर दिया था।

श्री भागी राम : अध्यक्ष महोदय, ये दो मिनट में कौन-सा पहाड़ तोड़ लेंगे।

आवाजें : इनको दो मिनट का समय दे दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : सदन की सिफारिश पर आपको दो की बजाए तीन मिनट का समय दे दिया जाता है।

डॉ० रघुबीर सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदन के नेता ने इस हाउस में बेरी हल्के की सड़कों के बारे में इन्फार्मेशन दी। एग्रीकल्चर मिनिस्टर मुख्य मंत्री जी को एक प्रोफार्मा देकर आए कि बेरी में 8 सड़कें निर्माणाधीन हैं। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि गोच्छी से बिसान सड़क 1994-1995 में कम्पलीट हो चुकी थी। बहराना से इस्माइला सड़क का काम चल रहा है। इसके अलावा 6 सड़कें दुबलधन से पहाड़ीपुर, जोंधी से गुड्डा, चिमनी से चिमनी मन्दिर, खातीवास से गवालिसन, पलड़ा से मांगावास और मदाना कलां से छोच्छी हैं इन सड़कों पर कोई काम नहीं हुआ, इनके ऊपर एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो सदन के पाँच मैम्बरों की एक कमेटी बना दें, वह सर्वे कर लेगी और अपनी रिपोर्ट दे देगी। उस रिपोर्ट से सबको पता लग जाएगा कि सही क्या है। (शोर एवं व्यवधान)

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा) : अध्यक्ष महोदय, रघुबीर सिंह जी अपने हल्के का दौरा तो करते नहीं हैं इन्हें कुछ नहीं पता कि इनके वहाँ क्या कार्य हो रहे हैं। इन्होंने अपने यहाँ 33 के०वी०ए० का एक सब-स्टेशन लगाने के बारे में प्रश्न दिया था कि वहाँ पर यह सब-स्टेशन कब तक लगेगा, जबकि यह सब-स्टेशन दो महीने पहले चालू हो चुका है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलवंत सिंह मायना : अध्यक्ष महोदय, मैं रघुबीर सिंह कादयान जी को बताना चाहूँगा

कि बरहाणा से लेकर डीघल तक की सड़क पर काम चल रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० रघुबीर सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, पिछले बजट सैशन के दौरान माननीय वित्त मंत्री जी ने यह कहा था कि 30 जून तक हरियाणा के अन्दर सभी सड़कों की रिपेयर हो जाएगी। उसके बाद सदन के नेता ने 30 मई का समय कर दिया था। मैंने सड़कों के नाम माननीय मुख्य मंत्री जी को दिए थे जिनके बारे में मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि इन सड़कों का कार्य हो जाएगा। इन सड़कों के नाम हैं बरहाना-डीघल-गोच्छी-बेरी-दुबलधन-सिवाना, दुबलधन-चीमनी, चीमनी-ढ़राना-बेरी, दुबलधन-जहाजगढ़ वाया पलड़ा, दुबलधन-माजरा-मलिकपुर-पहाड़ीपुर-अच्छेज-छुछकवास, बेरी-वजीरपुर-जहाजगढ़, बेरी-झज्जर वाया धौड़, सदाणा-महराणा-बिरधाना, झज्जर-खेड़ी-खातीवास-जहाजगढ़, बेरी-बिसाण-रिठोली-कबूलपुर, बेरी दुजाणा-महराणा, भम्भेवा-शिमली, बरहाणा-गोच्छी, बरहाणा-दिमाणा, डीघल-कलानौर एवं बेरी-सेरिया। अध्यक्ष महोदय, इन 16 सड़कों पर मुख्य मंत्री जी के आश्वासन देने के बावजूद भी काम नहीं करवाया है। इनमें से दुबलधन, बरहाना, डीघल, बेरी और अच्छेज आदि 4-5 सड़कों पर 4-4 फीट के गड्ढे पड़े हुए हैं। (विघ्न) स्पीकर साहब, यदि ऐसा नहीं है तो इस सदन की एक कमेटी बना दो और वह चैक करके बता देगी कि असलियत क्या है? स्पीकर साहब, आपने भी इन सड़कों को देखा है और आपने कहा था कि इनको ठीक करवाने के बारे में आप मुख्य मंत्री जी से कहेंगे।

श्री अध्यक्ष : रघुबीर जी, प्लीज् आप बैठें, आपका समय पूरा हो गया है।

डॉ० रघुबीर सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ****

श्री अध्यक्ष : कादयान साहब ने जो कुछ कहा है वह रिकार्ड न किया जाये। कादयान साहब, आपको काफी ज्यादा समय बोलने के लिए दिया गया और इससे आपके नेता भी संतुष्ट हैं, अब प्लीज् आप बैठ जाएं। (विघ्न)

डॉ० रघुबीर सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, हम यहाँ चुनकर इसलिए आते हैं ताकि अपने हल्के की समस्या बता सकें। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कादयान साहब, आप 45 मिनट तक बोल चुके हैं। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय डॉ० रघुबीर सिंह कादयान हाउस की वैल में आकर धरने पर बैठ गए तत्पश्चात् कांग्रेस के एक सदस्य श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा उन्हें उठाकर उनकी सीट तक ले गए।)

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, आप अपने एम०एल०एज़० को सद्बुद्धि दें। (शोर)

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, आपने बार-बार जितना टाइम भी देना था, देते रहे। उसके बावजूद भी श्री रघुबीर सिंह कादयान जी का हाउस की वैल में आकर बैठना शोभा नहीं देता है। ठीक है ये अच्छा बोले। यह अच्छी बात है। हम इनको सुन रहे थे और इनकी सारी बातें नोट भी कर रहे थे। इनके लैवल पर इस तरह की बातें शोभा नहीं देतीं। (विघ्न) इस तरह की बात तब हुआ करती है जब मैम्बरों को बोलने का समय पूरा न मिले। आपने माननीय सदस्य को बोलने का पूरा समय दिया और जो बातें ये रजिस्टर्ड कराना चाहते थे वह सारी बातें रजिस्टर्ड करा लीं। सरकार ने भी नोट कर लीं और हाउस में भी नोट हो गईं। (शोर)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, कादयान साहब ने जो कुछ भी कहा है आप उनकी

****चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

भावनाओं को पहचानो और उनकी मांगों को मान लेने का आश्वासन भी सरकार दे दे।

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, हाउस के मैम्बर्ज जो भी आवाज उठा रहे हैं चाहे वह हल्के से संबंधित हो, चाहे विभाग से संबंधित हो या फिर कोई सुझाव हो या कोई समस्या हो, हम हर बात को गंभीरता से नोट कर रहे हैं और उनको सरकार की तरफ से यथासंभव सोल्व करने का प्रयास भी किया जाएगा। जो अच्छे सुझाव होंगे उनको भी हम मानेंगे।

चौधरी भजन लाल : ठीक है, धन्यवाद।

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप सबने देखा है कि मैं सुबह से यहां पर बैठा हूँ और बाकायदा हर चीज को नोट कर रहा हूँ। मैं यह बात इसलिये नहीं कह रहा हूँ कि मैं माननीय सदस्य की कोई निन्दा करना चाहता हूँ लेकिन जो कुछ यहाँ हुआ है वह दुर्भाग्य वश हुआ है। इनकी तरफ से ऐसी बात शोभा नहीं देती है।

श्री बलबीर सिंह (महम) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया है इसके लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। माननीय वित्त मंत्री जी ने वर्ष 2001-2002 के लिये इस सदन में जो बजट पेश किया है मैं उस बजट के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ। माननीय वित्त मंत्री जी ने जितना कर रहित बजट पेश किया है वह शायद हरियाणा प्रदेश में पहली मिसाल है। आज तक कभी ऐसा कर रहित बजट पेश नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, जो बजट पेश किया गया है यह हरियाणा प्रदेश में पहली मिसाल है कि हरियाणा बनने के बाद कर रहित बजट पेश किया गया है। अध्यक्ष महोदय, सदन के जो सम्मानित सदस्य हैं, मेरे से बहुत सीनियर हैं, बुजुर्ग भी हैं, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, हमारे विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य एक आवाज में बोलते हैं कि प्रदेश में कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, एक मिसाल याद आ गई कि आज कल गाँवों के अन्दर सत्संग का बड़ा जोर है। (हंसी) उसमें एक चीज देखने योग्य है उसके बारे में एक ही बात कहना चाहूंगा और ज्यादा बातें नहीं कहना चाहूँगा। उस सत्संग में सबसे ज्यादा लेडीज़ जाती है, हमारे नौजवान साथी भी जाते हैं, वे किस किस्म के जाते हैं, इस बात का अंदाजा आप खुद लगा लें। जो उन सत्संगों में जाते हैं वे एक ही भाषा बोलते हैं कि वे नाम ले कर आए हैं। इसी तरह से हमारे कांग्रेस पार्टी के विरोधी साथी एक ही भाषा बोलते हैं, सरकार चाहे कोई विकास का कार्य कर रही है या कर दिया है तो उसको गलत बता रहे हैं क्योंकि इन्होंने भी यह बात कहने का नाम लिया हुआ है। अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की बात कही जाए तो उसको ये माननीय साथी गलत बताते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं 1991 से 1996 के समय की एक बात दावे के साथ कहता हूँ जब चौधरी भजन लाल जी प्रदेश के चीफ मिनिस्टर होते थे और उस समय इनकी सरकार पूर्ण बहुमत की थी। उस समय इन्होंने रोहतक जिले के अन्दर एक भी नया रोड नहीं बनवाया। अध्यक्ष महोदय, यह रिकार्ड की बात है कि पिछले डेढ़ साल के अर्से के दौरान रोहतक जिले में जितनी नई सड़कें बनी हैं उतनी कभी भी नहीं बनीं। मेरे हल्के महम के अन्दर 27 नई सड़कें बनाई गई हैं। हुड्डा साहब, यहां सदन में बैठे हैं इनके किलोई हल्के में 32 नई सड़कें बनाई गई हैं। डॉ० रघुबीर सिंह कादयान जी के बेरी हल्के में 14 नई सड़कें बनाई गई हैं। अध्यक्ष महोदय, जो हमारे विरोधी पक्ष के सम्मानित सदस्य बैठे हैं, उनमें हमारी बहन जी भी शामिल हैं। अध्यक्ष महोदय, सदन में हरियाणा प्रदेश की क्रीम बैठी है। जब क्रीम ही अनाप-शनाप बात करे तो फिर इस देश-प्रदेश का क्या हाल होगा? कांग्रेस पार्टी को अपना माहौल याद आता होगा। कांग्रेस पार्टी तो आया राम गया

राम के नाम से मशहूर है। जो देश का प्रधान मंत्री रह चुका हो, उसके और उसके कैबिनेट के मंत्रियों के खिलाफ मुकदमें दर्ज हों तो फिर आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि वह पार्टी कैसी पार्टी है? कांग्रेस पार्टी की जो नेता है उसको गेहूँ और जौं के पौधे में अन्तर का पता नहीं। अगर इनकी पार्टी की नेता यह अन्तर बता दें तो आप मुझे जो चाहे सजा दे दें, मुझे मंजूर होगी।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने पिछले डेढ़ वर्ष के दौरान खेलों को काफी बढ़ावा दिया है। खेलों की पैरवी ओलम्पिक संघ के अध्यक्ष भाई अभय चौटाला जी कर रहे हैं। चाहे कोई खिलाड़ी बालीबाल का हो, कुश्ती का हो, फुटबाल का हो, हाकी का हो या दूसरे किसी खेल का हो उनको सरकारी नौकरी देने के लिए हमारी सरकार ने 3 परसैंट का कोटा फिक्स किया है। भजन लाल जी की सरकार ने तो खिलाड़ियों के लिए एक परसैंट भी कोटा फिक्स नहीं किया था। चौधरी देवी लाल जी जो कोटा देकर गए थे उसको भी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने खत्म कर दिया यह रिकार्ड की बात है। लेकिन अब हमारी सरकार ने कहा है कि जो अच्छे खिलाड़ी होंगे उनको नौकरी में रखा जायेगा और उनको परमोशन भी दी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी बुढ़ापा पैंशन के बारे में भी कुछ आरोप सरकार पर लगा रहे थे। ये भाई कह रहे थे कि सरकार बुढ़ापा पैंशन में भी भेदभाव बरत रही है। जो पैंशन हमारी सरकार दे गई थी कांग्रेस पार्टी ने तो उसको भी काट दिया। शर्त लगा दी गई कि जिसका लड़का सर्विस में होगा या जिसके पास 5 एकड़ जमीन होगी या जिसका कोई बिजनैस होगा उसको पैंशन की सुविधा नहीं दी जायेगी। इन्होंने तो यहां तक कर दिया था कि यदि किसी का लड़का गांव में ही नून-तेल की परचून की दुकान खोल लेता था तो उसको भी बिजनैस मान लिया गया और उसके मां-बाप की भी पैंशन काट दी गई। 100 रुपये बुढ़ापा पैंशन देने की स्कीम भी हमने शुरू की थी और उसको डबल भी हमने किया है। आज हर गांव में पहले की अपेक्षा दुगने लोग पैंशन ले रहे हैं। आप बेशक रिकार्ड देख लें। आज के दिन 55 साल का बूढ़ा तो पैंशन लेता मिल जायेगा लेकिन 60 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति बगैर पैंशन के नहीं पायेगा।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर विकास के बारे में कहा गया कि हरियाणा में इस सरकार के आने के बाद कोई विकास के कार्य नहीं हो रहे और यह सरकार भेदभाव कर रही है। मैं रिकार्ड की बात बता रहा हूँ कि पिछले डेढ साल में सड़कों का इतना काम हुआ जितना कांग्रेस पार्टी अपने 5 सालों में भी सड़कों का काम नहीं कर पाई थी। इसी प्रकार से हमारी सरकार ने डेढ़ साल में पंचायतों को इतना पैसा विकास के लिए दिया है जितना कांग्रेस पार्टी 5 साल में भी नहीं दे पाई थी। (विघ्न) ये भाई तो सौदेबाजी में विश्वास रखते हैं। (विघ्न) यह तो नेता जी से लेकर छोटे से सिपाही तक सौदेबाजी में विश्वास रखते हैं इसमें मेरे साथी शामिल रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये एक और बात कहते हैं कि बजट में किसान को कोई रियायत नहीं दी गई। मैं अपने इन साथियों को याद दिला दूं कि डंकल प्रस्ताव पर जो दस्तखत हुए हैं वह किस के शासनकाल में हुए हैं। ये खुद उस समय सैंट्रल गवर्नमैंट में मंत्री थे। (विघ्न)

प्रो० सम्मत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चौधरी भजन लाल से यह कहना चाहूंगा कि ये इस बात पर थोड़ी रोशनी डाल दें। (विघ्न) ये उस समय केन्द्र में कृषि मंत्री थे, इसलिए इनसे बेहतर इस मामले पर कौन रोशनी डाल सकता है? (विघ्न)

श्री बलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, डंकल प्रस्ताव जब पास हुआ था उस समय सैंटर में कांग्रेस की सरकार थी, पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी और हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी की ही

[श्री बलबीर सिंह]

सरकार थी। ये लोग आज किसान-किसान कर रहे हैं, किसान की भी बात इनको बता देता हूँ। डी०ए०पी० का कट्टा भी 180 रुपये में मिलता था। सब जमींदार भाई यहां पर बैठे हुए हैंऔर उनको पता है कि कांग्रेस सरकार के राज में 360 रुपये प्रति कट्टा हो गया था। अब ये किसान की हमदर्दी की बात करते हैं। यह जो डंकल प्रस्ताव का नुकसान होगा या डंकल की जो मार जमींदारों पर पड़ेगी यह प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी की ही देन है यह सब लोगों को पता है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, एक सम्मानित साथी ने कहा कि 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम बहुत अच्छा है और बाद में फिर यह भी कहा कि इस कार्यक्रम के तहत बी०डी०ओज० और एम०एल०एज० के काम होते हैं इस प्रकार से ये दोगली बात करते हैं। उन्हें अपनी नीति को स्पष्ट करना चाहिए और बताना चाहिए कि वे इसका विरोध करते हैं या समर्थन करते हैं। इसे स्पष्ट कहना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने और आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने 'सरकार आपके द्वार' का जो निर्णय लिया है उसके तहत हर हल्के के विकास के काम हो रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि जिस हल्के का एम०एल०ए० या मंत्री स्वयं रुचि लेता था उस हल्के के काम तो हो जाते थे लेकिन बाकी के काम नहीं हो पाते थे। 50 प्रतिशत से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि कामों को करवाने के लिए चण्डीगढ़ नहीं आ सकते हैं लेकिन 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के तहत मुख्य मंत्री जी खुद लोगों के पास जाते हैं और खुले दरबार में हर व्यक्ति सरकार से सीधे मिलता है और अपनी बात कहता है। मुख्य मन्त्री जी उनके कामों को सुनते हैं और उनको वहीं पर ही मंजूर करते हैं और समस्याओं का समाधान मौके पर ही करते हैं। इस प्रकार के जो काम हैं उनके निर्माण कार्य भी शुरू हो चुके हैं और आगे और नये काम भी हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये हर बात का विरोध कर रहे हैं। इन्होंने तो कोई भी बात हो उसका विरोध करना ही है, उल्टा ही चलना है। अध्यक्ष महोदय, गन्ने की चर्चा भी यहां पर हमारे सम्मानित सदस्य ने की थी। मैं आपके माध्यम से उन सम्मानित सदस्य जी को बताना चाहूंगा कि आज पूरे प्रदेश में गन्ने का सबसे ज्यादा भाव अगर कहीं है तो वह हरियाणा प्रदेश में है। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने गन्ने का सबसे ज्यादा रेट दे रखा है। अध्यक्ष महोदय, आपके भी ध्यान में होगा कि इस सरकार के आने से पहले पानीपत मिल में जमींदारों की कई सालों की पेमैन्ट बकाया थी। इस सरकार के आने के बाद वह पेमैन्ट वसूल हो गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के नेता जी से कहना चाहूँगा कि पानीपत में लोग गन्ना बोना ही छोड़ गए थे क्योंकि उनकी 4-4 और 5-5 साल की पेमैन्ट ही नहीं मिल रही थी। लेकिन आज वहां पर पहले के मुकाबले ज्यादा गन्ना बोया जा रहा है। आज उनको पेमैन्ट लेने के लिए मिलों पर नहीं जाना पड़ता है। मुख्य मंत्री जी ने आदेश दे रखे हैं कि पेमैन्ट बैंकों से जाकर लें। (विघ्न)

स्पीकर साहब, यदि ये बिजली के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं इनको उसके बारे में भी बता देता हूँ। मौजूदा सरकार ने बिजली के मामले में एक भी जमींदार पर लाठी नहीं चलवाई है, गोली नहीं चलवाई है। गोली चलाने वाला जमाना चौधरी साहब आपको याद होगा, वह पिछली सरकार का था जोकि गोलियां चलवाया करते थे। अध्यक्ष महोदय, अगर कहीं पर भी 10 आदमी इकट्ठा होते थे तो उन पर फायर ब्रिगेड से पानी के फव्वारे छोड़े जाते थे और गोलियां चलवाई जाती थीं। अध्यक्ष महोदय, बिजली की कमी है वह हम मानते हैं। लेकिन एक बात मैं विश्वास के साथ कहना चाहूँगा। आज के वक्त में कांग्रेस की सरकार और चौधरी बंसी लाल जी की सरकार के वक्त से ज्यादा बिजली दी जा रही है और आप यह पता भी कर सकते हैं। मुख्य मंत्री जी अपनी हर मीटिंग में यह पता करते रहते हैं कि गांवों में बिजली की क्या पोजिशन है? आज बारिश नहीं हुई है जिसकी वजह से नहरों

में पानी नहीं गया है इसकी वजह से भी बिजली की कमी है। यह तो कुदरत की मार है और इसके आगे किसी की भी नहीं चलती है इससे कोई बच नहीं सकता है। (विघ्न) हुड्डा साहब आप चिंता न करें हम 24 घंटे बिजली देंगे। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बिजली के बिलों की बात की है। मैं इनको यह बताना चाहूँगा कि आज ज्यादा से ज्यादा लोग बिजली का बिल दे रहे हैं। यह क्यों हो रहा है क्योंकि हमारी सरकार ने सरचार्ज माफ कर दिया है, ब्याज माफ कर दिया है और चार किस्तों में बिल देने के लिए कह दिया है। सरकार की नीयत ठीक होनी चाहिए और इस सरकार की नीयत में कोई कमी नहीं है। नीयत में तो उनकी कमी थी जो गोलियां चलवाते थे। (विघ्न) धर्मबीर जी आप भूतपूर्व मंत्री हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं तो मोखरे गांव की बात बता देता हूँ और ये मदीना की बता दें। मोखरे गांव के 10-15 लाख रुपये के बिल बकाया हैं और महीने दो महीने में यह भी बकाया नहीं रहेगा। मदीना गांव में धर्मबीर सिंह के रिश्तेदार हैं इसलिए इनको बिजली के बिल भरने के लिए वहां के लोगों को कहना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ये तो अदालत का फैसला भी नहीं मानते हैं। जाकर कह देते हैं कि अदालत में पेश न हों। अब तो ये राजी भी हो रहे हैं और इकट्ठी ही दाल रांध रहे हैं। हालांकि चौधरी भजनलाल जी ने उनसे स्पष्ट कहा था कि अदालत में पेश तो होना पड़ेगा। (विघ्न)

डॉ० रघुबीर सिंह कादयान : स्पीकर सर, मेरा प्वाईंट ऑफ आर्डर है। जो आदमी हाउस में न बैठा हो उसके बारे में यहां पर कोई बात नहीं कहनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : कादयान साहब, इन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया है इसलिए आप बैठें।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, इन्होंने नाम नहीं लिया है ये तो चौधरी धर्मबीर के रिश्तेदारों का जिक्र कर रहे थे ये बीच में कहां आ गये।

श्री बलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये राधा स्वामी की तरह नाम नाम कर रहे हैं। पहले तो इन्होंने उनको अदालत की उल्लंघना करने के लिए भड़काया और कल लौबी में कह रहे थे कि उसका ठीक इलाज हो गया।

डॉ० रघुबीर सिंह कादयान : स्पीकर सर, ये किसके बारे में जिक्र कर रहे हैं।

श्री बलबीर सिंह : मैं धर्मबीर सिंह के बारे में कह रहा हूँ। इन्होंने भी महम में चबूतरे पर जाकर बहुत से वायदे किये थे लेकिन उन पर ये खरे नहीं उतरे। (विघ्न) पहले कोई भी हरकत होती थी उसका ब्लेम लोकदल वालों पर ही लगा करता था लेकिन अब भगवान का शुक्र है कि ऐसी बात नहीं है। अब ये तीनों चारों कांग्रेस में चले गए हैं और अब ये आपस में ही जूते बजा रहे हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं तो चौटाला साहब की पार्टी का छोटा सा सिपाही हूँ। अब अगर कहीं भी रैली हो लेकिन एक मुंगफली भी टूटती हो तो यह बता दें, जबकि पहले रेहड़ी को उल्टा ये करते थे और नाम हमारा लग जाता था। मैं आपके माध्यम से विपक्ष के नेता को और इनकी पार्टी के प्रैजीडैंट को कहना चाहता हूं कि इन पर नजर रखना, नहीं तो ये कुंडा कर देंगे। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, प्रजातंत्र में वह आदमी उभरकर आता है जो शरीफ हो और लोगों का हमदर्द हो। लोग बदमाशों के सामने हां तो भर लेते हैं लेकिन वोट नहीं देते हैं। जो लोगों की भलाई कर सके और हमदर्द हो उसको लोग चाह रहे हैं। अगर सारे बदमाश हों तो जंगल का राज हो जाएगा। मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि डॉ० रघुबीर सिंह कादयान बार-बार परिवार का जिक्र कर रहे थे कि परिवार को कैसे चलाया जाए यह बजट में नहीं दर्शाया। मैं आपके माध्यम से जिक्र करना चाहूंगा कि जिस घर में जूत बाजया करैं से, उस घर के सुथरे दिन कोनी आते, उसका उल्टा हो

[श्री बलबीर सिंह]

होता है। अध्यक्ष महोदय, जो भी सम्मानित साथी बोलने के लिए खड़े हुए उन्होंने यह बात कही कि क्राइम इतने बढ़ गए। जंगल का राज हो गया, ठीक है यह बात हम मानते हैं। अध्यक्ष महोदय, क्राइम तो हमने देखे हैं चाहे किसी की सरकार हो, क्राइम करने वाला क्राइम कर देता है पर सरकार की नीति का इस बारे में जो पता लगता है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि क्राइम करने वाला क्राइम करके चला गया लेकिन उसको पकड़ने में सरकार या अपनी पुलिस कितनी कामयाब होती है यह देखने वाली बात है। हमारी सरकार आने के डेढ़ साल के बाद एक भी केस ऐसा नहीं है जो न गिरफ्तार किए हों। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के समय के 5-4 केस गिना दूं। जिसका आज तक अता पता नहीं लगा है, जैसे द्रोपदी कांड, सुमित्रा कांड, भूतमाजरा आदि कांड हैं। यह कितनी बुराई की बात है कि सुशीला कांड जो कि जाति के नाम पर किया गया या करवाया गया था उसमें जो पावरफुल आदमी थे, उनके रिश्तेदार शामिल थे, उनका आज तक पता नहीं लगा। अब वह आदमी यह कहे कि जुल्म बढ़ गए हैं, ठीक बात नहीं है। वे अपने शासन काल को भूल गए। अब मुख्य मंत्री जी ने आदेश दे रखे हैं कि चाहे कोई सीनियर अधिकारी हो, चाहे सीनियर राजनेता है, कोई भी है, गलत काम करेगा तो उसे सजा जरूर मिलेगी। (घंटी) अध्यक्ष महोदय, मुझे दो चार मिनट का समय और दे दें।

श्री अध्यक्ष : आप दो मिनट में वाइंड अप करें।

श्री बलबीर सिंह : चौधरी बंसी लाल की सरकार जब सत्ता में नहीं आई थी तो उस से पहले कांग्रेस पार्टी का शासन था। अपने वे जो पुलिस के भाई हैं, कर्मचारी हैं उन्हें हफ्ते दस दिन में बंसी लाल इकट्ठा कर लेते थे कि आपका स्पेशल ख्याल करेंगे। जब सत्ता में आ गए तो कोई भी ख्याल नहीं करा। अब मौजूदा सरकार के मुख्य मंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने निर्णय लिया कि एक तो 16 साल की सर्विस के बाद सिपाही को हवलदार बनाया जाएगा ताकि वे निष्ठा से ड्यूटी दे सकें, कुछ सिपाहियों को हवलदार बना भी दिया है, सरकार ने यह बहुत अच्छा काम किया है। 32 साल की नौकरी के बाद ए०एस०आई० बनाया जाएगा। मैं आपके माध्यम से सरकार से अर्ज करूं, क्योंकि मैं भी पुलिस के परिवार में रहा हूँ इसलिए कहना चाहूंगा कि थोड़ा बहुत और भी पुलिस के भाइयों का ख्याल रखा जाए और कुछ अलग से उनको दिया जाए ताकि पता लगे कि सरकार ने पुलिस वालों को कुछ अलग से दिया है। अध्यक्ष महोदय, वे कर्मचारियों को भड़काते थे ऐसे ऐसे बयान दिये, मैं कहना चाहता हूँ कि जिसका रोजगार लग जाए, उसका अगर रोजगार छूटे चाहे वह किसी पार्टी से हो तो यह गलत बात है। विरोधी पक्ष के भाई यह कहते थे कि चौटाला साहब को तो प्रदेश के नौजवानों को नौकरी पर लगाना नहीं आता लेकिन मैं कहता हूँ कि जो 1600 सिपाही भर्ती किए थे वह किस की सरकार ने भर्ती किए थे। आज वे 1600 सिपाही बेघर हो गए हैं। वे अपने आपको पी०एच०डी० साबित किया करते थे, अब तो इनकी वह डिग्री फेल हो गई। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि अब उन भाइयों को मुख्य मंत्री जी ने अलग से रिलैक्सेशन दी है लेकिन मैं चाहूंगा कि जब भी पुलिस की भर्ती हो तो उस समय उनका ख्याल किया जाए, यह मेरा अनुरोध है चाहे व किसी भी पार्टी से हों, उनका ख्याल किया जाए। अध्यक्ष महोदय, भर्ती करने वाला कोई भी अधिकारी हो उसको अपनी कार्य प्रणाली देखनी चाहिए, उसको भर्ती होने वाले कैंडीडेट के शरीर में देखना चाहिए कि उसमें कोई कमी है या नहीं, या ठीक है। अगर कोई कैंडीडेट कमी का भरा हो और ब्यानबाजी करे कि वह ठीक है तो क्या लोग नहीं समझते कि वह झूठ बोल रहा है इसलिए जो सम्मानित सदस्य बोलें तो कम से कम वे तथ्यों के आधार पर तो बोलें जिनमें सच्चाई हो।

अध्यक्ष महोदय, जब से देश आजाद हुआ है हमारे सम्मानित हरिजन भाइयों की वोटें कांग्रेस पार्टी लेती आई है और उनका एक भी काम कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया है। स्पीकर सर, मैं हरियाणा सरकार, खासकर माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने हरिजन की लड़की की शादी के वक्त कन्यादान के रूप में 5100 रुपये देने का काम किया है ताकि गरीब आदमी अपनी लड़की के हाथ पीले कर सके और उसकी शादी ठीक ढंग से कर सके। विपक्ष की पार्टी ने उनके वोट तो लिये हैं लेकिन उनके लिये कोई भी काम नहीं किया। लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने गरीब आदमियों की भलाई के लिये अच्छा काम किया है जिस के लिये वे बधाई के पात्र हैं। (इस समय मेजें थपथपाई गईं) अध्यक्ष महोदय, बोलते समय मैंने किसी के बारे में कोई गलत बात नहीं की, फिर भी अगर मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकल गया हो तो मैं उसके लिये क्षमा चाहता हूँ। सम्मानित सदस्यों ने मुझे ध्यान से सुना उसके लिये मैं उनका धन्यवाद करता हूं और जो माननीय वित्त मंत्री महोदय ने 2001-2002 का बजट पेश किया है उसका मैं डटकर समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी बोलिये।

चौधरी जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा इस सदन में मौजूद नहीं है, वे कल बोलेंगे। हमारी पार्टी ने आपको बोलने वाले सदस्यों की लिस्ट दे रखी है आप उस लिस्ट में से सदस्यों को बोलने के लिये कहें। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : जिस भी सदस्य ने बोलना है आज बोल लें क्योंकि कल वित्त मंत्री जी रिप्लाई देंगे। ठीक है, जयप्रकाश जी आप ही बोलिये। (विघ्न)

चौधरी जय प्रकाश (बरवाला) **:** अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रो० सम्पत सिंह जी ने जो बजट स्पीच पढ़ी थी वह बहुत ही दबाव में पढ़ी थी। ये हरियाणा की जनता को गुमराह करने वाले दस्तावेज हैं। प्रो० सम्पत सिंह जी ने अपनी बजट स्पीच में स्वयं कहा है कि डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग बोर्ड और 11 वें वित्तायोग ने बजट में डिडक्शन कर दी है। लेकिन मुझे याद है कि जब मिस्टर के०सी० पंत चंडीगढ़ आए थे तो प्रैस कांफ्रैंस में उन्होंने कहा कि हरियाणा के बजट में जो डिडक्शन हुई है वह इसलिए हुई है कि सरकार ने सत्ता हासिल करने के लिए विधान सभा के चुनाव के लिए बजट में जो पैसे का प्रोविजन था उसका दुरुपयोग किया है।

श्री अध्यक्ष : उसकी रूलिंग दे दी गई है, क्लैरीफिकेशन दे दी गई है।

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाईंट आफ आर्डर है। जय प्रकाश जी, के०सी० पंत चंडीगढ़ में प्लानिंग कमीशन की मीटिंग लेने के लिए नहीं आए थे। दूसरा आपको यह बात पता होनी चाहिए कि यह जो डिडक्शन आप बता रहे थे, यह प्लानिंग कमीशन की नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनको बजट के बारे में मालूम नहीं है। यह फाइनैंस कमीशन की है और फाइनैंस कमीशन से के०सी० पंत का कोई वास्ता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इनको किसी चीज का पता नहीं है प्लानिंग कमीशन अलग चीज है और फाइनैंस कमीशन अलग चीज है। यह बात फाइनैंस कमीशन की है न कि प्लानिंग कमीशन की।

चौधरी जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मैंने 11 वां वित्तायोग कहा है। ये वित्तायोग को न समझते हों तो अलग बात है। (शोर)

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी, आप बजट पर बोलें।

चौधरी जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, खुसरो उस आयोग के चेयरमैन थे। अपनी चोरी को छिपाने के लिए ट्रेजरी बैंचिज की तरफ से हमेशा मजाक की बात की जाती है, यह मजाक नहीं है। वित्त मंत्री महोदय, आपकी असफलता का सबसे बड़ा प्रमाण इस बात से है कि आपने खुद मान लिया कि हमारा केन्द्र से जो पैसा आता है उसमें डिडक्शन हुई है। आप इस बात से बिल्कुल इन्कार नहीं कर सकते। अध्यक्ष महोदय, कुछ भाई कह रहे थे कि 'सरकार आपके द्वार कार्यक्रम' बहुत अच्छा है। 'सरकार आपके द्वार कार्यक्रम' में क्या किया गया वह मैं बताता हूं। इस प्रदेश की जनता की खून पसीने की कमाई जो टैक्स की शक्ल में सरकारी खजाने में जमा होती है, सरकार उसको भी ठीक इस्तेमाल नहीं कर रही। विधान सभा के चुनावों से पहले हरियाणा प्रदेश की मार्केट कमेटियों ने तकरीबन 100 करोड़ रुपये सड़कों के लिए रखे हुए थे। लेकिन उस पैसे का इस सरकार ने वोट लेने के लिये दुरुपयोग किया। बरवाला विधान सभा क्षेत्र के अन्दर 6 सड़कें मार्किटिंग बोर्ड की हैं। (विघ्न) मैं मार्किटिंग बोर्ड की सड़कों की बात कर रहा हूँ न कि पी०डब्ल्यू०डी० की बात कर रहा हूँ। मार्किटिंग बोर्ड की ये ऐसी सड़कें हैं जिनके ठेके दे दिए गए, उन पर मिट्टी भी डलवा दी गई लेकिन एक सड़क को भी कारपैटिंग नहीं किया गया जबकि एक साल से ऊपर समय हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इन सड़कों को कारपैटिंग करने के लिए महकमे के पास तारकोल नहीं है। ठेकेदारों में त्राहि-त्राहि मची हुई है। जब भी एल०ओ०सी० होती है तो मार्किटिंग बोर्ड के ठेकेदार एल०ओ०सी० के लिए वित्त मंत्री महोदय से और एग्रीकल्चर मिनिस्टर से सिफारिश करवाते हैं।

श्री बलवंत सिंह मायना : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहता हूँ। ये कह रहे हैं कि ठेकेदार मंत्रियों से सिफारिश करवाते हैं, ऐसी बात नहीं है। जब कार्य पूरा हो जाता है तब आखिरी पेमैंट होती है।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, इनको इस बारे में ज्ञान ही नहीं है।

श्री बलवंत सिंह मायना : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भजन लाल जी को बताना चाहूँगा कि मैं इस हाउस का सदस्य भी हूँ और मार्किटिंग बोर्ड का चेयरमैन भी हूँ। (शोर) मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि माननीय साथी को इस बात का ज्ञान नहीं है कि ये कारपैटिंग की बात कर रहे थे। मैं इनको बताना चाहूँगा कि सड़कों पर कारपैटिंग का काम लास्ट काम है। सर्दी और बारिश के मौसम में सड़कों की कारपैटिंग के लिए तारकोल का काम करते हैं तो वह पकड़ नहीं करता इसलिए जब गर्मी का मौसम आएगा तब सारी सड़कों की कारपैटिंग कर दी जाएगी, ऐसा मैं सदन में विश्वास दिलाता हूं।

18.00 बजे

चौधरी जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, बरवाला विधान सभा क्षेत्र की ये जो 8 सड़कें हैं ये 1999 के अंत में मंजूर की गई थीं उसके बाद पूरा गर्मी का मौसम आ चुका है, उस वक्त सर्दी कहाँ थी लेकिन वोट हासिल करने के लिए हरियाणा प्रदेश के लोगों का सैकड़ों करोड़ रुपया मिट्टी और रोड़ों में बहा दिया, हम इसके खिलाफ हैं। चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि कारपैटिंग करवा देंगे मैं इसके लिये इनका धन्यवाद करता हूं। हरियाणा मार्किटिंग बोर्ड की सारी की सारी एफ०डीज० टूट चुकी हैं और चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि पैसा खर्च करेंगे। पैसा है नहीं, वे कहाँ से लाएंगे। इनके इंजीनियर कहते हैं कि स्लो वर्क-स्लो वर्क यानि काम धीरे-धीरे किया जाये। करना होना यह चाहिए कि जहां पर मिट्टी और रोड़े पड़ चुके हैं वहाँ पर कारपैटिंग भी साथ ही होनी

चाहिए। अगर मिट्टी और रोड़े पहले डाले जाएंगे और कारपैटिंग बाद में होगी तो मिट्टी रोड़ों से बाहर निकल जाएगी इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में पढ़ दिया है कि मार्किटिंग बोर्ड की तरफ से सड़कों पर काफी पैसा खर्च किया है, लोग बड़े खुश हो रहे हैं लेकिन उसका नतीजा तब निकलेगा जब हम हल्के में जाकर देखेंगे। अध्यक्ष महोदय, बिजली के बारे में भी सरकार द्वारा काफी वाहवाही लूटी जा रही है वित्त मंत्री जी ने लिखा है कि बिजली की पुरानी तारें बदली गई हैं, नई लाईनें बिछाई गई हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि हिसार जिले में कितनी पुरानी तारों को बदला गया है और कितनी नई लाईनें बिछाई गई हैं, हमें बतायें। यह सरकार जो पिछली सरकार का इन्फ्रास्ट्रैक्चर था उसी को बार-बार गाये जा रही है। इनके भाषण में और पहले वाली सरकार के भाषण में कोई अंतर नजर नहीं आता। अध्यक्ष महोदय, मौजूदा सरकार अपने को किसान हितैषी सरकार कहती है लेकिन इन्होंने बिजली के क्षेत्र में किसानों को जितनी मार इस साल मारी है इतनी पहले किसी सरकार ने नहीं मारी। किसानों की हमदर्द कहने वाली सरकार ने किसानों पर बिजली के रेट 35 रुपये प्रति हार्स पावर बढ़ा दिए हैं। इस तरह से किसान को बुरी तरह से सरकार की तरफ से मार पड़ रही है। सरकार फ्लैट रेट को भी समाप्त करने की बात कर रही है और कह रहे हैं कि मीटर लगवा देंगे और उसी हिसाब से बिजली का बिल किसानों से लिया जाएगा। मौजूदा सरकार ने कहा कि पिछले वर्ष इन्होंने केन्द्र सरकार से आग्रह करके गेहूँ के रेट 90 रुपये प्रति क्विंटल बढ़वाये लेकिन यह नहीं बताया कि डीज़ल, बिजली, कीटनाशक दवाईयों और बीज के रेट कितने ज्यादा बढ़ाए गए। यही कारण है कि हरियाणा की जनता का इस सरकार से मन हट चुका है और जनता का ध्यान डाईवर्ट करने के लिए ही वित्त मंत्री जी के माध्यम से मौजूदा सरकार ने असत्य कागज़ सदन में पेश करवा दिए हैं जिसकी वजह से आज इस बजट पर से हमारा विश्वास उठ चुका है।

अब मैं पानी के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। इस बारे में मांगे राम गुप्ता जी ने भी कहा था और देश के प्रधान मंत्री जिस समय हरियाणा में आये थे उस समय उन्होंने भी कहा था कि एस०वाई०एल० के पानी के बारे में हरियाणा के मुख्य मंत्री की पहल करनी चाहिए। लेकिन हरियाणा प्रदेश के मुख्य मंत्री का ब्यान है कि यह मामला न्यायपालिका के विचाराधीन है इसलिए हम कोई बात नहीं करेंगे। मुख्य मंत्री जी का यह कहना गलत है, सिस्टम इस तरह नहीं चलता। यह बात ठीक है कि यह मामला न्यायपालिका के विचाराधीन है लेकिन आपसी बातचीत से यदि यह मामला हल हो जाए तो इससे सरकार को क्या परेशानी होगी? यह सरकार 1987 के अंदर एस०वाई०एल० के पानी के नाम पर हरियाणा में स्थापित हुई थी और उसके बाद तीन सरकारें बन चुकी हैं इस मामले पर कुछ नहीं हुआ। 1987 से लेकर 1990 तक इनेलो की सरकार थी, 1991 से लेकर 1996 तक कांग्रेस सरकार थी और 1996 से लेकर 1999 तक चौधरी बंसी लाल जी की सरकार थी और अब फिर इनेलो-भाजपा की सरकार आ गई है। एस०वाई०एल० का पानी लेने के लिए हमारे तीन नौजवान शहीद हो चुके हैं और आज तक इस पर कोई कामयाबी नहीं मिली है।

श्री भागी राम : अध्यक्ष महोदय, मैं जे०पी० जी से जानना चाहूँगा कि वे नौजवान साथी किसके समय में शहीद हुये थे, उस समय किसकी सरकार थी?

चौधरी जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, वे नौजवान उस समय शहीद हुये थे जब [redacted] चौटाला साहब के साथ था। (विघ्न) उस समय उन नौजवानों की शहादत के नाम पर वोट मांगने वाली सरकार को बने डेढ़ साल हो गये हैं लेकिन इन्होंने अब तक एस०वाई०एल० के पानी के बारे में केन्द्र सरकार से या पंजाब सरकार से बातचीत नहीं की और न ही किसी तरह का आग्रह किया। इससे बुरी

[चौधरी जय प्रकाश]

बात और क्या हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, 1995 में सदन के नेता ने पूरे हरियाणा प्रदेश में ट्रैक्टर पर रैली निकाली थी, उस वक्त कांग्रेस की सरकार हरियाणा में थी, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। उस वक्त चौटाला साहब ने कहा था कि यमुना जल समझौता गलत हुआ है और मेरी सरकार आएगी तो मैं इस समझौते को रद्द करूंगा। अध्यक्ष महोदय, भागीराम जी बता दें अगर ऐसा न हुआ हो तो। उस समय पूरे प्रदेश में यात्राएं निकाली गई थीं। अब डेढ़ साल से इनेलो-भाजपा की सरकार हरियाणा प्रदेश में है। आज तक इस संबंध में सरकार ने कोई भी रिजौल्यूशन पास नहीं किया है और न ही कोई चिट्ठी केन्द्र सरकार को लिखी है। हरियाणा प्रदेश के किसानों का पानी उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सरकार को दिया जा रहा है। फिर भी सरकार यह कहती है कि यह सरकार हरियाणा प्रदेश के किसानों की हमदर्द है। अध्यक्ष महोदय,मैं कहता हूँ कि जब से हरियाणा बना है तब से लेकर आज तक किसी भी सरकार में किसानों की इतनी दुर्गति नहीं हुई है जितनी इस सरकार में हो रही है। अध्यक्ष महोदय, नहरी पानी का बार-बार जिक्र हुआ है। मैं आपके माध्यम से प्रो० सम्पत सिंह जी को बताना चाहूँगा कि वे बधौड़ माइनर की हालत जाकर देख लें, बरवाला लिंक की हालत देख लें, कहाँ है पानी? ऐसी बातों को वे मजाक में ले जाते हैं कि बहुत पानी है। (शोर) पूरे हिसार जिले में जो पानी 15 दिन के बाद मिलता था वह अब 45 दिन के बाद मिल रहा है। इससे नाकाबिल सरकार कोई हो नहीं सकती। जो किसानों के हमदर्द कहलाते हैं वही किसानों के पानी का हिस्सा मारते हैं। अध्यक्ष महोदय, बजट में जिक्र किया गया है कि एम०आई०टी०सी० के नाले पक्के करवाए जाएंगे। वित्त मंत्री जी अपने रिप्लाई में जरूर बतायें कि पिछले एक वर्ष में इनके शासन में यानि पिछले बजट से लेकर आज तक कितने किलोमीटर नाले पक्के करवाये गये। आज सारी नालियां टूटी पड़ी हैं और वाहवाही लूटने के लिए कह देते हैं कि एम०आई०टी०सी० के जो नाले टूटे पड़े हैं उनके निर्माण का सारा खर्च सरकार वहन करेगी। हम पहले वाली सरकार की तरह नहीं हैं। ये बतायें तो सही कि कितने नाले इन्होंने रिपेयर कराये हैं। (विघ्न) पानी के मामले को लेकर भी इस सरकार ने कोई गम्भीरता नहीं दिखाई है। पंजाब के नवांशहर या मजीठा में कोई चुनाव हो तो हरियाणा प्रदेश के मुख्य मंत्री वहाँ पर अकाली दल के लिए वोट मांगते हैं तो क्या मुख्य मंत्री जी का यह फर्ज नहीं बनता या सरकार का यह धर्म नहीं है कि जब सियासी बात करने के लिए चुनावी लड़ाई में जाते हैं तथा सामाजिक रिश्ते बड़े मधुर है तो एस.वाई.एल. के बारे में नहीं कह सकते कि पानी का हमारा जो हिस्सा है वह हमें दो। लेकिन अपने व्यापारी रिश्ते कायम रखने के लिए कि कहीं रिश्ते टूट न जायें, इस डर से उनसे पानी की बात नहीं करते। डेढ़ वर्ष में कोई भी चिट्ठी इस संबध में नहीं लिखी गई है इससे बुरी हालत हो नहीं सकती। (इस समय उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुये) (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, जल संसाधन के ऊपर पिछले वर्ष जो पैसा खर्च किया गया था उसकी अपेक्षा अब की बार कम खर्च हुआ है। क्या प्रो० सम्पत सिंह अपने रिप्लाई में बताएंगे कि इस बार पानी पर कम पैसा क्यों खर्च हुआ? उपाध्यक्ष महोदय, पानी हमारे लिए और खासकर हरियाणा प्रदेश के लिए बहुत जरूरी है चाहे दक्षिणी हरियाणा हो या फिर हिसार जिला ही। बार-बार यहाँ चर्चा चलती है कि हिसार में पानी ज्यादा है बरवाला में पानी ज्यादा है। मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहूँगा कि वहाँ 45 दिन से पानी नहीं है। पानी कहां चला गया है? अगर सिरसा जिले में ज्यादा पानी चला गया है तो उसके लिए हम लोग दोषी नहीं हैं क्योंकि हम तो विपक्ष में बैठे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अब पी०डब्ल्यू०डी० (बी०एण्ड आर०) की सड़कों की बात आती है तो बड़े अदब के साथ कहता हूँ कि सड़कों के ऊपर हरियाणा प्रदेश की सरकार ने अच्छा काम किया है। मेरे हल्के की सड़कों की रिपेयर भी हुई है लेकिन मैं आपके माध्यम

से वित्त मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि सड़कों के लिये हुडको से अब तक कितना पैसा आया है और कितना और आएगा। हमारी जो सड़कें बाकी हैं उनकी रिपेयर कब तक हो जाएगी? यह सारी बात भी वित्त मंत्री जी को अपने जवाब में बतानी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार बेरोजगार नौजवानों की भावनाओं के ऊपर बनी थी लेकिन बजट में उनको अनदेखा किया गया है। इनकी पार्टी के नेता और प्रो० सम्मत सिंह ने कहा कि हजारों नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन कहीं पर भी यह बात अंकित नहीं की है कि कितने नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा?

प्रो० सम्मत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, वे बजट को ठीक तरह से पढ़ें तो सही।

चौधरी जय प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने उसे पढ़ लिया है। इसमें केवल रोजगारोन्मुखी योजनाओं का जिक्र है। अब ये ड्रामे-बाजी नहीं चलेगी। इन्होंने रोजगार के सम्बन्ध में कुछ नहीं बताया है। उपाध्यक्ष महोदय, आज भी एक हरिजन भाई आमरण अनशन पर बैठा हुआ है जिसका मैं नाम नहीं बताऊंगा। (शोर)

श्री बलवंत सिंह मायना : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आपकी कांग्रेस पार्टी की सरकार बहुत अर्से तक रही आप उसका भी लेखा जोखा दे दें। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने हरियाणा प्रदेश के कितने युवक युवतियों को नौकरियां दी और कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया यह बता दें। हरियाणा प्रदेश में आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार आने के बाद प्रदेश के 14000 युवक युवतियों को नौकरियां दी गई हैं। यह रिकॉर्ड की बात है।

चौधरी जय प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदय, महासिंह गुरानिया नाम का हरिजन जो दलित समुदाय से सम्बन्ध रखता है, उसने मुझे यह लिखकर दिया है कि महासिंह गुरानिया का इस सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ धरना। उपाध्यक्ष महोदय, इससे बुरी बात और क्या हो सकती है। एक महीने से लगातार हरियाणा कान्फैड के कर्मचारी हड़ताल पर हैं और हाँसी स्पीनिंग मिल के कर्मचारी दो महीने से लगातार हड़ताल पर बैठे हैं जिनकी उम्र 50-50 साल की हो गई है। उपाध्यक्ष महोदय, आज उनको यह कह दिया जाए कि हम आपको तीन महीने की तनखाह देंगे या उसके बराबर पैसा देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, जिस आदमी की उम्र 50 वर्ष की हो गई हो उसके बच्चे जवान हैं, वह किसी दूसरी जगह एडजैस्ट नहीं हो सकता। या तो सरकार यह फैसला करे कि सरकार जो भी महकमा बंद करती है वह बंद करे वह बंद करने का सरकार का अधिकार है लेकिन उस महकमें के जो कर्मचारी हैं उनको दूसरे महकमों में एडजैस्ट करना चाहिए यह नहीं कि वहाँ पर नये लोग भर्ती करने के प्रयास किए जाएं।

नगर एवं ग्राम आयोजना मंत्री (श्री धीर पाल सिंह) : डिप्टी स्पीकर साहब, विरोधी पक्ष के साथी बार-बार एक ही बात कह रहे हैं। मैं माननीय सदस्य जय प्रकाश जी को बताना चाहूँगा कि माननीय पंजाब एण्ड हरियाणा हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया हमने उसकी पालना की है। कनफैड की जो छोटी-छोटी दुकाने थीं वे घाटे में चल रही थीं इसलिए कानफैड से कोई दूसरा काम लेने की बात थी। माननीय हाई कोर्ट ने यह आदेश पारित किया है कि वहां पर कर्मचारियों की छंटनी हो सकती है। माननीय हाई कोर्ट के आदेश की पालना करते हुए हमारी सरकार की यह मंशा नहीं है कि कर्मचारियों की छंटनी की जाए लेकिन छंटनी होने के बावजूद और हाईकोर्ट का आदेश मानने के बावजूद उन कर्मचारियों को ये अधिकार दिए हैं कि हरियाणा सरकार जब किसी महकमें के लिये आवेदन पत्र मांगे उस समय वे अपना आवेदन दे सकते हैं और उनकी आयु सीमा को छोड़ दिया गया है।

चौधरी जय प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात मानता हूँ कि सरकार रिट्रैंचमैंट कर सकती है। यदि किसी महकमें में घाटे की बात हो तो सरकार उस महकमे को बंद कर सकती है। मैं तो केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ कि वहाँ से जिन कर्मचारियों की रिट्रैंचमैंट की गई है उनको दूसरे महकमों में एडजैस्ट किया जाए।

प्रो० सम्पत सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, वैसे तो मुख्य मंत्री जी ने गवर्नर एड्रैस पर हुई बहस का जवाब देते समय कन्फैड के बारे में और हांसी स्पीनिंग मिल के बारे में काफी कुछ बता दिया था लेकिन मैं माननीय सदस्य का और ज्यादा ज्ञान वर्धन करने के लिए कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक कनफैड का सवाल है तो वहाँ पर एक बार पहले भी कर्मचारियों की रिट्रैंचमैंट हुई है। निकाले गये कर्मचारियों को पहले सरकार ने क्लास-4 की पोस्टों पर एडजैस्ट करने की कोशिश की। (शोर एवं विघ्न) उस वक्त बिना किसी सैंक्शन और क्वालिफिकेशन के इनकी भर्ती कर ली गई थी। जब उनको क्लास-4 के अगेन्स्ट लगाने की कोशिश की तो ये लोग कोर्ट में चले गये कि सरकार हमें क्लास-4 के अगेन्स्ट नहीं लगा सकती। डिप्टी स्पीकर साहब, अगर उस वक्त ये लोग उस फैसले को मान लेते तो बहुत फायदे में रहते। (शोर एवं विघ्न) वे किस सोच के हिसाब से कोर्ट में गये, ये जानें। बाद में कोर्ट ने कह दिया कि इनको क्लास-4 के अगेन्स्ट नहीं लगाया जाए। अगर अब उनको क्लास-4 के अगेन्स्ट भी लगाते हैं तो अब कोर्ट के आदेशों की अवहेलना होती है, जिसकी अवहेलना कोई भी सरकार या कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता।

जहाँ तक स्पीनिंग मिल का सवाल है तो यह स्पीनिंग मिल न तो हैफेड की है और न ही सरकार की है। यह मिल वहाँ की एक लोकल सोसाइटी की है। हैफेड ने तो केवल कुछ समय के लिये इसे लीज़ पर लिया था। लीज़ खत्म होने पर उसे छोड़ दिया गया। यह मिल सोसाइटी की थी और सोसाइटी ने ही इसको बंद किया। सोसाइटी इसको चलाती है तो 2 लाख रुपये रोज़ का घाटा है और नहीं चलाती तो एक लाख रुपये का रोज़ का घाटा है। यह लोकल सोसाइटी की मिल है और सरकार ने उन मिल मुलाजिमों की रिट्रैंचमैंट नहीं की। वे सोसाइटी के मुलाजिम थे सरकार के नहीं।

चौधरी भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने अभी जो स्टेटमैंट इस मिल के बारे में दी है वह ठीक नहीं है। सरकार ने हैफेड, कान्फैड व दूसरी संस्थाओं से बहुत से कर्मचारियों को निकाला है या निकालने जा रही है। मैं यह नहीं कह सकता कि सरकार इनको निकाल नहीं सकती। जो संस्थाएं घाटे में चल रही हों उनके कर्मचारियों को निकालना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मेरा कहना यह है कि निकालने की बजाए इन कर्मचारियों के नुक्सान/हितों को देखते हुए उनको दूसरी जगह पर दूसरी पोस्टों पर जिन ग्रेड और पोस्टों पर पहले वे लगे हुए थे, लगाया जाना चाहिए। कई तो अब ओवरऐज भी हो गए होंगे। यह बेचारे कर्मचारी कहाँ पर जाएंगे इनका ध्यान सरकार को करना चाहिए।

प्रो० सम्पत सिंह : क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनकी क्लास-4 की पोस्टें बनती थीं। फिर वे कोर्ट में चले गए इसलिए कोर्ट के आदेशानुसार उन्हें अब क्लास-4 भी नहीं लगा सकते। (शोर एवं विघ्न)

चौधरी भजन लाल : मेरा कहना यह है कि जिस पोस्ट पर वे पहले लगे हुए थे उनको निकालने के बाद दूसरी जगह पर उसी ग्रेड में लगाने में क्या दिक्कत है। (शोर एवं विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी, आप बैठिए।

चौधरी भजन लाल : डिप्टी स्पीकर साहब, सोसाइटी भी गर्वनमैंट चलाती है। सोसाइटीज को गर्वनमैंट ऐड देती है। (शोर एवं विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंह : चौधरी साहब, यह गर्वनमैंट की सोसाइटी नहीं थी और न ही कोई पब्लिक अंडरटेकिंग थी। यह एक लोकल सोसाइटी थी जिसे हैफेड ने लीज पर कुछ समय के लिये लिया था। लीज़ पर लेने वाला कोई तभी रखेगा जब उसको फायदा होगा और उसको फायदा नहीं होगा तो वह नहीं रखेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने दोनों बातें क्लीयर कर दी कि एक तो वे बिना सैंक्शन और बिना क्वालिफिकेशन के कान्फैड के कर्मचारियों को लगाया गया था। क्लास-IV के अगेन्स्ट इनको लगा नहीं सकते क्योंकि यह कोर्ट का फैसला है। दूसरे यह स्पीनिंग मिल सरकार की नहीं थी बल्कि एक लोकल सोसाइटी की थी।

चौधरी जय प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या इन कर्मचारियों को क्लास-IV पर लगाने के लिए इन्होंने उनसे बैठकर कोई बात करने की कोशिश की थी अगर इन्होंने ऐसी कोई कोशिश की है तो हमें बता दें ताकि हमें भी पता लग जाए। ये इस बारे में अपनी रिप्लाई में बता दें।

प्रो० सम्पत सिंह : अब कोर्ट के फैसले के कारण हम उन्हें क्लास-IV भी नहीं लगा सकते।

श्री मांगे राम गुप्ता : क्लास-IV पर न सही लेकिन जिस पोस्ट पर वे जहाँ पर पहले लगे हुये थे, उस हिसाब से उनको उसी पोस्ट पर दूसरी जगह पर लगा सकते हैं। (शोर एवं विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंह : उस वक्त जेब से लैटर निकाल कर एपार्बटमैंट लेटर दे देते थे। क्या कभी जब चाहे जेब से निकाल कर किसी को एम्लाएमैंट दी जा सकती है। (शोर एवं विघ्न)

चौधरी जय प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदय, अभी सरकार ने जिन 1600 पुलिस कर्मचारियों को निकाला है उसमें मैं सरकार की कोई गलती नहीं मानता क्योंकि उनको सुप्रीम कोर्ट ने हटाया है। लेकिन मैं एक बात प्रोफैसर साहब को कहना चाहूँगा कि सभी काम नफे नुक्सान को देखकर नहीं किये जाते यानि हर समय नफा नुक्सान नहीं देखा जाता। कई बार जनहित में नफे नुक्सान से हटकर भी काम करना पड़ता है। (शोर एवं विघ्न) अगर नफे नुक्सान को देखोगे तो फिर कई थाने बंद करने पड़ेंगे, फिर उनको क्यों चालू रखा हुआ है। सरकार को सोशल वैल्फेयर के आधार पर भी कई काम करने पड़ते हैं। (शोर एवं विघ्न) कई ऐसी चीजें भी हैं जिनको नुक्सान के बाद भी चलाना पड़ता है, मैं समझता हूँ कि जनहित में उनको चलाना भी चाहिये। अगर सरकार उनको नहीं चलाती तो इसमें आपकी कमजोरी व विफलता है। उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा प्रश्न ग्रामीण विकास योजना के बारे में है।

श्री उपाध्यक्ष : आप वाइंड अप करें।

चौधरी जय प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात दो मिनट में खत्म कर देता हूँ। मेरा कहना यह है कि ग्रामीण विकास से सम्बन्धित बनाई गई समितियों के बारे में हर पार्टी के मैम्बरों ने कहा कि यह ठीक नहीं है। आप इस बारे में पुलिस का रिकार्ड देख लें कि मेरे हल्के बरवाला में मतलोडा के अन्दर एक बार नहीं 5 बार वहां पर समिति बनाने के लिए बी०डी०ओ० का स्टाफ गया, वहाँ पर झगड़े हुये। इसी प्रकार से यमुनानगर में कत्ल हुआ। ये जगह-जगह झगड़े क्यों हुए? अगर

[चौधरी जय प्रकाश]

जनता इन समितियों को चाहती तो ये झगड़े क्यों होते। (शोर एवं विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को यह बताना चाहता हूँ कि इसमें सरकार की बेईमानी थी क्योंकि सरपंचों का ज्यादा बहुमत हमारी पार्टी का था तो इसलिए इन लोगों ने उन लोगों के अधिकारक्षेत्र को कम करने के लिये और अपने लोगों को घुसाने के लिए यह असंवैधानिक कार्य किया। उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में सदन के नेता ने भी एक बार यह कहा था कि यह काम संविधान के मुताबिक किया गया है। अगर यह संविधान के मुताबिक किया गया है तो यह बताएं कि संविधान की किस धारा में लिखा हुआ है। प्रोफैसर सम्पत सिंह जी जब जवाब दें तो उस रिप्लाई में बता दें तो अच्छी बात है। असंवैधानिक कार्यवाही करके झूठी वाहवाही लूटना कोई अच्छी बात नहीं है।

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है। हरियाणा प्रदेश की जनता ने पिछले विधान सभा के चुनाव में इनको सबक सिखाया, जिला परिषद के चुनावों में इनको सबक सिखाया, म्यूनिसिपल कमेटीज के चुनावों में इनको सबक सिखाया, इनके पंचों और सरपंचों को बेदखल किया और ये कह रहे हैं कि हमारी मैजोरिटी है। उपाध्यक्ष महोदय, ये लॉ एण्ड आर्डर की बात कर रहे हैं। जब ये भाई हमारी पार्टी में थे तो नौजवानों को सिखा दिया कि सारी रेहड़ियां लूट लो, सारे प्लॉट्स पर कब्जा कर लो। उन्होंने पूछा कि मन्दिरों का क्या करें तो इन्होंने जवाब दिया और यहां तक कहा कि इन मन्दिरों पर भी कब्जा कर लो और भीतर पुजारी को रोक दो और कहीं कोई मूर्ति वगैरा मिल जाए और उस पर कोई छत्र वगैरा मिल जाए तो उसको भी उठा ले चलो और आज ये लॉ एण्ड आर्डर की बात करते हैं।

चौधरी जय प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे साथी मंत्री ने बिल्कुल ठीक बात कही है क्योंकि उस वक्त इस सदन के वर्तमान नेता मुख्य मंत्री जी मेरे अध्यक्ष होते थे। जिसकी खांवै बाकली उसके गावैं गीत, उस वक्त वे हमारे अध्यक्ष थे और जो काम वे करवाते थे हम करते थे। इस बारे में रामपाल माजरा जी से पूछ लें वह सब भी हमसे उन्होंने ही करवाया था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूँगा कि फरीदाबाद के अन्दर 148 एकड़ जमीन पर जो कब्जा है क्या वह कब्जा जय प्रकाश ने करवाया है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके हल्के के गाँव सलोखड़ा की बात है। सलोखड़ा में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की जमीन थी उसके ऊपर भी क्या जय प्रकाश ने कब्जा करवाया? (विघ्न) मेरे कहने का मतलब है कि हमारे इन साथियों को इस बात के लिए शर्म महसूस करनी चाहिए कम से कम इन लोगों को जय प्रकाश से इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए। उस वक्त मैंने जो कुछ भी किया वह इनके नेता के इशारे पर किया था। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : अब किनके इशारे पर कर रहे हो, क्या इनके कहने पर कर रहे हो? (विघ्न)

चौधरी जय प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी बीरपाल जी मेरा समय नष्ट कर रहे हैं आप उन्हें बिठाइये। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : जय प्रकाश जी, गुड़गांव में कोई कब्जा नहीं हो सकता है। चौधरी भजन लाल जी के टाइम में भी वहां पर कब्जा करने की कोशिश की गई थी तब भी कब्जा नहीं हो पाया था। सलोखड़ा में किसी का कोई कब्जा नहीं है। आप मेरे साथ चलकर देख लें वहाँ पर कोई कब्जा नहीं है। (विघ्न) आप आ जाएं हम कल ही वहाँ पर चलते हैं। (विघ्न) यह मेरे हल्के की बात है। चौधरी भजन लाल जी के टाईम में 360 एकड़ जमीन पर कब्जा हुआ था उस समय हमने गुड़गांव जाकर वह

कब्जा तुड़वाया था। चोमा खेड़ा गांव के अन्दर गोलियां चली थीं। दो एकड़ जमीन पर असल में भी कब्जा करने की कोशिश की गई थी लेकिन वहां पर भी हम लोगों ने कब्जा नहीं होने दिया। (विघ्न) आप एक मिनट बैठें। गुड़गांव का प्रतिनिधि इतना कमजोर नहीं है कि कोई वहां पर कब्जा कर ले। (विघ्न) आप जब भी जी चाहे आ जाएं गुड़गांव में किसी का कब्जा नहीं होने देंगे। जहां तक धीरेन्द्र ब्रह्मचारी वाली जमीन की बात है, आप बता दें कि उसका मालिक कौन है। मैं, आप और कैप्टन अजय सिंह एक साथ बैठ लेते हैं। आप बताएं कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी की जमीन पर किसका कब्जा है और उसका मालिक कौन है। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने जैसे जमीन ली थी, वह जब आप मेरे साथ बैठेंगे तब आपको बताऊंगा कि गांव वालों से क्या-क्या कह कर वह जमीन ली थी।

चौधरी जय प्रकाश : जमीन किसी ने भी ली हो लेकिन इस सरकार के आदमियों ने उस पर कब्जा तो किया है। (विघ्न एवं शोर) उपाध्यक्ष महोदय, माननीय साथी जो 148 एकड़ के कब्जे की बात कह रहे हैं तो मैं इनको कहना चाहूँगा कि इनकी जानकारी अधूरी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनको यह बताना चाहूँगा कि दफा 4 के तहत 138 एकड़ भूमि की एक्वायरमैंट के लिए नोटिस दिया गया है। यह कोई कब्जा नहीं है। **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए।)**

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी, आप दो मिनट में खत्म करें। आपको बोलते हुए काफी समय हो गया है।

श्री राम कुवार सैनी : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाईंट ऑफ आर्डर है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कांग्रेस की सरकार के वक्त चौधरी भजन लाल जी के राज में ग्रीन बैल्ट की जमीन पर कब्जा किया गया था। हमारी पार्टी के लोगों ने, हमारे गाँवों के लोगों ने मिलकर वह कब्जा छुड़वाया था। इन्होंने नाथुपुर की जमीन भी खा ली थी। उस समय श्री ए०सी० चौधरी मंत्री हुआ करते थे। इसके अलावा पांच गाँवों की 14 एकड़ शामलात जमीन थी। इन्होंने भजन लाल जी के नाम से वहां पर प्रशिक्षण संस्थान बनवाना था। उसका भी हमने विरोध करके खाली करवाया था। गुड़गांव और नारनौल में 14 भूमिगत खानें ली गई थीं। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष : सैनी साहब, आप बैठ जाएं।

चौधरी जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश में गुड़गांव के अन्दर खानें हैं वहाँ पर कुछ लोगों ने मिलकर यूनियन बनाकर सरकार के ऊपर दबाव डालकर उन खानों को लिया था। आप मुझे यह बताएं कि वहाँ पर ऐसी कोई यूनियन बनाई गई है। (विघ्न)

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अगर सदन की सहमति हो तो सदन का समय आधा घन्टा और बढ़ा दिया जाए।

आवाज़ें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : सदन का समय आधा घन्टा बढ़ाया जाता है।

वर्ष 2001-2002 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री जसबीर मलौर : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। अध्यक्ष महोदय, ये जो खानों की बात कर रहे हैं इस बारे में मैं इनको बताना चाहूँगा कि यहां पर सामने खम्भे पर लिखा हुआ है कि या तो सभा में प्रवेश नहीं किया जाये अगर प्रवेश किया जाये तो सत्य ही कहा जाये। मैं आपके माध्यम से इनसे यह जानना चाहूंगा कि आज से आठ साल पहले लोगों को नौकरियां दिलवाने के लिए पैसे लिए गए थे वे वापिस किये हैं या नहीं। (विघ्न) मैं यह कहता हूं कि इन्होंने मेरे से पैसे लिए थे। (शेम शेम) चौधरी भजन लाल जी ने, अपनी पार्टी में ऐसे आदमी रखे हुए हैं जिनकी वजह से इनकी पार्टी का नाम बदनाम हो रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मेरा सभी माननीय सदस्यों से यह कहना है कि वे सदन की गरिमा को बनाए रखें।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण

चौधरी जय प्रकाश एम०एल०ए० द्वारा—

चौधरी जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन पर बोलना चाहूंगा। * * क्या बात कर रहा है * * कैसे पार्टी में आया था यह मैं बता देता हूं।

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी जिन अनपार्लियामैंटरी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वे रिकार्ड न किए जाएं।

चौधरी जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने मेरे पांव पकड़े थे तब मैंने इनको अपनी हरियाणा विकास पार्टी में शामिल किया था। इन्होंने पांच साल पहले मेरे पांव पकड़े थे तब मैंने इनको टिकट दी थी। अध्यक्ष महोदय, यह तो बिल्कुल क्लीयर है कि रिश्वत कौन लेता है, कौन नहीं लेता है। (शोर एवं व्यवधान) आज आप इसकी जांच करवा लें। आज से डेढ़ साल पहले गांव में रहता था और आज इसके पास कितनी प्रोपर्टी है इसकी भी जांच करवा ली जाए। (शोर एवं व्यवधान) अरे भले आदमी * * * * साफ करते थे। मैंने तो इससे * * साफ करवाए हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी जो भी अनपार्लियामैंटरी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको रिकार्ड न किया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

परिवहन मंत्री (श्री अशोक कुमार) : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने आन दि फ्लोर ऑफ दि हाउस कहा है कि मेरे से जय प्रकाश जी ने पैसे लिए हैं। इस बात पर सदन में चर्चा होनी चाहिए इनको बताना चाहिये और अपनी क्लैरीफिकेशन देनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) इस बात को ऐसे ही दबाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए।

चौधरी जय प्रकाश : मैं तो ऐसे ही करूंगा। स्पीकर सर, ये जैसा मुझे बोलेंगे वैसा ही मेरे से सुनेंगे।

श्री अध्यक्ष : अब जय प्रकाश जी जो भी बोल रहे हैं उसको रिकार्ड न किया जाए।

चौधरी जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, *****

श्री अशोक कुमार : अध्यक्ष महोदय, पहले इस बात का फैसला हो जाना चाहिए कि इन्होंने पैसा लिया है या नहीं।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, मेरे सम्मानित साथी ने अभी कहा है कि मैं इसी तरह से करूंगा, ठीक नहीं है। इनको सदन की जो परम्पराएं हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। ये जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं उसका भी इनको ध्यान रखना चाहिए। यह भिवानी की रैली की स्टेज नहीं है कि जो इनकी मर्जी में आये वह बोलें बल्कि यह सदन है और सदन, सदन के हिसाब से चलेगा। उनको अपने ऊपर लगे आरोप का जवाब देना होगा। हमारे एक साथी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि इन्होंने उनसे पैसे लिए हैं।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, हाउस का माहौल बहुत गरम हो गया है। इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे मर्यादा में रहकर बात करें। उनको कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिसका कोई सबूत न हो। इस तरह की बात कहना ठीक नहीं है। मैं दोनों तरफ के सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे कोई भी गलत बात न कहें। (विघ्न) मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप हाउस का माहौल ठीक रखें। अगर ऐसा नहीं होगा तो प्रदेश के लोग हमें यह कहेंगे कि किस तरह का वातावरण हाउस का है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अब सदन का समय हो गया है इसलिए मेहरबानी करके कल तक के लिए हाउस एडजर्न कर दें।

चौधरी जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने साथी से कहना चाहूंगा कि अगर उनके पास इस बारे में कोई ऐफीडेविट है तो दें या फिर थूक कर चाट लें।

श्री जसबीर मलौर : स्पीकर सर, मैं इस बारे में ऐफीडेविट दूंगा।

चौधरी जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, ******

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी जो बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाये।

श्री राम कुमार नगूरा : अध्यक्ष महोदय, मलौर साहब ने मुझ से भी कहा था कि जय प्रकाश जी ने उनसे एक लाख रुपये लिए हुए हैं। इन्होंने इस तरह से अम्बाला जिले के लोगों का एक करोड़ सात लाख रुपया देना है क्योंकि और भी कई लोगों से इन्होंने पैसे ले रखे हैं। 1900 रुपये इन्होंने मेरे से भी पहले लिए थे।

चौधरी जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, ***** (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बजट पर बोलिए। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, ये मेरे पास 1995 में टिकट लेने आये थे। *****

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जो कुछ कह रहे हैं उसे रिकार्ड न किया जाये।

श्री भागी राम : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाईंट ऑफ आर्डर है। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही सीरियस मैटर है। एक माननीय विधायक जिसे एक लाख जनता ने वोट डालकर चुना है और जब विधान सभा चल रही है, विधानसभा के चलते उन्होंने यह आरोप लगाया है और कहा है कि जय प्रकाश मेरे से एक लाख रुपया खा गया। दूसरा विधायक गवाही दे रहा है यह बड़ा ही सीरियस मामला है, मजाक की बात नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

*** चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप बैठ जाएं। भजन लाल जी, आप इनको कहें कि ये बैठ जाएं। कोई बात कहनी है तो आप चेयर से टाइम लें।

चौधरी जय प्रकाश : मैंने अगर पैसा लिया था तो मैं उस समय लोकदल में था और लोकदल के अध्यक्ष को दे दिया अब उनसे हिसाब करें।

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, कन्फैशन हो गई है आप बात समाप्त करें और आगे की कार्यवाही शुरू करें।

चौधरी जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, चुनाव के पहले हरियाणा प्रदेश की सरकार ने हिसार में पुलिस सम्मेलन बुलाया था और उसमें संपत सिंह जी ने बड़े बलंगबांग दावे किए थे। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उस सम्मेलन में पुलिस कर्मचारियों की जो मांगें मानी गई थीं, जो अनाउसमैंट हुई थी, क्या वह सारी मान ली हैं? इन्होंने 16 वर्ष के बाद पुलिस के सिपाही को हवलदार बनाने की घोषणा कर दी और 32 वर्ष के बाद ए०एस०आई० बनाने की घोषणा की है। मैं इस बारे में ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 32 वर्ष के बाद तो 57 की आयु में उसकी रिटायरमैंट हो जाएगी तो फिर प्रमोशन कैसे होगी?

श्री अध्यक्ष : पुलिस की भर्ती की आयु सीमा 18 से 25 है।

चौधरी जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा की सरकार ने कुछ दिन पहले पंचकूला में पुलिस जनता सम्मेलन में डी०एस०पीज़० के लिए वर्दी भत्ता बढ़ाकर 4 हजार रुपये कर दिया। यह पुलिस के अफसरों को खुश करने के लिए किया गया है ताकि पुलिस से विपक्ष के लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवा सकें। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी, आप बैठ जाएं। अब बजट पर श्री शादी लाल बतरा बोलेंगे।

श्री शादी लाल बतरा : अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम कल के लिये है।

चौधरी जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मुझे दो मिनट का समय और दे दें।

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी, आप पौन घंटा बोल चुके हैं, अब आप बैठ जाएं। बतरा जी, कल वित्त मंत्री जी ने जवाब देना है, आपका नाम आज के लिए दे रखा है, आप अपने लीडर से पूछ लें। अगर आप बोलना चाहते हैं तो बोलें नहीं तो अनीता यादव बोलेंगी। (विघ्न) जय प्रकाश जी, आपका समय समाप्त हो गया है, आप बैठिए। अब श्रीमती अनिता यादव जी बोलेंगी।

चौधरी जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी, आप बैठिए। आपकी पार्टी को स्ट्रैंथ के हिसाब से काफी समय दिया गया है। अब आपको इससे आगे एक मिनट का भी समय नहीं दिया जाएगा।

चौधरी जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, बोलने का मेरा हक है इसलिए मुझे थोड़ा समय और दिया जाये। ******

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : आपकी प्रार्थना को अस्वीकार किया जाता है। आप बैठिये। जय प्रकाश जी जो बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए।

चौधरी जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, * * * * * * *

श्री अध्यक्ष : अनिता जी, आप बोलिये। अगर नहीं बोलना है तो किसी और सदस्य को बोलने के लिए समय दिया जाएगा। (विघ्न) जय प्रकाश जी, आप बैठ जाइये।

श्रीमती अनीता यादव : अध्यक्ष महोदय, आप जय प्रकाश जी को तो बैठाइये।

चौधरी जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मैं तो इसलिए बोलने के लिए कह रहा था कि माननीय वित्त मंत्री महोदय यह न कह दें कि कांग्रेस पार्टी में कोई बोलने वाला नहीं है। मैं तो बैठ जाता हूं। आपने मुझे समय दिया इसके लिये आपका धन्यवाद।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आपके पास जो विपक्ष के नेता ने नाम दिए हैं उन सदस्यों को आप बोलने का मौका आज अवश्य दें, चाहे हाउस का समय और क्यों न बढ़ाना पड़े।

श्री पूर्ण सिंह डाबड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ़ आर्डर है। आनरेबल मैम्बर ने फरमाया कि मुझे एक लाख लोगों ने यहां चुनकर भेजा है। उन एक लाख लोगों ने हिंदुस्तान के संविधान के तहत इनको चुनकर यहां भेजा है। संविधान के तहत ही इनको सोचना पड़ेगा। ये सदन में बैठे या पार्लियामैंट में बैठें, इनको संविधान को सामने रखकर ही यहां बैठना पड़ेगा। (शोर एवं व्यवधान)

वर्ष 2001-2002 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्रीमती अनिता यादव (साल्हावास) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि प्रो० सम्पत सिंह जी ने जो यह बजट पेश किया है इसमें पूरे हरियाणा प्रान्त में किसी के लिये भी कोई नई योजना नहीं रखी गई है। यह हितैषी बजट नहीं है। इस बजट में किसी भी वर्ग के लिए, किसी भी क्षेत्र के लिए कोई भलाई का काम नहीं किया गया। इस बजट से जनता को कोई सैटिसफैक्शन नहीं मिली। मेरी तरफ से तो यह बजट का एक पुलिंदा है, असल का पुलिंदा है। इस बजट में लोगों को गुमराह किया गया है। अध्यक्ष महोदय, इस सम्मानित सदन के साथियों ने आज सुबह से बड़ी चर्चा की है कि हरियाणा सरकार ने गुजरात त्रासदी में यह किया, वह किया। हालांकि दिए हुए दान को कभी गाते नहीं हैं। हमारे यहां एक कहावत है—'चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर, दान दिए धन न घटे कह गए सन्त कबीर।' बजुर्गों की इस बात को हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। सदन के साथियों ने गुजरात त्रासदी में दी हुई सहायता राशि पर जितने पुलिन्दे बांधे हैं, मैं समझती हूं कि यह चुनाव का दौर नहीं था कि कारगिल मुद्दे की तरह कैश कर लिया जाए। कारगिल में आज तक जितने सैनिक शहीद हुए हैं उसके लिए सारी स्टेटस की सरकारें और सैन्टर की सरकार पूरी-पूरी जिम्मेवार है क्योंकि हमारी हरियाणा सरकार कहती है कि हमने शहीदों के नाम पर 10-10 लाख रुपये दिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहती हूं कि सरकार अपनी तरफ से 2 लाख रुपये देती है और जो बाकी 8 लाख रुपया दिया जाता है वह मुख्य मंत्री युद्ध वीर कोष में से दिया जाता है। जो कि लोगों का पैसा होता है। इसके लिए हरियाणा सरकार क्रैडिट उठाना चाहती है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से गुजरात त्रासदी का बार-बार जिक्र किया जा

[श्रीमती अनिता यादव]

रहा है। इसमें सभी वर्गों, सभी व्यापारियों और सभी पोलिटिकल पार्टियों ने अपनी तरफ से दान दिया। बार-2 जिक्र करने से कि दान दिया तो उस दान का फल खत्म हो जाता है। इसलिए जो दान दे दिया उसका ज्यादा जिक्र नहीं करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि गुड़गांव में जो बिल्डिंग डैमेज हुई है उसको या तो ठीक करवाया जाए या इसको दोबारा बनाकर लोगों के विश्वास को बनाया जाये। मेरे एक भाई ज्यादा बोल रहे थे कि शहरों का नवीनीकरण और सुन्दरीकरण किया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि झज्जर में अगर शहीद भगत सिंह का स्मारक है और नेता जी सुभाष चन्द्र का स्टेच्यु है, उनको किसी अधिकारी द्वारा दिखवाएं कि उनकी हाईट कितनी है ? उसके सुन्दरीकरण में भी अधिकारियों ने पैसा खाया है। इस बात का सरकार पता करवा सकती है। सरकार इस साल हर मोर्चे पर विफल हुई है। चाहे वह युवा वर्ग हो, किसान वर्ग हो, छात्र वर्ग हो, बिजली पानी की बात हो, सड़कों की बात हो, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो या महिलाओं के साथ घटित घटनाओं की बात हो। महिला दिवस पर मुख्य मंत्री महोदय बोल रहे थे मैं उनको कहना चाहूंगी कि महिलाओं के साथ जो छेड़छाड़ होती रहती है। उसको रोकने का उपाय करना होगा ही। पिछली सरकारें इस पर काबू नहीं कर पाई लेकिन यह सरकार तो कुछ करके दिखाए। 11-11 साल के बच्चों को कोई उठाकर ले जाता है, इसकी रोकथाम करना भी सरकार का फर्ज बनता है। व्यापारियों के लिये फार्म 38 लागू करके व्यापारियों को उलझन में डाल दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, 2001-2002 की वार्षिक योजना में जो 2530 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। इसमें से 1815 करोड़ रुपये जो व्यय किया गया है, और 715 करोड़ रुपये का जो घाटा है वह सरकार कहां से पूरा करेगी, यह मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदय, आज बिजली की हालत बहुत खस्ता हो गई है। किसानों के साथ-साथ छात्र वर्ग भी बिजली की इस स्थिति से पूरी तरह प्रभावित हुआ है। आज परीक्षाएं चल रही हैं लेकिन किसी भी गांव में जाकर सर्वे करवा कर देखें कि लाइट पूरी नहीं होती। सभी स्टूडैंट्स तो क्या घर की महिलाएं भी लाइट का इंतजार करती है कि जब लाइट आएगी तो खाना बनाएंगे। इस तरह से देहात में लाईट की बहुत बुरी हालत है। बजट में कहा गया है कि ट्रांसमीशन सिस्टम में अपग्रेडेशन स्कीम के तहत 475 करोड़ रुपये लगाए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहती हूं कि हरियाणा में कितनी किलोमीटर तक पुरानी तारें अब तक बदली जा चुकी हैं और आने वाले समय में कितने किलोमीटर तक और तारों को बदला जायेगा।

इसी तरह सड़कों के बारे में भी बार-बार जिक्र किया गया है। मुख्य मंत्री महोदय ने भी राव धर्मपाल जी के माध्यम से यह बताने की कोशिश की है कि गुड़गांव के अन्दर कितनी सड़कें बनी हैं, इसलिए मैं भी जानना चाहती हूं कि मेरे हल्के सालहावास में कितनी सड़कें बनी हैं और आने वाले समय में कितनी सड़कें बनाई जायेंगी। पूरे हरियाणा प्रदेश में सड़कें बनाने के लिये 511.83 करोड़ रुपये बजट में रखे हैं। इस बारे में कहना चाहूंगी कि यह पैसा सड़कें बनाने के लिए बहुत कम है क्योंकि इतने पैसे में से हमारे क्षेत्र को हिस्सा नहीं मिलेगा और हमारी तरफ की सड़कें नहीं बनेंगी। इसलिए यह पैसा बढ़ाया जाए। मेरे हल्के के अन्दर सड़कों की हालत बहुत खराब है, उनमें बड़े-बड़े गड्डे पड़े हुए हैं। गाड़ी दूसरे गेयर से तीसरे गेयर में नहीं चला सकते। जो गड्डे हमारी तरफ भरे हैं उनमें अभी तक तारकोल नहीं डाला गया है इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि जहां पर गड्डे भर दिये गये हैं उनमें जल्दी ही तारकोल डाला जाये और जो सड़कें टूटी हुई हैं उनको जल्दी से जल्दी

बनवाया जाये। इसके अतिरिक्त परिवहन के बारे में कहा गया है कि 1100 पुरानी बसों को बदला जा रहा है। इस बारे में मैं परिवहन मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि जो बसें पुरानी बदली जायेंगी, उन पुरानी बसों को मेरे हल्के सालहावास में चला दिया जाये क्योंकि वहां पर लड़कियां जीपों की छत पर बैठकर स्कूल या कालेज जाती हैं और इन जीपों का तकरीबन हर रोज एक्सीडेंट हो जाता है जिसके कारण लड़कियों के हाथ या पांव कई बार टूट जाते हैं। इसलिए मैं मुख्य मंत्री जी से भी गुजारिश करूंगी कि पुरानी बसों को मेरे यहां चलाया जाये ताकि लड़कियां, जो दो घरों को बसाती हैं, उनको दिक्कत न हो।

श्री अध्यक्ष : अनिता जी, प्लीज आप जल्दी समाप्त करें। आपका बोलने का टाइम समाप्त हो गया है।

श्रीमती अनिता यादव : अध्यक्ष महोदय, पब्लिक हैल्थ के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि महिलाओं के साथ जो शोषण हो रहा है वह बहुत निंदनीय है। मैं भी एक महिला हूं, इसलिये मैं महिलाओं की परेशानियां जानती हूं। यह मेरा दायित्व है कि मैं उनको सदन में रखूं। अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां कई गांव तो ऐसे हैं यदि वहां पीने का पानी लेने के लिए महिलाएं सुबह 4 बजे ट्यूबवैल पर चली जायें तो हो सकता है उसे एक या दो बाल्टी पानी मिल जाये। यदि महिलाएं 5 या 6 बजे पानी लेने जाती हैं तो उन्हें आधा कीचड़ वाला पानी मिलता है और वह पानी भी उन्हें मजबूरी में लाना पड़ता है। गांव की औरतें मुझे कहती हैं कि बहन जी आप तो कहती थीं कि आप पीने का पानी हमें दिलवाएंगी और नलका लगवाएंगी, अब यह क्या हो रहा है?

श्री अध्यक्ष : अनिता जी, क्या आप उन गांवों के नाम बता सकती हैं जहां पर पानी के साथ औरतों को मजबूर होकर कीचड़ वाला पानी लाना पड़ता है और पीना पड़ता है?

श्रीमती अनिता यादव : अध्यक्ष महोदय, नंदगांव, झाड़ली, बिरोहड़, खेड़ा थू और झामरी ऐसे ही गांव हैं। मातनहेल और कोसली मण्डी में तो मुख्य मंत्री जी भी अपने सर्वे के दौरान देख कर आये हैं कि दो रुपये या तीन रुपये का एक घड़ा पानी मिलता है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं कृषि की बात पर आती हूं। यहां पर बार-बार सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने सत्ता में रहकर कुछ नहीं किया और बार-बार जनता को गुमराह कर रहे थे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहूंगी कि राज्य में 75 प्रतिशत लोग खेती पर निर्वाह करते हैं। कांग्रेस सरकार के समय में ही उद्योगों को कृषि का दर्जा दिया गया था। किसानों को फसलों का समर्थन मूल्य कभी कम नहीं होने दिया और न ही कृषि पर सब्सिडी कम होने दी । आज प्रदेश की क्या हालत है वह भी जनता को पता है और जनता सरकार की कारगुजारियों से भी परिचित है। 1991 से 1996 तक कांग्रेस सरकार के समय में जब फ्लड के दौरान किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थीं तो उन सभी किसानों को पांच हजार से दस हजार रुपये तक की राशि मुआवजे के रूप में दी गई थी। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, आज मेरे क्षेत्र के लगभग सभी गांव सूखे की चपेट में आ गये हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : मैडम अनिता जी, आपका एक मिनट बाकी है। (शोर)

श्रीमती अनिता यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जो गांव सूखे की चपेट में आ गये हैं वहां के किसानों को मुआवजा दिया जाये।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, यदि सदन की सहमति हो तो हाउस का समय आधे घंटे के लिए बढ़ा दिया जाये।

आवाजें : ठीक है, जी।

श्री अध्यक्ष : सदन का समय आधा घंटा बढ़ाया जाता है।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, ऐसे नहीं हो सकता। आप हमेशा ऐसा करते हैं। (शोर) मेहरबानी करके आप आज हाउस का समय न बढ़ायें। और कल तक के लिये एडजर्न कर दें। (शोर)

श्री रामबीर सिंह : सर, मेरा एक प्वाइंट ऑफ आर्डर है। (शोर)

श्री अध्यक्ष : कांग्रेस के जो सदस्य खड़े हैं वे सब बैठ जायें। मैडम अनिता यादव जी, आप भी एक मिनट बैठिये। रामबीर जी, आप बोलिये। आपका क्या प्वाइंट ऑफ आर्डर है।

वर्ष 2001-2002 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री रामबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, बहन अनिता जो कृषि उपज की बात कर रही थीं, मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के राज में 1981 में गेहूं का 104/- रुपये या 105/-रुपये भाव था। उस वक्त भजन लाल जी ही मुख्य मंत्री थे। मैं उस समय मार्किट कमेटी, नारनौल में लगा हुआ था। उस टाइम सारे सीजन में मंडी में केवल मात्र 11 बोरियों की अराईवल थी। किसानों ने रोष में आकर मंडियों का बहिष्कार किया था। आज ये किसानों को उनकी कृषि उपज का उचित भाव दिए जाने की कैसे बात कर रहे हैं?

श्रीमती अनिता यादव : अध्यक्ष महोदय, अब मैं ट्यूबवैलों के कनैक्शन देने की बात कहना चाहती हूं। श्री रामपाल माजरा जी भी यहां पर बैठे हुये हैं। कई साथी तत्काल योजना लागू करने की बात कर रहे थे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन में उदाहरण देकर बताना चाहती हूं कि लोगों को ट्यूबवैल के कनैक्शन नहीं मिले हैं। धकौरा गांव का रामचन्द्र है जिसने 20 हजार रुपये भर दिये हैं फिर भी उसे तत्काल योजना के तहत ट्यूबवैल कनैक्शन नहीं मिला है। इसी तरह से जुडी गांव के सूबे सिंह हैं, जिन्होंने 20 हजार रुपये भर रखे हैं लेकिन आज तक उसको ट्यूबवैल का कनैक्शन नहीं दिया गया। जखाला गांव का राजकुमार है जिसने पच्चीस-तीस हजार रुपये भर रखे हैं लेकिन उसे ट्यूबवैल का कनैक्शन नहीं दिया गया है। इसलिये मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जिन किसानों ने ट्यूबवैल कनैक्शन के लिये पैसे भर रखे हैं उन्हें ट्यूबवैल के कनैक्शन जल्दी दिये जायें।

श्री अध्यक्ष : मैडम, वाइंड अप करें।

श्रीमती अनिता यादव : अध्यक्ष महोदय, खेलों की बात है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अंधा बांटे बाकली घर-घर को को दे वाला उसूल अपना रखा है। गांव बिरड़ का रमेश यादव जोकि खो-खो में वर्ल्ड कप जीत कर आया है, उसको सरकार ने कोई सम्मान नहीं दिया। इसी तरह से संतोष यादव जी कि माउंट एवरैस्ट पर दो बार चढ़ चुकी है उसको भी कोई सम्मान नहीं दिया गया। कोहारा गांव का एक लड़का क्रिकेट में खेलना चाहता था उसको भी क्रिकेट में खेलने का चांस नहीं दिया गया। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : मैडम अब आप बैठिये। आपका समय समाप्त हो चुका है। अब शादी लाल बतरा जी, आप बोलिये। (शोर) शादी लाल जी, कल बोलने का समय नहीं मिल पाएगा। (शोर) आप आज बोल लीजिये। (शोर) चौधरी भजन लाल की सल्तनत के ये आखिरी बादशाह हैं।

श्री शादी लाल बतरा (रोहतक) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया उसके लिये आपका बहुत धन्यवाद। हमारे वित्त मंत्री जी ने जो कर मुक्त बजट सदन में पेश किया है उसमें दो प्रकार की बातें हो सकती हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि कर मुक्त का मतलब है आगामी वर्ष के लिये या तो सरकार के पास कोई योजनायें नहीं या उनकी रेवेन्यू रीसीट उम्मीद कर रहे हैं कि ज्यादा हो जाएगी जिससे बजट में कोई कर नहीं लगाना पड़ेगा। पिछले साल भी करमुक्त बजट पेश किया गया था। हमने उसको सुना था, उसको देखा था और हमने उस समय यह सोचा था कि सरकार बहुत कर्मशील है, लोगों की बड़ी हितैषी है कि एक करमुक्त बजट पेश कर दिया लेकिन हम घर पहुंचे भी नहीं थे कि टैक्सों की भरमार शुरू हो गई। इस बात को देखते हुये हमारी समझ में यह आया है कि सरकार की करनी और कथनी में बहुत फर्क है। इसके खाने के दांत और हैं और दिखाने के और हैं। अध्यक्ष महोदय, पिछले साल का करमुक्त बजट पेश करने के बाद इस सरकार ने लोगों पर कर लगा दिये जिसके कारण हरियाणा की जनता में त्राहि-त्राहि मची हुई है। अध्यक्ष महोदय, जब पिछले साल करमुक्त बजट पेश हुआ था तो उस बजट में 165 करोड़ रुपये का घाटा था। लेकिन जब पिछला साल खत्म हुआ तो वह बढ़कर 233 करोड़ रुपये का घाटा हो गया। अध्यक्ष महोदय, इस साल के जो बजट एस्टिमेट्स आये हैं उनके बारे में सरकार कहती है कि 288.79 करोड़ रुपये का घाटा होगा इसका मतलब हुआ कि सरकार टैक्स लगाएगी। अगर सरकार ने टैक्स लगाने हैं तो वह चुने हुये विधायकों के सामने लगाये ताकि माननीय सदस्य उनके बारे में अपने विचार रख सकें और उसकी आलोचना कर सकें। मैं कहता हूं या तो यह सरकार आलोचना से डरती है कि सरकार की कोई आलोचना न हो या यह सरकार चाहती है कि विधान सभा का सत्र खत्म हो जाएगा उसके बाद संविधान की धाराओं का उल्लंघन करते हुये पिछले दरवाजे से टैक्स लगा देंगे। इस साल में भी वैसे ही टैक्स लगाए जाएंगे जैसे पिछले साल बजट पेश होने के बाद लगाए गए थे। यह प्रजातंत्र के हित की बात नहीं है। अगर आपने कोई टैक्स लगाना है तो वह यहां सैशन में लगाएं ताकि उसके बारे में हर माननीय सदस्य को अपनी बात कहने का मौका मिले कि यह गलत है। अगर सरकार ने कोई टैक्स नहीं लगाया तो प्रदेश में विकास की पोजीशन क्या होगी? इसी तरह से बिजली के रेट्स काफी बढ़ गये हैं। आने वाले समय में यह सरकार बिजली के लिये क्या करेगी व लोगों को बिजली की सुविधा देने के लिए क्या करेगी इस बारे में भी सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं है। आज बिजली लोगों के लिए क्वालिटी आफ लाईफ बन गई है। अगर आप यह कहें कि तेल का दीया जलाकर पढ़ लो तो अब वह बात बनेगी नहीं क्योंकि पहले का युग कुछ और था और आज का युग कुछ और है। बिजली के उत्पादन के लिये कोई प्रावधान इस बजट में नहीं किया कि इस योजना पर कितना पैसा खर्च होगा और वह कहां से मिट आऊट करेंगे। आज पापुलेशन बढ़ रही है पिछली बार 1981 से 1991 के दौरान जो पापुलेशन की काऊंटिंग हुई थी उस वक्त 27 परसैंट पापुलेशन बढ़ी थी। अब जो जनगणना हुई है उसकी सही फिगर्ज नहीं आई हैं लेकिन उम्मीद है कि हमारे प्रदेश की जनसंख्या 2 करोड़ से ऊपर चली जाएगी। आज बिजली की खपत दो तरीके से हो रही है। एक तरफ तो हमारी आबादी बढ़ रही है और दूसरी तरफ कुछ लोग यह चाहते हैं कि हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश होने से हमारे यहां उतनी आमदनी नहीं रही इसलिये यहां पर उद्योग लगाये जाने की बात करने लग गये हैं। उद्योग लगाने के लिये भी बिजली चाहिये। जब बिजली का उत्पादन नहीं होगा तो फिर प्रदेश को बिजली कहां से मिलेगी? जब प्रदेश का विकास नहीं होगा तो पिछड़ापन आयेगा ही जिस कारण हम पिछड़ जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, यह जो बजट पेश हुआ है यह हरियाणा प्रदेश के हित में नहीं है, क्योंकि इसमें वित्त मंत्री जी ने राजस्व बढ़ाने की कोई स्कीम

19.00 बजे

[श्री शादी लाल बतरा]

नहीं बताई जिससे यह पता चले कि हमारा राजस्व कैसे बढ़ सकता है? जब राजस्व ही नहीं बढ़ेगा तो फिर हमारे विकास की प्रगति भी वही रहेगी जो पहले चल रही है।

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : बतरा जी, आप सुझाव दें कि राजस्व कहां से आ सकता है?

श्री शादी लाल बतरा : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुनिये। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, जो बजट बना है, जो राजस्व आएगा वह कहां कहां जायेगा उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। एक रुपये में से 21.59 पैसे तो लोन की रीपेमैंट पर खर्च हो जायेंगे और 13.82 पैसे उसके सूद की रीपेमैंट पर खर्च हो जायेंगे। अगर इन दोनों को जोड़कर देखा जाये तो यह फिगर 35 पैसे बैठ जाती है। अगर यह 35 पैसे बनता है तो मैं जानना चाहता हूं कि इसको ये मीट आऊट कैसे करेंगे? इसको ये मीट आऊट करेंगे पब्लिक डैट से। पब्लिक डैट में आप देखें तो 35.28 प्रतिशत आंकड़े आते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो पिछला कर्जा हमने देना था और उसका जो सूद देना है उसके लिये और कर्जा बढ़ा देंगे। और कर्जा बढ़ाने से यह फिगर 2002 तक 16445 करोड़ रुपये हो जायेगी। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार गई तो उस वक्त यह फिगर्ज 1996 में 6212 करोड़ रुपये थी जो अब पांच सालों में बढ़ कर 16445 करोड़ रुपये हो जायेगी। इस प्रकार आप देखेंगे की पांच सालों में यह तकरीबन 10 हजार करोड़ रुपये की फिगर्ज बढ़ गई है। इसलिये मैं समझता हूं कि हरियाणा सरकार की जो पालिसी है वह हरियाणा के लोगों के हित में नहीं है। अगर इसी प्रकार से यह सरकार सूद और रीपेमैंट को लोन लेकर करती है तो फिर सरकार कब तक चलेगी और हरियाणा के लोगों का क्या होगा? सरकार जो कर्जा लेगी वह सारे हरियाणा प्रदेश के वासियों पर लेगी। अगर सरकार इसी प्रकार से काम करेगी तो फिर इसकी कल्पना नहीं की जा सकती कि प्रदेश का क्या होगा। हमें इस पर गहराई से सोचना होगा। आदरणीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि आप कोई सुझाव दें। वित्त मंत्री जी जिस ढंग से आप सुझाव देने की बात कर रहे हैं उस ढंग से सुझाव नहीं दिए जा सकते क्योंकि जब तक सारे रिसोर्सिज नहीं देखे जाते तब तक सुझाव नहीं दिए जा सकते। आपने जो टैक्स लगाए हैं मैं उन टैक्सों से एग्री नहीं करता। आपने हाउस टैक्स लगाया। पहले हाउस टैक्स रैन्टल वैल्यू पर लगता था कि फलां मकान से कितना किराया आ सकता है। उस किराये पर टैक्स लगता था। अब सरकार ने टैक्स उस मकान की मार्किट वैल्यू पर लगा दिया। आज प्राईस इन्डैक्स बढ़ रहा है। पहले की अपेक्षा जमीनों की कीमतें बढ़ रही हैं। जो जमीन आज से 30 साल पहले 50 रुपये गज या 100 रुपये गज थी आज वह 50 हजार रुपये गज हो चुकी है। अब चूंकि रैन्टल वैल्यू पर तो आप टैक्स लगाएंगे नहीं। उस जगह पर मकान बनाते हैं तो उसकी रैन्टल वैल्यू तो वही रहेगी लेकिन मार्किट वैल्यू बढ़ जाएगी और सरकार मार्किट वैल्यू पर टैक्स लगाएगी जो ठीक नहीं है। मैं आपको एक ऐसा उदाहरण रोहतक शहर गांधी कैम्पस का दे सकता हूं कि जहां पहले 5 हजार रुपये जिस कोठी की कीमत थी आज उसकी कीमत 2 लाख रुपये हो गई। उन लोगों के पास कमाने का कोई साधन नहीं है। वे लोग रिक्शा चलाकर अपना पेट पालते हैं लेकिन अब टैक्स 2 लाख रुपये पर लगेगा जिससे उनको काफी दिक्कत आएगी जबकि पहले रैंटल वैल्यू के हिसाब से उसका टैक्स 10 या 20 रुपये बनता था जो अब बढ़कर सैकड़ों में चला जाएगा। अब गरीब आदमी कहां से इतना पैसा दे पाएगा। इसलिए जो टैक्स लगाए हैं वे हरियाणा की जनता को देख करके नहीं लगाए गए हैं और न ही यहां के लोगों की आमदनी को देखकर टैक्स लगाए गए। इसलिए आपने जो टैक्स लगाए हैं मैं उससे सहमत नहीं हूं। इसी प्रकार से बिजली के जो रेटस बढ़ाये गये हैं वे भी अंधाधुंध बढ़ा दिये गये। स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, रोड्ज के लिए पैसा चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से नई भर्ती पर रोक लगी हुई है। यदि किसी स्कूल या कॉलेज में कोई अध्यापक या लैक्चरार लगा हुआ है और उसकी यदि बदली हो जाए या उसकी डैथ हो जाए या वह रिजाईन कर जाए तो उसकी जगह पर दूसरा अध्यापक कोई नहीं आता। यदि उस कालेज की या स्कूल की अपग्रेडेशन हो जाती है और वहां पर दो व्यक्तियों की आवश्यकता है तो वह पूरी नहीं हो पाती। वहां पर मैडीकल कॉलेज में या दूसरे महकमों में काफी पोस्टें खाली पड़ी हैं। मैंने इन खाली पड़ी पोस्टों के बारे में एक सवाल भी किया था। वह आज लगा हुआ भी था लेकिन उसका उत्तर मेरे पास नहीं आया। अध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रश्न भी पूछा कि मैडीकल कॉलेज में कितनी सैंक्शंड पोस्टस हैं और कितनी वैकेंसीज हैं और कितने डाक्टर्ज लगे हुए हैं। जो पोस्टें खाली पड़ी हैं वे कब से पड़ी हैं और अगर उन पर नियुक्तियां नहीं हुई हैं तो क्यों नहीं हुई है। इस प्रश्न का जवाब मुझे सरकार ने आज नहीं दिया क्यों नहीं दिया यह मैं नहीं कह सकता (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : बतरा साहब अब आप वाइंड अप करें।

श्री शादी लाल बतरा : अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि इस प्रकार से बात बनती नहीं है। मैं तो पहली बार चुनकर आया हूं और मैं बोलना भी चाहता हूं मुझे आपसे उम्मीद है कि आप मुझे सहयोग देंगे और मुझे बोलने के लिए समय भी देंगे ताकि मैं अपनी बात कह सकूं।

श्री अध्यक्ष : आप गवर्नर एड्रैस पर भी बोले थे।

श्री शादी लाल बतरा : अध्यक्ष महोदय, मैं बोला ज़रूर था लेकिन मुझे सीखना भी तो है (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं तो बजट के प्रावधानों की बात ही कर रहा हूं। मैं नियुक्तियों की बात कर रहा था, मेरा कहना यह है कि डाक्टर्ज की जो पोस्टें खाली पड़ी हैं और सैंक्शंड पोस्टें हैं उन पर डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं हुई है जिसके कारण उन लोगों का नुकसान हो रहा है जिनको यह विश्वास था कि वह हमारा ही मैडीकल कॉलेज है और इलाज के लिए वहां पर जाएंगे तो हमें अच्छा ट्रीटमैंट मिलेगा। आज वहां से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। वहां पर जो ट्रीटमैंट मिलता है वह या तो वी०आई०पीज० को मिलता है या फिर उस गरीब आदमी को मिलता है जिसका कोई सहारा नहीं है। जो मिडल आर्डर आदमी है उसको वहां पर कोई नहीं पूछता और वह सोचता है कि प्राइवेट डाक्टर के पास जाकर ट्रीटमैंट करवा लें और इस ट्रीटमैंट के लिए वह किसी न किसी प्रकार पैसे का भी प्रबन्ध करता है क्योंकि जान सबको प्यारी है। अध्यक्ष महोदय, सरकार यह आज्ञा दे दे कि जो डाक्टरों की पोस्टें खाली पड़ी हैं उन पर नियुक्ति कर दी जाएं चाहे इसके लिए बजट में थोड़ा और प्रावधान करने की जरूरत है तो वह कर लिया जाए। (विघ्न) इसी प्रकार से यूनिवर्सिटी की बात है। अध्यक्ष जी, यूनिवर्सिटी में जो सैंक्शंड पोस्टें हैं वे खाली पड़ी हुई हैं और पिछले तीन सालों से कोई अप्वायटमैंट नहीं हो रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे विद्यार्थियों का कितना नुक्सान हो रहा है। विद्यार्थियों का नुकसान हो और लोगों के स्वास्थ्य का नुकसान हो रहा है और इस बारे में सरकार सोचे नहीं तो स्थिति और भी ज्यादा गम्भीर हो जाती है जिसके लिए सारे लोगों का चिन्तित होना स्वाभाविक है। हम लोग तो सरकार से प्रार्थना ही कर सकते हैं और अनुरोध कर सकते हैं कि आप ऐसा न करें। आप लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल करिये, आप विद्यार्थियों का ख्याल करिये और जो नियुक्तियां होनी चाहिए थीं वे जल्दी से जल्दी होनी चाहिएं। नई नियुक्तियों पर सरकार ने बैन लगा रखा है वह बैन हटना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इन सब बातों का सम्बन्ध बजट से होता है इसलिए इनका प्रावधान बजट में होना चाहिए था। यह प्रावधान होने के बाद ही कुछ हो सकता है। जैसे कि परसों भी मेरा एक प्रश्न आया था जिसमें सरकार ने रोहतक में 68 कॉलोनियों को अनएथोराईज्ड

[श्री शादी लाल बतरा]

डिक्लेयर किया था। सरकार ने जो जवाब दिया था उसमें सरकार ने यह माना था कि वहां पर सीवरेज की स्कीम नहीं है वाटर सप्लाई की लाईन नहीं है। (विघ्न) सरकार ने इस बात को माना था कि 10 कॉलोनीज में वाटर सप्लाई नहीं है और 20 कॉलोनीज में सीवरेज लाईन नहीं है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि रोहतक जैसे शहर में जो कि बहुत पुराना शहर है जिसकी यह चर्चा थी कि रोहतक एक बढ़िया सिटी है लेकिन यह शहर आज गांव से भी बदतर हो गया है। आज यह मूल सुविधाओं से भी वंचित हो गया है। वहां के लोग पीने के पानी के लिए कहां जाएं। गांवों में तो लोग कुओं से पानी ले आते हैं लेकिन वहां तो कुआं भी नहीं है। (विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं बतरा साहब से यह कहना चाहूंगा कि ये बहुत ही सीनियर, सयाने और पुराने आदमी हैं। मैं इनसे यह कहना चाहूंगा कि ये सुझाव भी दें कि रैवेन्यू को कैसे बढ़ाया जाये? ये कह रहे हैं कि यह टैक्स ठीक नहीं, यह टैक्स ठीक नहीं, ये कोई ठोस सुझाव दें कि रैवेन्यू को इस प्रकार बढ़ाया जा सकता है।

श्री शादी लाल बतरा : अध्यक्ष महोदय, कोई भी व्यक्ति सारी चीजें देखे बिना कोई सुझाव नहीं दे सकता है। पिछला रिकार्ड मेरे पास नहीं है मैं ऑफ हैंड क्या कहूं। मैं विधान सभा में पहली बार चुनकर आया हूं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात समझ सकता हूं कि जो टैक्स लगे हैं वे कितने गलत हैं इनके कारण लोगों में आतंक है और लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। अगर वे लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं तो उनकी तकलीफ को यहां पर उठाना हमारा काम है, लोगों के आंसू पोंछना हमारा काम है, उनकी बात सुनना और उनकी दिक्कतों को सरकार के सामने रखना हमारा काम है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि वे टैक्स ठीक नही हैं। मेरे एक साथी ने कहा कि यह सरकार उपयोगी है, ठीक है, यह सरकार उद्योगी है, यह भी ठीक है लेकिन इसके साथ ही साथ सरकार में पारदर्शिता भी होनी चाहिए। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार में पारदर्शिता नहीं है। यह मैं क्यों कह रहा हूं क्योंकि जब भी कोई टैक्स लगाना होता है, राजस्व लगाना होता है तो सरकार यह अपने आप लगा लेती है उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता होता है। कोई टैक्स लगाना होता है, राजस्व लगाना होता है वह सदन में लगे ताकि हम लोगों को बता सकें कि यह टैक्स क्यों लगा है और इस टैक्स के लगने से क्या-क्या फायदे हैं? अगर ऐसा होगा तो हम लोगों को सैटीसफाई कर सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

MR. SPEAKER : Now, the House stands *adjourned till 9.30 A.M. tomorrow, the 14th March, 2001.

*19.17 hrs. (The Sabha then *adjourned till 9.30 A.M. on Wednesday, the 14th March, 2001.)

33269—H.V.S.—H.G.P., Chd.